

राजस्थान टुडे



जयपुर
सुनील कोठारी



जोधपुर
प्रसन्नचंद मेहता



अजमेर
अनामिका शर्मा



पाली
नमिता बुबकिया



अलवर
सुमनलता अग्रवाल



उदयपुर
पारस सिंघवी



भरतपुर
अनुराधा सिंह



कोटा
अनुसूया गोस्वामी



भीलवाड़ा
जसवंत कंवर



बीकानेर
अनिल कल्ला





AYUSHI
BUILDCON PVT. LTD.



AYUSHI
BUILDERS & DEVELOPERS



221-222, Shyam Nagar, Pal Link Road, Jodhpur - 342 003 (Raj.)
Tel. : 0291-2710071 Mobile : 94141 27593, 93147 11416
E-mail : mdsharma74@live.in



प्रधान सम्पादक - दिनेश रामावत
प्रबंध सम्पादक - राकेश गांधी
राजनीतिक सम्पादक - सुरेश व्यास
कार्यकारी सम्पादक - अजय अस्थाना
सह सम्पादक - बलवंत राज मेहता

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली - राधा रमण
जयपुर - मणिमाला शर्मा
अजमेर - धर्मेन्द्र प्रजापति
उदयपुर - मधुलिका सिंह
कोटा - अरविन्द गुप्ता
बीकानेर - राकेश आचार्य
पाली - चैनराज भाटी
सिरोही - गणपत सिंह
जालोर - तरुण गहलोत
बाड़मेर - धर्मसिंह भाटी

रेखाचित्र - राजेंद्र यादव

विज्ञापन प्रतिनिधि

जोधपुर - प्रवीण गिरी - 99280 26609

संपादकीय कार्यालय

बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स महावीर कॉलोनी,
भास्कर सर्किल, रातानाड़ा, जोधपुर - 342 011
फ़ाट्सएफ नंबर - 81078 00000

ई-मेल - rajasthanodaya@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और प्रधान सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पुनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342 011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्पोरेट लिमिटेड, 10 जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर में मुद्रित। संपादक : अजय अस्थाना*
(*पी आर पी एक्ट के तहत उत्तरदायी)

4 अपनी बात
जीत बड़ी, जमीन उतनी मजबूत नहीं

नियमित कॉलम

21 बात बेलगाम **30** बोल हरि बोल
39 अभिव्यक्ति **42** ग्रहों की चाल

5 एक जनादेश, कई तस्वीरें



6 जयपुर संभाग-हाई प्रोफाइल मुकाबले...



8 जोधपुर संभाग - मारवाड़ में भगवा लहर



10 अजमेर संभाग...
जनादेश पर भारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट

13 कोटा संभाग...
भाजपा आगे, गुटबाजी से पिछड़ी कांग्रेस

15 उदयपुर संभाग...
भाजपा भारी, कांग्रेस ने भी दी टक्कर

17 भरतपुर संभाग...
बेअसर होते परम्परागत गढ़

19 बीकानेर संभाग...
बीकानेर में कांग्रेस की वापसी

24 जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही...
शहर हमारा है, जिम्मेदारी किसकी?

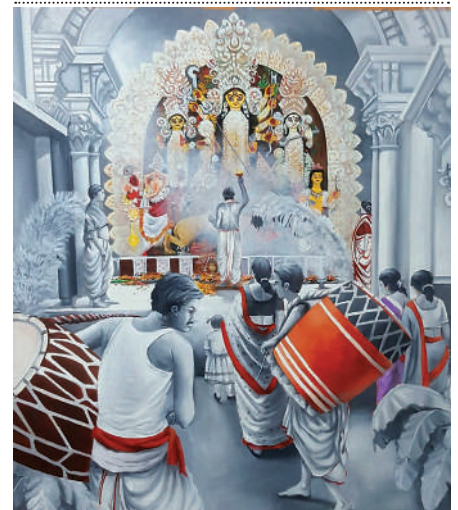
26 राजकाज...
चुनाव आयोग की साख पर सवाल

28 ब्रिक्स सम्मेलन...
मतभेद के बीच सहयोग की राह

31 श्राद्ध और पुनर्जन्म...
आत्मा बदली तो श्राद्ध किसका?

34 स्पोर्ट्स...
'विशट' तूफान और कीर्तिमानों का महाकुंभ

38 युवा एवं करियर...
हरित कौशल, नए करियर



40 दुर्गा पूजा...
राजस्थान में गूंजी बंगाल की धुन

जीत बड़ी, जमीन उतनी मजबूत नहीं



कुछ दिन पहले शहर की एक गली से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मिले। टूटी सड़क की तरफ इशारा करते हुए बोले, “साहब, चुनाव तो हर बार होते हैं, बदलता कुछ नहीं।” उनकी बात में शिकायत कम, थकान ज्यादा थी। राजस्थान के निकाय चुनावों के नतीजे देखने के बाद वही बात बार बार याद आती रही।

नतीजे आते हैं तो पहला सवाल होता है कि कौन जीता और किसका बोर्ड बना? लेकिन नगर निकाय चुनाव की असली कहानी वाडों के आंकड़ों, स्थानीय चेहरों और चुनाव के बाद बने समीकरणों में छिपी होती है।

राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में 10,245 वाड हैं। अंतिम उपलब्ध परिणामों में भाजपा ने 4,182, कांग्रेस ने 3,619 और निर्दलीयों ने 2,273 वाड जीते। यानी वाडों में भाजपा की हिस्सेदारी करीब 40.8 और कांग्रेस की करीब 35.3 प्रतिशत रही, साढ़े पांच प्रतिशत अंक की बढ़त। लेकिन वोटों में भाजपा को 35.18 और कांग्रेस को 34.24 प्रतिशत मिले, यानी अंतर एक प्रतिशत अंक से भी कम। मतदाताओं का फैसला उतना एकतरफा नहीं था, जितना बोर्डों और मेयर पदों की संख्या से लगता है।

यही इस चुनाव का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। भाजपा ने वाडों की बढ़त को बोर्डों और मेयर पदों में बदल दिया। 25 सितंबर को जयपुर, जोधपुर और कोटा के मेयर चुनाव भी उसने जीते और दस में से नौ नगर निगमों में उसके मेयर हो गए। एकमात्र अपवाद बीकानेर रहा, जहां कांग्रेस का मेयर बना। फिर भी इसे हर जगह एकतरफा जनादेश नहीं कहा जा सकता।

जोधपुर में भाजपा को 45 और कांग्रेस को 44 वाड मिले, यानी मुकाबला लगभग बराबरी का था, फिर भी निर्दलीयों और अन्य समर्थन से भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता मेयर बने। अजमेर में कांग्रेस के 37 और भाजपा के 32 पार्षद थे, फिर भी मेयर भाजपा का बना। पाली में भी कांग्रेस के पास ज्यादा पार्षद थे, पर चुनाव बाद के समीकरणों ने भाजपा को मेयर पद तक पहुंचा दिया। भरतपुर में निर्दलीय सबसे बड़ा समूह थे, वहां भी भाजपा की अनुराधा सिंह निर्विरोध मेयर बनीं।

इन्हें केवल “जोड़ तोड़” कहना तस्वीर को छोटा करना होगा। पार्षदों के बीच बनने वाले समीकरण भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हां, ऐसे मामलों में बोर्ड का गठन सीधे वाड स्तर के बहुमत का प्रतिबिंब नहीं होता।

बीकानेर इसका उलटा उदाहरण है। वहां कांग्रेस के पास 80 में से 42 पार्षद थे। मेयर चुनाव में अनिल कल्ला को



दिनेश रामावत
प्रधान सम्पादक

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने दस में से नौ नगर निगमों में मेयर पद जीते। वाडों में वह सबसे आगे रही, लेकिन कुल वोट में कांग्रेस से उसका अंतर सिर्फ 0.94 प्रतिशत ही रहा। कई शहरों में कांग्रेस या निर्दलीयों के पास ज्यादा पार्षद होने के बावजूद बोर्ड भाजपा का बना। यह चुनाव सिर्फ जीत और हार का नहीं, स्थानीय राजनीति के बदलते गणित को समझने का भी है।

50 और भाजपा को 30 वोट मिले। जहां वाडों का गणित साफ था, वहां बोर्ड का नेतृत्व भी उसी दिशा में गया।

निर्दलीयों की भूमिका भी बड़ी कहानी है। 2,273 वाडों में वे जीते और उनका वोट शेयर करीब 27 प्रतिशत रहा। इनमें स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे भी हैं और टिकट न मिलने पर अलग राह चुनने वाले नेता भी, पर यह संख्या बताती है कि शहरी राजनीति में पार्टी चिन्ह के अलावा उम्मीदवार की अपनी पहचान मायने रखती है। बारां में आम आदमी पार्टी का बोर्ड बनना भी बताता है कि मुकाबला हमेशा भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहता।

भाजपा की सफलता को कम करके देखने का कोई कारण नहीं। उसने वाडों में सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, अधिकांश निकायों में बोर्ड बनाए और नौ निगमों में मेयर पद हासिल किया। पर एक प्रतिशत अंक से कम के वोट अंतर को देखते हुए इसे राज्यभर में उसी अनुपात के जनसमर्थन का प्रमाण मानना सही नहीं होगा।

कांग्रेस के लिए भी सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि वह हार गई। उसने बीकानेर जीता, अजमेर और पाली में उसके पार्षद ज्यादा रहे और वोट शेयर में वह भाजपा से बहुत पीछे नहीं थी। समस्या यह है कि वह वाड स्तर के समर्थन को कई जगह सत्ता में नहीं बदल सकी। यह संगठन, स्थानीय नेतृत्व और चुनाव बाद के प्रबंधन, तीनों पर सवाल उठाता है।

अब असली परीक्षा शुरू हुई है। मेयर बन गया, बोर्ड बन गया, शपथ भी हो गई, पर शहर के लिए चुनाव यहीं खत्म नहीं होता। भाजपा के सामने चुनौती है कि बढ़त को बेहतर प्रशासन में बदले। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि बची जमीन को संगठित और भरोसेमंद राजनीति में बदले। निर्दलीयों की जवाबदेही भी उतनी ही है, क्योंकि पार्टी का झंडा न होने से जनता के सवाल खत्म नहीं होते।

नगर निकाय की खूबी यही है कि जनता अपने नुमाइंदों को रोज देखती है। सुबह नल खोलते वक्त, जलभराव से गुजरते वक्त, कूड़े के ढेर के पास से निकलते वक्त और रात को अंधेरी गली में लौटते वक्त। यही रोजमर्रा का अनुभव बोर्ड का असली रिपोर्ट कार्ड है।

जनता को यह याद नहीं रहेगा कि किस मेयर को कितने वोट मिले। उसे याद रहेगा कि सड़क बनी या नहीं, पानी समय पर आया या नहीं, कचरा उठा या नहीं और गली की बत्ती जली या नहीं।

चुनावी शोर थम चुका है, विजय जुलूस भी निकल चुके हैं। अब शहरों की बारी है यह पूछने की कि बदला क्या?

एक जनादेश, कई तस्वीरें

राजस्थान के निकाय चुनावों ने सत्ता की तस्वीर के साथ शहरों की अलग-अलग राजनीतिक पसंद भी सामने रखी है। कहीं स्पष्ट बहुमत मिला तो कहीं मुकाबला करीबी रहा। संभागवार नतीजे प्रदेश के शहरी जनादेश को समझने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

राजस्थान के शहरों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बारी इस जनादेश को समझने की है। परिणामों को केवल इस गिनती तक सीमित कर देना आसान है कि किस दल ने कितने निकाय जीते, लेकिन स्थानीय चुनावों की तस्वीर इससे कहीं व्यापक होती है। यहां मतदाता के सामने बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ उसके शहर की सड़क, सफाई, पानी, सीवरेज, यातायात और रोशनी जैसे रोजमर्रा के सवाल भी होते हैं। प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय समीकरण भी नतीजों पर असर डालते हैं।

प्रदेश स्तर पर भाजपा ने स्पष्ट बढ़त बनाई है। वार्डों की जीत में वह कांग्रेस से आगे रही और निर्दलीयों ने भी बड़ी संख्या में वार्ड जीतकर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन वोट शेयर में भाजपा और कांग्रेस का अंतर एक प्रतिशत अंक से भी कम रहा। यानी मतदाताओं के स्तर पर मुकाबला लगभग बराबरी का था।

शीर्ष पदों के चुनाव में तस्वीर बदल गई। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों में भाजपा कांग्रेस से काफी आगे निकल गई। दस नगर निगमों में से नौ में भाजपा के महापौर बने हैं। कांग्रेस के पास केवल बीकानेर है, जहां उसने साफ बहुमत के साथ वापसी की। जयपुर, जोधपुर और कोटा के महापौर चुनाव सबसे अंत में, 25 सितंबर को हुए और तीनों में भाजपा जीती।

इसका मतलब है कि पार्षदों के वोट और शीर्ष पद की कुर्सी हमेशा एक ही कहानी नहीं कहते। स्थानीय चुनावों में पार्टी को मिले

कुल वोट सत्ता का अकेला आधार नहीं होते। चुनाव के बाद बनने वाले गठजोड़, निर्दलीयों का रुख और संगठन की रणनीति अक्सर अंतिम नतीजा तय करती है।

निर्दलीयों की भूमिका यहीं सबसे अहम हो जाती है। वार्डों में उनकी ताकत बड़ी रही, लेकिन शीर्ष पदों तक वे गिनती के निकायों में ही पहुंच सके। कई जगह उन्होंने किसी दल को बहुमत तक पहुंचाया या शीर्ष पद के चुनाव में निर्णायक समर्थन दिया। भरतपुर इसका अनूठा उदाहरण है, जहां निर्दलीय पार्षदों की संख्या भाजपा और कांग्रेस दोनों से ज्यादा रही, फिर भी महापौर पद भाजपा के खाते में निर्विरोध चला गया।

अजमेर और पाली में यह अंतर सबसे साफ दिखता। अजमेर में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, फिर भी भाजपा की अनामिका शर्मा निर्दलीयों के समर्थन से महापौर

बनीं। पाली में भी कांग्रेस के पार्षद सबसे ज्यादा थे, लेकिन भाजपा की नमिता बुबकिया महापौर चुनी गईं। यहां कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी को बहुत ही कम वोट मिले, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी टक्कर देकर दूसरे स्थान पर रहीं।

जोधपुर में वार्ड की तस्वीर बेहद करीबी थी। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद लगभग बराबर थे। इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी को छह वोट से हरा दिया। जयपुर और कोटा में भाजपा का महापौर पद पर पलड़ा कहीं ज्यादा भारी रहा। यह अंतर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। छोटे

निकायों में भी कहीं मुकाबला एक वोट पर टिका रहा, जैसे कोटा जिले की सुकेत नगरपालिका में, तो कहीं कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जैसे श्रीविजयनगर में।

इन नतीजों को केवल भाजपा की बढ़त या कांग्रेस की चुनौती के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली सवाल यह है कि अलग-अलग शहरों के मतदाताओं ने अपने स्थानीय नेतृत्व के बारे में क्या संकेत दिए हैं। क्या पुरानी नाराजगी ने किसी जगह परिणाम बदला? क्या मजबूत संगठन ने किसी दल को बढ़त दिलाई? क्या स्थानीय चेहरे ने पार्टी के पारंपरिक आधार को प्रभावित किया? और क्या निर्दलीयों की मजबूती यह बताती है कि मतदाता दलों से अलग विकल्प तलाश रहा है?

इन सवालों के जवाब पूरे प्रदेश में एक जैसे नहीं मिलेंगे। राजस्थान भौगोलिक और सामाजिक रूप से जितना विविध है, उसके शहरों की राजनीतिक

पसंद भी उतनी ही अलग है। पश्चिमी राजस्थान का चुनावी मिजाज पूर्वी राजस्थान से अलग हो सकता है। शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती और मारवाड़ के शहरों में स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व की अपनी भूमिका है। इसलिए किसी एक शहर का परिणाम वहां के समीकरण समझे बिना पूरे प्रदेश का संकेत नहीं माना जा सकता।

चुनाव परिणामों की बड़ी तस्वीर भाजपा की बढ़त दिखाती है, लेकिन शहरों के भीतर मौजूद अलग-अलग समीकरण बताते हैं कि यह जनादेश एकरंगी नहीं है। कहीं संगठन और दल का प्रभाव दिखता है तो कहीं स्थानीय चेहरा सबसे अहम बनकर उभरता है। अगले पन्नों पर संभागवार चुनावी तस्वीर इसी जनादेश के अलग-अलग रंगों को सामने रखती है।



राजस्थान टुडे में आगे प्रस्तुत संभागवार तस्वीर इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन रिपोर्टों में केवल यह नहीं बताया गया है कि किस संभाग में किस दल ने कितने निकाय जीते। यह देखने का प्रयास है कि जनादेश का मिजाज कहां कैसा रहा, मुकाबला कहां एकतरफा और कहां करीबी रहा, किन शहरों में स्थानीय नेतृत्व ने भूमिका निभाई और कहां निर्दलीयों ने समीकरण बदल दिए।

हाई प्रोफाइल मुकाबले में बंटा जनादेश

जयपुर संभाग के निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। भाजपा ने अधिक निकायों में बोर्ड बनाए, लेकिन कई जिलों में कांग्रेस और निर्दलीयों ने चुनौती दी, जिससे मिश्रित जनादेश मिला।



मनीष गोधा वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

प्रदेश के सबसे बड़े और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जयपुर संभाग में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग बराबर की टक्कर देखने को मिली। जयपुर संभाग में राजधानी जयपुर, अलवर, सीकर और दौसा भाजपा और कांग्रेस के हेवीवेट नेताओं के जिले हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचन्द बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़,



सुनील कोठारी, महापौर



सरोज कंठर, उपमहापौर

संजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे नेता इन जिलों से आते हैं। ऐसे में इस संभाग चुनावी मुकाबले पर

पूरे प्रदेश की नजर थी और मुकाबला भी रोचक हुआ। संभाग के कुल 90 निकायों में भाजपा 49 और कांग्रेस 40 निकायों में बोर्ड बनाने में कामयाब रही। एक निकाय निर्दलीय के नाम रहा। चुनाव परिणाम में भी दोनों दलों के बीच सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और निर्दलीयों ने दोनों ही दलों को अच्छी टक्कर दी।

चुनाव परिणाम में भाजपा संभाग के जयपुर, अलवर और खैरथल- तिजारा में बेहतर प्रदर्शन करती दिखी। वहीं कांग्रेस के लिए दौसा, झुंझुनूं और सीकर जिले अच्छे रहे। वहीं कोटपुतली-बहरोड़ में निर्दलीयों का वर्चस्व दिखा। वैसे चुनाव परिणाम में निर्दलीयों ने पूरे संभाग में ही अच्छा प्रदर्शन किया। जयपुर, झुंझुनूं में तो कई संभागों में निर्दलीय ही किंगमेकर बने नजर आए। कुल मिलाकर इस संभाग के शहरी मतदाता ने विधानसभा और लोकसभा का ट्रेंड निकाय चुनाव में भी कमोबेश बनाए रखा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर, झुंझुनूं और दौसा जैसे जिलों में कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल की थी और वहीं स्थिति इस बार भी दिखी। यह भाजपा के लिए चिंता की स्थिति हो सकती है कि ढाई साल के शासन के बाद भी पार्टी इन जिलों के मतदाता को अपेक्षा के अनुरूप साथ नहीं पाई। नए बने जिलों खैरथल- तिजारा और बहरोड़- कोटपुतली के मतदाता ने ना तो जिला बनाने वाली कांग्रेस को निहाल किया और ना ही जिला बनाए रखने वाली भाजपा को पूरा समर्थन दिया।

राजधानी जयपुर हमेशा की तरह इस चुनाव में भी भाजपा का गढ़ साबित हुई। पार्टी यहां एक बार फिर नगर निगम में बहुमत पाने और बोर्ड बनाने में सफल रही। चुनाव से पहले कराए गए परिसीमन का पार्टी ने पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस जयपुर शहर में टिकिट वितरण में फेल साबित हुई और गुटबाजी ने एक बार फिर कांग्रेस को हरा दिया।



नगर निगमों में भाजपा का औसत प्रदर्शन

जयपुर संभाग में जयपुर और अलवर दो नगर निगम हैं और इनमें भाजपा का प्रदर्शन ठीकठाक रहा। प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित जयपुर नगर निगम में भाजपा 78 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर गई और बोर्ड बनाने में भी सफल रही, हालांकि यह अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि पार्टी बहुमत से सिर्फ दो सीट ज्यादा हासिल कर पाई है, जबकि मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री जयपुर से हैं। जयपुर को पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां के दस विधानसभा क्षेत्रों में से पार्टी बगरू और आदर्श नगर में कांग्रेस से पिछड़ गई थी, जबकि सिविल लाइंस में बीजेपी और कांग्रेस की बराबरी सीटें थी। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा और पार्टी सिर्फ 57 सीटें हासिल कर पाई। निर्दलीयों ने 15 सीट पर उल्लेखनीय जीत हासिल की।

वहीं अलवर नगर निगम में तो पार्टी स्पष्ट बहुमत भी हासिल नहीं पाई थी, हालांकि बढ़त में थी और बोर्ड भी बना लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य सरकार में मंत्री संजय शर्मा के होने के बावजूद बहुमत से दूरी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

नगर परिषदों में भाजपा के बोर्ड तो बने लेकिन जनादेश मिश्रित था। जयपुर संभाग की नगर परिषदों की बात करें तो भाजपा दस में से छह में बोर्ड बनाने में सफल रही थी, हालांकि उसके पास स्पष्ट बहुमत सिर्फ जयपुर जिले की चौमू नगरपरिषद में था। पार्टी कोटपुतली, बहरोड़, फतहपुर, शाहपुरा और खैरथल में बोर्ड बनाने में सफल रही, इनमें भाजपा को निर्दलीयों का पूरा साथ मिला। वहीं कांग्रेस के पास सीकर में बहुमत था और झुंझुनूं, खैरथल, दौसा और शाहपुरा में बढ़त थी। पार्टी इनमें से सीकर, झुंझुनूं और दौसा बचाने में कामयाब रही, वहीं तिजारा में निर्दलीयों की मदद से सिर्फ एक पार्षद होने के बावजूद बोर्ड बनाने में सफल रही। इस दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर संभाग के शहरी निकायों से भाजपा को जनादेश के रूप में बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले थे, लेकिन सत्ता में होने का फायदा उठाते हुए पार्टी नगरपरिषदों में बढ़त बनाने में सफल रही। चौमू में स्पष्ट बहुमत भाजपा के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि पार्टी यहां से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा अपने गृह जिले सीकर में पार्टी का दबदबा कायम रखने में सफल रहे।

जयपुर - जनादेश निर्दलीयों के साथ, बोर्ड भाजपा ने बनाए



जयपुर जिले की दो नगरपरिषदों और 16 पालिकाओं के चुनाव परिणाम में जनादेश निर्दलीयों के साथ था, क्योंकि 16 पालिकाओं में से भाजपा के पास दो और कांग्रेस के पास तीन में स्पष्ट बहुमत था। वहीं 11 पालिकाओं में फैसला निर्दलीयों के हाथ था। जबकि नगरपरिषदों में भाजपा के पास चौमू में स्पष्ट बहुमत था और शाहपुरा में कांग्रेस को बढ़त थी। बोर्ड बनाने में निर्दलीयों का साथ भाजपा को मिला और 18 निकायों में से 12 में भाजपा के बोर्ड बने, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 में ही बोर्ड बना पाई।

अलवर- भाजपा बेहतर स्थिति में



नाम के मामले में बिना मात्रा के इस जिले की 12 नगरपालिकाओं में भाजपा कांग्रेस से बेहतर स्थिति में थी। पार्टी के पास दो पालिकाओं में बहुमत और तीन में अच्छी बढ़त थी। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत कहीं भी हासिल नहीं कर पाई, हालांकि तीन जगह बढ़त में रही, वहीं निर्दलीयों के पास दो में बहुमत और एक पालिका में बढ़त थी। निर्दलीय आमर पर सत्ता के साथ रहते हैं इसलिए अलवर नगर निगम सहित 9 निकायों में पार्टी बहुमत नहीं होने के बाद भी बोर्ड बना गई और कांग्रेस तीन पर ही कब्जा जमा पाई।

दौसा- कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन

कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर ज्यादातर बार सूटबल रहे दौसा जिले में इस बार भी पार्टी बेहतर स्थिति में रही। नगर परिषद के साथ ही पार्टी नौ में दो नगर पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत के साथ थी, वहीं तीन में पार्टी के पास बढ़त थी, जबकि भाजपा बहुमत कहीं भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बढ़त चार पालिकाओं में रही। वैसे यहां चार पालिकाओं में भाजपा-कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा और सीटों का अंतर ज्यादा नहीं रहा। कांग्रेस यहां 8 और भाजपा 3 निकायों में बोर्ड बनाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट यहां अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे।

नगरपरिषद चुनाव : सीटों का गणित

नगरपरिषद	कुल सीट	भाजपा	कांग्रेस	निर्दलीय	बोर्ड
कोटपूतली	60	19	13	28	भाजपा
झुंझुनू	60	15	30	15	कांग्रेस
खैरथल	45	08	20	17	भाजपा
तिजारा	35	03	01	31	कांग्रेस
बहरोड़	55	20	06	29	भाजपा
दौसा	55	17	24	14	कांग्रेस
सीकर	65	22	38	05	कांग्रेस
फतहपुर	55	13	21	21	भाजपा
चौमू	45	30	12	3	भाजपा
शाहपुरा	55	23	20	12	भाजपा

झुंझुनू - निर्दलीयों के आगे सब फेल

राजनीतिक तौर पर सबसे जागरूक जिलों में गिने जाने वाले झुंझुनू में जनादेश में निर्दलीयों के आगे सब फेल साबित हुए, क्योंकि 18 नगर पालिकाओं में से चार में निर्दलीयों के पास स्पष्ट बहुमत रहा, वहीं पांच में बढ़त थी। दो ऐसी पालिकाएं थी, जहां निर्दलीयों और कांग्रेस की सीटें बराबर थी। हालांकि 17 निकायों में बोर्ड भाजपा और कांग्रेस के ही बने। कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 8 निकायों में बोर्ड बनाए, एक निकाय में निर्दलीय अध्यक्ष बना। चुनाव परिणाम में भाजपा दो जगह स्पष्ट बहुमत और एक पालिका में बढ़त बनाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस ने यहां नगर परिषद और दो पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के साथ दो जगह बढ़त हासिल की। कुल मिलाकर यह जिला हमेशा की तरह कांग्रेस के लिए बेहतर रहा, वहीं निर्दलीयों को बड़ा समर्थन देकर भाजपा कांग्रेस को स्पष्ट संदेश भी दिया कि यहां की शहरी जनता बहुत ज्यादा संतुष्ट दोनों से ही नहीं है।

कोटपूतली-बहरोड़ - निर्दलीयों ने बाजी मारी

दो बड़े कस्बों को मिलाकर बनाए गए इस नए जिले ने चुनाव परिणाम में भाजपा और कांग्रेस से बहुत ज्यादा लगाव नहीं दिखाया और निर्दलीयों पर भरोसा जताया। दोनों नगरपरिषद ही नहीं सात में से चार पालिकाओं में भी वोटर ने इन्हीं पर भरोसा दिखाया है। सत्तारूढ़ भाजपा सिर्फ एक पालिका में बढ़त बना पाई वहीं कांग्रेस पर दो पालिकाओं के वोटर ने भरोसा दिखाया। जिला कांग्रेस ने बनाया था, जनता ने उसे कुछ खास नहीं दिया। भाजपा ने इसे बनाए रखा, जनता ने इसे भी निहाल नहीं किया। हालांकि बोर्ड बनाने के मामले में बंटवारा भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हुआ। दोनों नगर परिषद और तीन पालिकाओं में भाजपा का बोर्ड बना, जबकि चार पालिकाओं में कांग्रेस ने बोर्ड बनाया।

सीकर - कांग्रेस का दबदबा

कांग्रेस के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी सीकर भरोसेमंद साबित हुआ। पार्टी यहां के 14 निकायों में से सीकर नगर परिषद और एक पालिका में स्पष्ट बहुमत के साथ छह निकायों में बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। जबकि भाजपा को फतहपुर नगर परिषद और तीन जगह बढ़त मिली थी। वहीं एक निकाय में मामला बराबरी पर छूटा था, जबकि एक निकाय में निर्दलीय को बढ़त हासिल थी। बोर्ड बनाने में भी कांग्रेस आगे रही और 8 बोर्ड बनाए वहीं 5 जगह भाजपा के बोर्ड बने। एक बोर्ड का फैसला बाद में घोषित हुआ।

खैरथल-तिजारा- भाजपा का दमदार प्रदर्शन

अलवर जिले की दो तहसीलों को मिला कर बनाए गए इस जिले में भाजपा का दमदार प्रदर्शन रहा। खैरथल नगर परिषद में भाजपा के पास बढ़त थी, वहीं चार पालिकाओं में से एक में पार्टी का स्पष्ट बहुमत रहा, वहीं तीन में बढ़त थी। तिजारा नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस दोनों का बहुत खराब प्रदर्शन रहा और बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद सिर्फ एक सीट होने के बावजूद कांग्रेस निर्दलीयों की मदद से यहां बोर्ड बना गई। यहां के सात निकायों में से भाजपा छह में बोर्ड बनाने में सफल रही।

मारवाड़ में भगवा लहर

कई जगह मुकाबले इतने रोचक हुए कि लोग चौंक गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले पाली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद भी अपना बोर्ड नहीं बना सकी और वहां भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया।



सुरेश त्याग वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

हाल ही सम्पन्न जोधपुर सम्भाग के निकाय चुनावों में सत्ताधारी भाजपा अपना सियासी गढ़ बचाने में न सिर्फ कामयाब रही, बल्कि वाडों के चुनाव में कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेस बोर्ड बनाने की चढ़ाई में फिसल कर धड़ाम से नीचे आ गिरी। सिर्फ सिरोंही व जालोर जिला मुख्यालयों में कांग्रेस बोर्ड बना सकी, बाकी सभी जगह भाजपा ने अपने बहुमत व निर्दलीयों की मदद से बोर्ड बना लिए।

सम्भाग मुख्यालय जोधपुर के अलावा पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोंही और फलोदी जिलों के 41 नगरीय निकायों के 1330 वाडों में हुए चुनाव के बाद भाजपा ने बोर्ड बनाने के मामले में बाजी मार ली, लेकिन वाडों और मतों के मामले में उसे कांग्रेस से कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ा। भाजपा ने 657 वाडों में विजय हासिल की तो कांग्रेस के खाते में भी 481 वाड आये, जबकि 187 में निर्दलीय प्रत्याशियों व पांच में रालोपा ने जीत हासिल की। भाजपा ने 41 में से 36 निकायों में बोर्ड बना लिए, जबकि कांग्रेस पांच निकायों में ही अपने सभापति बनवा सकी।

कई जगह मुकाबले इतने रोचक हुए कि लोग चौंक गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले पाली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद भी अपना बोर्ड नहीं बना सकी और वहां भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया।

सम्भाग के निकायों के परिणाम और शहर की सरकार पर कब्जे की तुलना करें तो सामने आता है कि वाडों के चुनाव में भले ही दोनों दलों में कांटे की टक्कर रही, लेकिन बोर्ड बनाने की लड़ाई में बड़ा अंतर आ गया। कई निकायों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बोर्ड नहीं बना सकी। दूसरी तरफ भाजपा कई जगह बहुमत से पीछे रहते हुए भी निर्दलीयों के समर्थन से अध्यक्ष, सभापति या महापौर पद हासिल करने में सफल रही। कुल मिलाकर कहानी ये नहीं है कि जोधपुर सम्भाग में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ दिया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने जीती हुई सीटों को अन्य विजेताओं की मदद से स्थानीय सत्ता में बदलने की क्षमता में कांग्रेस को बुरी तरह मात दी है। भाजपा को स्थानीय सत्ता के स्तर पर स्पष्ट बढ़त मिली है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना अस्तित्व बचाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी।



प्रसन्नचंद मेहता।



विजय सिंह पंवार।

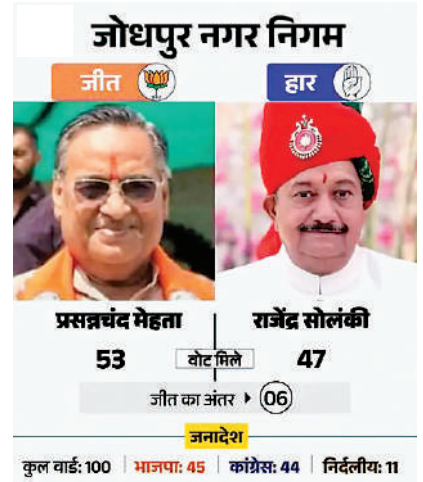
बड़ी ताकत बनकर उभरे निर्दलीय

इन चुनावों निर्दलीय भी एक ताकत बनकर उभरे हैं। पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोंही, पोकरण और फलोदी सहित अनेक निकायों में निर्दलीय पार्षदों ने बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभाई। सम्भाग में 190 वाडों में जीत के अलावा कई जगह सत्ता का ताला निर्दलीयों की चाबी से ही खुला है। राज्य स्तर पर भी लगभग 27 प्रतिशत वोट लेकर निर्दलीयों ने संकेत दे दिया है कि प्रमुख दलों के आधिकारिक उम्मीदवारों से असंतुष्ट स्थानीय मतदाता हमेशा दूसरे प्रमुख दल की ओर नहीं जाता। वह निर्दलीय को भी विकल्प बना सकता है। इस स्थिति ने प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों के सामने उम्मीदवार चयन और स्थानीय संगठन की स्थिति को चुनौती पूर्ण बना दिया है।

जोधपुर जिले में कड़ा मुकाबला

- जोधपुर जिले में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। जिले के सात निकायों के 275 वाडों में भाजपा ने 129 और कांग्रेस ने 120 वाड जीते। निर्दलीयों के खाते में 23 व रालोपा को 3 वाडों में जीत हासिल हुई। सम्भाग में सबसे कड़ा मुकाबला भी जोधपुर नगर निगम में हुआ। यहां के 100 वाडों में से भाजपा को 45, कांग्रेस 44, निर्दलीय 10 व एक में रालोपा जीती, लेकिन भाजपा ने सात निर्दलीय अपने पक्ष में कर निगम में अपना बोर्ड बना लिया।
- साल 2020 में जोधपुर में दो नगर निगम के 160 वाड थे। उस चुनाव में कांग्रेस ने नगर निगम उत्तर और भाजपा ने नगर निगम दक्षिण में अपने बोर्ड बनाए थे। संयुक्त रूप से कांग्रेस व भाजपा के पास क्रमशः 82 व 62 वाड थे, लेकिन हाल ही हुए चुनाव में एक निगम बनने के बाद दोनों ही पार्टियां लगभग बराबरी पर आ गईं।
- जिले में नई बनी नगर पालिकाओं मथानिया, तिंवरी, भोपालगढ़ व बालेसर सत्ता तथा पहले से मौजूद बिलाड़ा व पीपाड़ में भी दोनों दलों में टक्कर नजर आई, लेकिन कांग्रेस मथानिया व पीपाड़ में ही बोर्ड बना सकी। भोपालगढ़ में बहुमत के बावजूद भाजपा का सभापति चुन लिया गया।

मेहता महापौर व पंवार उप महापौर



महापौर के चुनाव में भी यह करीबी मुकाबला आगे दिखाई दिया। भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी आमने-सामने थे। मतदान के बाद मेहता को 53 और सोलंकी को 47 मत मिले। इस तरह भाजपा ने महापौर पद छह मतों के अंतर से जीत लिया। इसी तरह उपमहापौर पद का चुनाव संघर्षपूर्ण रहा। यहां भाजपा के विजय सिंह पंवार ने कांग्रेस के अब्दुल करीम जानी को हराकर उपमहापौर पद हासिल किया।

पाली में बागी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल

पाली के 10 निकायों में 320 वार्डों में से भाजपा ने 161, कांग्रेस ने 102 और निर्दलीयों व अन्य ने 57 वार्ड जीते। पाली नगर निगम में कांग्रेस 29 सीटें जीतकर सबसे



बड़ी पार्टी बनी, लेकिन महापौर के चुनाव में कांग्रेस की बागी राजबाला हिंगड़ ने खेल बिगाड़ दिया। भाजपा की नमिता बुबकिया 33 वोट हासिल कर महापौर बन गई। हिंगड़ 29 वोट ले गई और कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा केवल तीन वोट मिले। जिले

के अन्य निकायों में कांग्रेस को उबरने का मौका तक नहीं मिला। सोजत सिटी, सोजत रोड, सुमेरपुर, तख्तगढ़ व बाली में भाजपा भारी रही। केवल मारवाड़ जंक्शन में कांग्रेस-भाजपा को 11-11 वार्डों में सफलता मिली और आखिरी बोर्ड बनाने की लॉटरी भाजपा के नाम खुल गई।

बाड़मेर में 15 साल बाद फिर भाजपा



बाड़मेर में भाजपा ने 15 साल बाद वापस नगर परिषद पर कब्जा जमाया। परिषद के 55 वार्डों में से भाजपा ने 29 सीटें हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस को 21 व निर्दलीयों को पांच सीटें मिली। जिले की चौहटन नगरपालिका में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहां भाजपा के 11 व 9 निर्दलीय जीते और भाजपा ने आसानी से बोर्ड बना लिया।

जैसलमेर में कड़ा मुकाबला, सभापति भाजपा का



जैसलमेर नगर परिषद व पोकरण नगरपालिका में मुकाबला बराबर का रहा। भाजपा ने जैसलमेर परिषद में बहुमत हासिल कर अपना सभापति चुनवा लिया। भाजपा ने 45 सदस्यीय बोर्ड में 25 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 16 व चार सीटें निर्दलीयों ने जीती। पोकरण की 25 सदस्यीय नगर पालिका में कांग्रेस ने 12 व भाजपा ने 11 सीटें जीती। दो वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए, लेकिन बोर्ड पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया।

बालोतरा में भी भारी पड़ी भाजपा



नवगठित बालोतरा जिले के सात निकायों के 185 में से 105 वार्डों में जीत हासिल कर भाजपा भारी पड़ी। कांग्रेस को 62 व निर्दलीयों को 18 वार्डों में जीत मिली, लेकिन सभी सात निकायों में कमल ही खिला। बालोतरा नगर परिषद के साथ जसोल, समदड़ी, सिवाना, सिणधरी, गुडामलानी व धोरीमन्ना में सभी जगह भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई।



जालोर में कांग्रेस की वापसी



जालोर जिले में कांग्रेस झंडे तो नहीं गाढ़ सकी, लेकिन जिला मुख्यालय की नगर परिषद में बहुमत से दो सीट कम होने के बावजूद उसने अपना सभापति बनवा कर वापसी कर ली। लम्बे अरसे से भाजपा का गढ़ रहे जालोर में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। वहां उसे 19, भाजपा को 14 व निर्दलीयों को सात वार्डों में जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने चार निर्दलीयों को अपने पक्ष में करके बोर्ड बना लिया। जिले के पांच निकायों में 165 वार्डों के चुनाव में भाजपा को 82, कांग्रेस को 50 व निर्दलीयों को 33 सीटें मिली। जालोर के अलावा कांग्रेस भीनमाल, सांचौर, आहोर व सायला में सभी जगह वार्डों की संख्या में भाजपा से पीछे ही रही और इन सभी में भाजपा के बोर्ड बने।

सिरोही में भाजपा को कड़ी टक्कर



सिरोही के छह निकायों में 180 वार्डों में से 79 पर जीत हासिल कर कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। भाजपा 77 तो निर्दलीय व अन्य 24 वार्डों में जीते। सिरोही में कांग्रेस ने बोर्ड भी बना लिया। पिंडवाड़ा में कांग्रेस बहुमत हासिल करने के बाद भी अपना बोर्ड नहीं बना सकी। शिवगंज, आबूरोड, माउंट आबू व मंडार नगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन बोर्ड बनाने में भाजपा ने बाजी मार ली।

फलोदी में भी भाजपा का परचम

नए बने फलोदी जिले के दो निकायों फलोदी नगर परिषद व पहली बार बनी बाप नगर पालिका में भाजपा ने कब्जा किया। दोनों निकायों के 60 वार्डों में से भाजपा ने 27, कांग्रेस ने 19 व निर्दलीयों ने 14 वार्ड जीते।

संभाग में आंकड़ों की कहानी

निकाय- 41 | वार्ड- 1330

भाजपा- 657 | कांग्रेस- 481 | निर्दलीय- 187 | रालोपा- 10

बोर्ड: भाजपा- 36 | कांग्रेस- 05

जनादेश पर भारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट



धर्मेंद्र प्रजापति,

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

अजमेर संभाग के निकाय चुनावों में भाजपा का दबदबा रहा। 52 में से 36 निकायों में भाजपा ने अपने प्रमुख बनाए हैं, जबकि कांग्रेस 14 पर सिमट गई। अजमेर में 37 पार्षदों के बावजूद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और 32 पार्षदों वाली भाजपा ने अपना महापौर बना लिया। किशनगढ़, डीडवाना और कुचामन में भी पार्षदों का गणित बदल गया है।

अजमेर संभाग के नगर निकाय चुनाव में की तस्वीर बताती है कि भाजपा ने न केवल पार्षद सीटों में बढ़त बनाई, बल्कि निर्दलीयों के समर्थन और बेहतर चुनावी प्रबंधन के बल पर निकाय प्रमुखों के चुनाव में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया।

अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, नागौर और टोंक जिलों के कुल 52 निकायों में भाजपा के 36 महापौर, सभापति अथवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस 14 निकाय प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर सकी। नागौर जिले की मारवाड़-मूंडवा नगरपालिका में आरएलपी और रियांबड़ी नगरपालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद जीता।

वार्ड चुनाव में जिन 26 निकायों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, उनमें निर्दलीय पार्षदों और छोटे दलों ने निर्णायक भूमिका निभाई। अध्यक्षीय चुनाव के बाद यह भी साफ हो गया कि इस खंडित जनादेश का सबसे अधिक राजनीतिक लाभ भाजपा ने उठाया।



बाड़ाबंदी के बावजूद वोटों का गणित बदला, क्या कांग्रेस अपने ही पार्षदों की नब्ज नहीं टटोल पाई?



*अन्य में आरएलपी और निर्दलीय के एक-एक निकाय प्रमुख शामिल हैं।

पार्षद चुनाव में भाजपा 740, कांग्रेस 589 सीटों पर

■ संभाग के 52 शहरी निकायों में कुल 1,695 वार्ड निर्धारित थे, लेकिन टोंक नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के कारण 1,694 वार्डों के परिणाम घोषित हुए।

■ भाजपा ने 740 पार्षद सीटें जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को 589, निर्दलीयों को 321 और आरएलपी सहित अन्य दलों को 44 सीटें मिलीं। भाजपा कांग्रेस से 151 सीट आगे रही। यह बढ़त मुख्य रूप से नगरपालिकाओं और छोटे कस्बों में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन से बनी।

जिला अनुसार घोषित सीटों का विवरण

क्षेत्र	निकाय	घोषित सीटें	भाजपा	कांग्रेस	निर्दलीय	अन्य
अजमेर जिला	9	315	160	120	33	2
ब्यावर जिला	5	170	91	49	22	8
भीलवाड़ा जिला	11	325	156	102	66	1
डीडवाना-कुचामन	8	285	81	105	94	5
नागौर जिला	9	285	96	101	60	28
टोंक जिला	10	314	156	112	46	0
अजमेर संभाग	52	1,694	740	589	321	44

अजमेर में बड़ा उलटफेर
37 पार्षद कांग्रेस के, महापौर भाजपा की

अनामिका शर्मा,
महापौरहेमंत सांखला,
उप महापौर

अजमेर नगर निगम का परिणाम पूरे संभाग के अध्यक्षीय चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर रहा। 80 सदस्यीय निगम में कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद चुने गए थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत के 41 के आंकड़े से चार सीट पीछे थी। भाजपा को महापौर बनाने के लिए नौ अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी।

महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा को 43 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल को 37 वोट प्राप्त हुए। इस तरह भाजपा ने अपने निर्वाचित पार्षदों की संख्या से 11 वोट अधिक हासिल कर छह मतों से महापौर पद जीत लिया।

कांग्रेस को उतने ही वोट मिले, जितने उसके पार्षद थे। परिणाम का सीधा राजनीतिक संकेत है कि निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भाजपा के पक्ष में गया। इस जीत के साथ भाजपा ने अजमेर नगर निगम में अपना बोर्ड बचा लिया, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सत्ता से बाहर रह गई।

यह परिणाम केवल महापौर पद की हार-जीत नहीं, बल्कि कांग्रेस के राजनीतिक और रणनीतिक प्रबंधन की बड़ी विफलता है। जनता ने भाजपा से अधिक पार्षद कांग्रेस को दिए, लेकिन कांग्रेस उस जनादेश को सत्ता में परिवर्तित नहीं कर सकी। दूसरी ओर भाजपा ने संख्या में पीछे रहने के बावजूद निर्दलीयों को अपने पक्ष में जोड़कर महापौर बना लिया।

26 त्रिशंकु निकायों में भाजपा का चुनावी प्रबंधन भारी

वार्ड परिणामों में भाजपा को 18 और कांग्रेस को 7 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला था। मकराना में 36 निर्दलीय पार्षद जीते थे। शेष 26 निकायों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।

लेकिन निकाय प्रमुखों के चुनाव में भाजपा

ने 36 पद जीत लिए। इसका अर्थ है कि पार्टी ने अपने स्पष्ट बहुमत वाले निकायों के अतिरिक्त 18 और निकायों में निर्दलीयों, छोटे दलों अथवा दूसरे खेमे से मिले समर्थन के सहारे सत्ता हासिल की।

कांग्रेस के पास सात निकायों में स्पष्ट बहुमत था, जबकि उसके 14 निकाय प्रमुख बने। उसने सात अतिरिक्त निकायों में समर्थन जुटाया, लेकिन खंडित जनादेश को सत्ता में बदलने की दौड़ में भाजपा उससे काफी आगे रही।

सवाल: अजमेर का मेयर जनता के जनादेश से बना या राजनीतिक प्रबंधन से?

अब परिणाम सामने है। 37 पार्षदों वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर है और 32 पार्षदों वाली भाजपा ने महापौर बना लिया। हालांकि किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त का कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है, इसलिए किसी दल अथवा पार्षद पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन निर्दलीय पार्षदों का एकतरफा समर्थन किन राजनीतिक अथवा विकास संबंधी शर्तों पर मिला, इसे सार्वजनिक करना लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए आवश्यक है।

अजमेर जिले में 9 में 8 निकायों पर भाजपा

अजमेर जिले में भाजपा ने अध्यक्षीय चुनाव में एकतरफा बढ़त बनाई। जिले के नौ निकायों में से आठ में भाजपा और केवल केकड़ी में कांग्रेस का निकाय प्रमुख बना।

- अजमेर नगर निगम-अनामिका शर्मा, भाजपा
- किशनगढ़ नगर परिषद-राजकुमार, भाजपा
- पुष्कर नगर परिषद-राजेंद्र बाकोलिया, भाजपा; निर्विरोध
- केकड़ी नगरपालिका-अनिल कुमार मित्तल, कांग्रेस
- नसीराबाद नगरपालिका-सुखदेव, भाजपा
- पीसांगन नगरपालिका-लोकेश, भाजपा
- सरवाड़ नगरपालिका-मनोज सैनी, भाजपा
- सावर नगरपालिका-पद्मिनी, भाजपा
- टांटोटी नगरपालिका-टीकम, भाजपा

किशनगढ़ में भाजपा के केवल 29 पार्षद थे और बहुमत के लिए 31 वोट चाहिए थे, लेकिन भाजपा के राजकुमार ने 41 वोट हासिल किए। नसीराबाद में भाजपा और कांग्रेस के नौ-नौ पार्षद थे; भाजपा के सुखदेव 11 वोट लेकर अध्यक्ष बने। पीसांगन में भाजपा के नौ पार्षद होने के बावजूद लोकेश को 16 वोट मिले।

केकड़ी में कांग्रेस के अनिल कुमार मित्तल ने 21 वोट लेकर अध्यक्ष पद जीता। यहां कांग्रेस के 20, भाजपा के 18 और आरएलपी के दो पार्षद थे।

ब्यावर जिले में भाजपा का क्लीन स्वीप

ब्यावर जिले के सभी पांच निकाय प्रमुख पद भाजपा के खाते में गए।

- ब्यावर नगर परिषद-पुष्पा बल्लुआ
- बिजयनगर नगरपालिका-ममता
- जैतारण नगरपालिका-भेणाराम गहलोत
- मसूदा नगरपालिका-टीकम चंद माली
- रायपुर नगरपालिका-मदन लाल; निर्विरोध

ब्यावर नगर परिषद में भाजपा के 23 पार्षद थे और बहुमत के लिए 31 वोट चाहिए थे। इसके बावजूद भाजपा की पुष्पा बल्लुआ सभापति बनीं। यहां 13 निर्दलीय और आरएलपी के चार पार्षदों की भूमिका निर्णायक रही।

भीलवाड़ा में भाजपा को 8, कांग्रेस को 3 निकाय

भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के पास 45 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत था। भाजपा की जसवंत कंवर निर्विरोध महापौर चुनी गईं।

जिले में भाजपा ने भीलवाड़ा निगम के अलावा आसींद, बनेड़ा, बीगोद, बिजौलिया, गुलाबपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ में सत्ता हासिल की। कांग्रेस ने गंगापुर, हमीरगढ़ और शाहपुरा नगरपालिका अध्यक्ष पद जीते।

- भीलवाड़ा निगम-जसवंत कंवर, भाजपा; निर्विरोध
- आसींद-सत्येंद्रसिंह चौहान, भाजपा
- बनेड़ा-गोपालचरण, भाजपा
- बीगोद-लोकेश कुमार नागौरी, भाजपा
- बिजौलिया-स्नेहा तिवाड़ी, भाजपा
- गंगापुर-प्रीति काकानी, कांग्रेस
- गुलाबपुरा-विष्णु देवी वैष्णव, भाजपा
- हमीरगढ़-प्रकाश जाट, कांग्रेस
- जहाजपुर-अलकेश, भाजपा
- मांडलगढ़-श्वेता देवी डांगी, भाजपा
- शाहपुरा-रमेश कुमार सेन, कांग्रेस

नागौर में बहुकोणीय राजनीति कायम

नागौर जिले के नौ निकायों में भाजपा के चार, कांग्रेस के तीन, आरएलपी के एक और निर्दलीय के एक प्रमुख निर्वाचित हुए। नागौर नगर परिषद में 23 निर्दलीय पार्षद सबसे बड़ा समूह थे, लेकिन सभापति पद भाजपा की संतोष ने जीता। मारवाड़-मूंडवा में आरएलपी की अलका और रियांबड़ी में निर्दलीय सुनील कुमार चौहान अध्यक्ष बने।

- नागौर नगर परिषद-संतोष, भाजपा
 - बासनी-शौकत अली, कांग्रेस
 - डेगाना-राधाकिशन, भाजपा
 - जायल-कमलेश, कांग्रेस
 - कुचेरा-तेजपाल, कांग्रेस
 - मारवाड़-मूंडवा-अलका, आरएलपी
 - मेड़ता सिटी-कंचनदेवी सांखला, भाजपा
 - मेड़ता रोड-तुलसी देवी, भाजपा
 - रियांबड़ी-सुनीलकुमार चौहान, निर्दलीय
- यह परिणाम बताता है कि नागौर की राजनीति भाजपा व कांग्रेस तक सीमित नहीं है। यहां क्षेत्रीय दल व स्थानीय चेहरे सत्ता के समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं।

टोंक शहर कांग्रेस का, जिले के आठ निकाय भाजपा के

टोंक जिले के दस निकायों में भाजपा ने आठ और कांग्रेस ने दो निकाय प्रमुख पद जीते।

टोंक नगर परिषद में कांग्रेस के पास 32 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत था। कांग्रेस के मयंक गोयल सभापति चुने गए। उनियारा में भी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया। शेष आठ निकाय भाजपा के खाते में गए।

- टोंक नगर परिषद-मयंक गोयल, कांग्रेस
- देवली-कजोड़ी देवी, भाजपा
- डिग्गी-अरविंद, भाजपा
- दूनी-अर्चना देवी, भाजपा
- लांबाहरिसिंह-सोनियाकुमारी स्वर्णकार, भाजपा
- मालपुरा-जिनेंद्रकुमार जैन, भाजपा
- निवाई-नरेंद्रकुमार शर्मा, भाजपा
- पीपलू-रमेश, भाजपा
- टोडारायसिंह-संत कुमार, भाजपा
- उनियारा-नरेशकुमार गुर्जर, कांग्रेस

निवाई में कांग्रेस 19 और भाजपा 18 पार्षदों के साथ दूसरे स्थान पर थी, फिर भी अध्यक्ष पद भाजपा ने जीत लिया। यह भी चुनाव बाद समर्थन जुटाने में भाजपा की बढ़त को दर्शाता है।

भाजपा की सबसे बड़ी सफलता- खंडित जनादेश को सत्ता में बदलना

- अजमेर संभाग के परिणाम का पहला चरण भाजपा को पार्षद सीटों में बढ़त देने वाला था। दूसरा चरण—निकाय प्रमुखों का चुनाव—उसके चुनाव प्रबंधन की सफलता साबित हुआ।
- अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन सिटी और नागौर जैसे कई निकायों में भाजपा स्पष्ट बहुमत में नहीं थी। वहीं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो वहीं निर्दलीय सबसे बड़ा समूह थे। इसके बावजूद भाजपा अपने उम्मीदवारों को महापौर अथवा सभापति बनवाने में सफल रही।
- कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका अजमेर रहा। डीडवाना-कुचामन में पांच पद और टोंक नगर परिषद में सत्ता हासिल करना उसकी उपलब्धि है, लेकिन अजमेर नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी महापौर नहीं बना पाना उसकी रणनीतिक कमजोरी बनकर सामने आया।

निर्दलीय जीते 321 सीटें, लेकिन सत्ता में सीधी हिस्सेदारी केवल एक पद

- संभाग में 321 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। यह कुल घोषित सीटों का लगभग 19 प्रतिशत है। इसके बावजूद सीधे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केवल रियांबड़ी नगरपालिका में अध्यक्ष पद जीता गया।
- हालांकि सत्ता में उनकी वास्तविक भूमिका इससे कहीं बड़ी रही। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, पीसांगन, मकराना, नागौर और कई अन्य निकायों में उन्हीं के समर्थन से प्रमुख चुने गए। यानी निर्दलीय स्वयं अधिक पदों पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि सत्ता किस दल को मिलेगी।

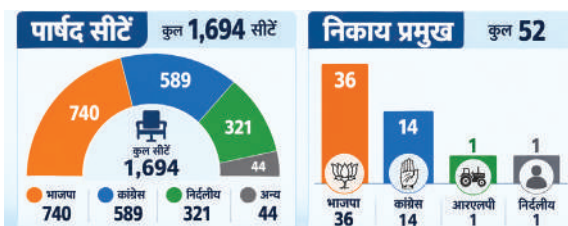
राजनीतिक संदेश

अजमेर संभाग के नगर निकाय चुनाव का परिणाम तीन स्पष्ट संदेश देता है।

पहला: छोटे शहरों और कस्बों में भाजपा का संगठनात्मक आधार मजबूत बना हुआ है। 740 पार्षद सीटें और 36 निकाय प्रमुख पद इसका प्रमाण हैं।

दूसरा: कांग्रेस ने अजमेर नगर निगम में 37 पार्षद जीतकर वापसी का संकेत जरूर दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सत्ता हासिल नहीं कर सकी। टोंक, मकराना और डीडवाना-कुचामन के पांच निकायों में उसका प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा, लेकिन समग्र सत्ता-समीकरण में वह भाजपा से काफी पीछे रह गई।

तीसरा: निर्दलीय पार्षद इस चुनाव के वास्तविक किंगमेकर साबित हुए। उन्होंने स्वयं केवल एक निकाय प्रमुख पद जीता, लेकिन अनेक शहरों में उनके समर्थन ने भाजपा अथवा कांग्रेस का बोर्ड बनवाया। पार्षद चुनाव में मतदाताओं ने कई जगह खंडित जनादेश दिया था। निकाय प्रमुखों के चुनाव ने उस खंडित तस्वीर को भाजपा के पक्ष में स्पष्ट सत्ता-समीकरण में बदल दिया। अजमेर संभाग का अंतिम निष्कर्ष यही है— जनता ने पार्षदों के स्तर पर विविध जनादेश दिया, लेकिन सत्ता के चुनाव में भाजपा का संगठन, रणनीति और निर्दलीयों को साथ लेने की क्षमता कांग्रेस पर भारी पड़ी।



अजमेर में 40-40 की बराबरी के बाद पच्ची से भाजपा के हेमंत सांखला बने उपमहापौर



अजमेर संभाग के नगर निगमों में उपमहापौर, नगर परिषदों में उपसभापति और नगरपालिकाओं में उपाध्यक्षों के चुनाव परिणामों ने कई निकायों में सत्ता-संतुलन को और स्पष्ट किया, जबकि कुछ स्थानों पर अध्यक्षीय चुनाव से अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिला।

अजमेर नगर निगम में उपमहापौर पद का मुकाबला सबसे रोमांचक रहा। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को 40-40 वोट मिले। बराबर मत आने के बाद पच्ची निकाली गई, जिसमें भाजपा के हेमंत सांखला विजयी रहे। इस तरह भाजपा ने महापौर के बाद उपमहापौर पद भी अपने पास रख लिया। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले महापौर चुनाव में भाजपा की अनामिका शर्मा को 43 और कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले थे। उपमहापौर चुनाव में भाजपा का आंकड़ा घटकर 40 और कांग्रेस का बढ़कर 40 हो गया। यानी महज 24 घंटे में तीन पार्षदों का मतदान रुख बदल गया।

भीलवाड़ा में भाजपा के राधेश्याम सोमानी निर्विरोध

भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर जसवंत कंवर के बाद भाजपा के राधेश्याम सोमानी उपमहापौर पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस तरह भीलवाड़ा निगम के दोनों प्रमुख पद भाजपा के खाते में गए। भाजपा के पास यहां 70 में से 45 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत है।

किशनगढ़ में भाजपा के मनेंद्र सिंह खंगारोत उपसभापति

किशनगढ़ नगर परिषद में भाजपा के मनेंद्र सिंह खंगारोत उपसभापति निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेन्द्र यादव को दस मतों से पराजित किया। इससे पहले भाजपा के राजकुमार सभापति बने थे। इस तरह किशनगढ़ नगर परिषद के सभापति और उपसभापति—दोनों पद भाजपा ने हासिल कर लिए।

ब्यावर में भाजपा के दीक्षांत हरचंदानी की जीत

ब्यावर नगर परिषद में भाजपा के दीक्षांत हरचंदानी उपसभापति निर्वाचित हुए। भाजपा पहले ही पुष्पा बल्लुआ को सभापति बनवा चुकी थी। स्पष्ट बहुमत से दूर रहने के बावजूद भाजपा ने ब्यावर में दोनों प्रमुख पद जीतकर निर्दलीयों और सहयोगी पार्षदों पर अपनी पकड़ साबित की।

टोंक में कांग्रेस की फरजाना सईद उपसभापति

टोंक नगर परिषद में कांग्रेस की फरजाना सईद ने 36 वोट हासिल कर उपसभापति पद जीता। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओम पांडे को 13 मतों से पराजित किया। कांग्रेस के मयंक गोयल पहले ही सभापति चुने जा चुके हैं। इस प्रकार टोंक नगर परिषद में सभापति और उपसभापति—दोनों पद कांग्रेस के पास चले गए।

अजमेर में निर्दलीय पावरफुल

अजमेर में पच्ची से भाजपा का उपमहापौर जरूर बन गया, लेकिन बराबर मतदान ने यह साबित कर दिया कि निगम के भीतर सत्ता का गणित स्थायी नहीं है। आने वाले समय में समितियों के गठन, बजट, विकास प्रस्तावों और महत्वपूर्ण मतदान के दौरान निर्दलीय पार्षद एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकते हैं।

भाजपा आगे, गुटबाजी से पिछड़ी कांग्रेस



अरविंद गुप्ता,

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

हाड़ौती के निकाय चुनावों में भाजपा का बूथ मैनेजमेंट और मजबूत संगठन उसकी बढ़त का आधार बना, जबकि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर बूथ प्रबंधन ने कई जगह उसके प्रदर्शन को प्रभावित किया।

हाड़ौती संभाग के चारों जिलों में संपन्न निकाय चुनाव में भाजपा ने अपनी अनंत विजय यात्रा जारी रखी। डबल इंजन की सरकार के बाद शहर की सरकार पर भी भाजपा का पलड़ा ही भारी रहा। हाड़ौती में 28 नगर निकायों में से 17 पर भाजपा, 10 पर कांग्रेस और एक बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी का बोर्ड बना है। स्थानीय निकाय चुनाव में जनदेश का वोट प्रतिशत देखें तो भाजपा पहले, कांग्रेस दूसरे, निर्दलीय तीसरे व आप पार्टी चौथे पायदान पर रही।

भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति, अनुभव और सूझबूझ के साथ निकाय चुनाव में बूथ मैनेजमेंट और संगठन को सबसे आगे रखा, जिससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। दूसरी ओर, कांग्रेस की कमजोर संगठन क्षमता, अंदरूनी गुटबाजी, बूथ मैनेजमेंट में समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी जैसे घटकों से अधिकांश सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।

अनंत चतुर्दशी पर्व पर कोटा नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने अपना विजयी डंका बजाया। भाजपा प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी 65 मतों से विजयी रही, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट मिल सके। नगर निगम के चुनाव में कुल 100 मतों से भाजपा के पास 57 और 2 निर्दलीय सहित 59 वोट थे। कांग्रेस के पास 39 व एक निर्दलीय सहित 40 वोट थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा प्रत्याशी को 6 वोट अधिक मिले। जाहिर है प्रदेश में सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस अब परस्पर गुटबाजी में बिखरने लगी है।

कारण स्पष्ट है, जनता ने कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण नगर निगम दोनों में कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन पिछले एक वर्ष में दोनों निगम में से एक महापौर सहित कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इससे वार्डों के विकास कार्य प्रभावित हुए। प्रदेश में भाजपा सरकार होने से पार्टी के पार्षदों को अप्रत्यक्ष फायदा मिला।

कोटा स्मार्ट सिटी है। इसके मूलभूत विकास कार्यों के लिए मोदी सरकार ने नगर निगम को पर्याप्त बजट दिया, लेकिन पांच वर्षों तक कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण में कांग्रेस बोर्ड ने शहर की सड़कों, सीवरेज, साफ-सफाई, पार्किंग और अतिक्रमण जैसे बुनियादी मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अपने कार्यकाल में कोटा में कई



उप महापौर विवेक राजवंशी को स्वागत करती नवनिर्वाचित महापौर अनुसुइया गोस्वामी। साथ में विधायक संदीप शर्मा एवं श्रीमती कल्पना देवी।

निर्दलीय बने किंगमेकर

प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों में प्रत्याशियों के चयन में अंदरूनी गुटबाजी सामने आती है, जिससे टिकट नहीं मिलने पर खफा होकर जमीनी और वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर जाते हैं। आम जनता उनके व्यवहार, उपलब्धता और कार्यशैली को देखकर वोट दे देती है। यही निर्दलीय जीतकर अपनी पार्टी के साथ या बाड़ेबंदी के खेल में बहुमत वाली पार्टी के साथ हो जाते हैं। ग्रामीण निकायों के बोर्ड में जहां 1-1 वोट से हार-जीत का फैसला रहा, वहां निर्दलीय किंगमेकर बनकर उभरे हैं।

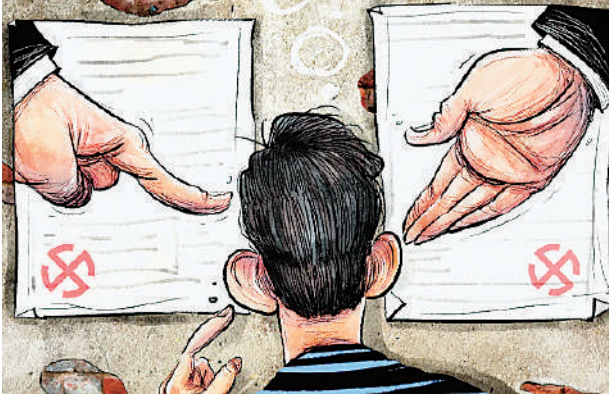
कुछ चौंकाने वाली बातें

निकाय चुनाव में यह पहला अवसर है जब कोटा जिला कांग्रेस मुक्त हो गया है। इसी तरह, पहली बार बारां नगर परिषद पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर सबको चौंका दिया। हाड़ौती की कुछ नगरपालिकाओं में निर्दलीयों ने जीत के समीकरण बिगाड़कर कम सीटें जीतने वाली पार्टी का बोर्ड बनवा दिया। कोटा जिले की इटावा नगर पालिका में भाजपा ने निर्दलीय पार्षद निर्मला नागर को अपना सिंबल देकर चेयरपर्सन बना दिया। जबकि यहां भाजपा को 14, कांग्रेस को 16 और 5 निर्दलीय को जीत मिली है। ऐसा ही सुकेत में हुआ जहां 25 वार्डों में से भाजपा 10, कांग्रेस 11 व 4 पर निर्दलीय जीते हैं। यहां भाजपा ने कमल खिला दिया। नगर निगम में मेयर, नगर परिषद व नगर पालिका में चेयरमैन बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों ने विजेता पार्षदों की बाड़ाबंदी की। कहीं पावर तो कहीं पैसा बांटने के आरोप भी लगे।

प्लाई ओवर व सुंदर चौराहे, हरे भरे डिवाइडर, चौड़ी सड़कें, नए लिंक रोड, पार्किंग स्थल, चम्बल रिवर फ्रंट, दर्शनीय सिटी पार्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कैटल मुक्त कोटा के लिए देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना जैसे विकास कार्यों का जाल फैलाया, जिससे कोटा की तस्वीर बदल गई। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद नगर निगम में कांग्रेस का इंजन ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ, भाजपा ने निगम चुनाव में जीत की रणनीति बनाकर प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ स्तर के मैनेजमेंट तक जमीनी कार्य किया। इस प्रभावी व्यूह रचना में कोटा-बूंदी के सांसद एवं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एवं भाजपा नेता हरिकृष्ण बिरला की भूमिका सबसे अहम रही।

आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार, कोटा नगर निगम की 100 सीटों के लिए 67.66 प्रतिशत मतदाताओं ने शहर की सरकार चुनने में रूचि दिखाई। जबकि 32.34 प्रतिशत शहरी मतदाताओं ने किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने में रूचि नहीं ली। कोटा में भाजपा को 2,83,321 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2,70,013 वोट मिले। अर्थात् भाजपा को 13,308 वोट अधिक मिले। बूंदी में भाजपा को 60,147 वोट एवं कांग्रेस को 56,057 वोट मिले। यानी भाजपा को 4,069 वोट अधिक मिले। जबकि झालावाड़ में कांग्रेस 6518 वोट एवं बारां में 7324 वोट लेकर आगे रही। बारां में आम आदमी पार्टी ने 34,282 वोट हासिल कर पहली बार अपना बोर्ड बनाकर सबको चौंका दिया।

दांव पर रही इनकी साख



कोटा-बूंदी जिले में सांसद व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा व कल्पना देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, रामनारायण मीणा, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, महेंद्र राजोरिया, विधायक चेतन पटेल, शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष भानुप्रताप, नईमुदीन गुड्डू, बारां जिले में पूर्व मंत्री व अंता से विधायक प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन, भाजपा विधायक प्रतापसिंह सिंघवी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झालावाड़-बारां क्षेत्र से भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह जैसे कई नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की साख भी दांव पर लगी थी। इसमें झालावाड़ को छोड़कर अन्य सभी जगह भाजपा नेता अपनी रणनीति में सफल साबित हुए। जबकि निकाय चुनाव के दौरान बयानबाजी से बड़े-बड़े दावे करने वाले कांग्रेस नेताओं को नतीजों में मुंह की खानी पड़ी है।

कहां किसका बोर्ड बना



निकाय चुनाव ने दिखाया, शहर का मतदाता अलग सोचता है

विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाता अक्सर बड़े राजनीतिक मुद्दों, सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर मतदान करता है, लेकिन निकाय चुनाव की तस्वीर कुछ अलग होती है। यहां मतदाता के सामने उसके वार्ड की सड़क, नाली, सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट और पार्श्व की उपलब्धता जैसे सवाल अधिक सीधे होते हैं। हाड़ौती के निकाय चुनाव के नतीजों में भी स्थानीय राजनीति की इसी अलग प्रकृति के संकेत दिखाई देते हैं।



एक ही जिले और लगभग समान राजनीतिक माहौल के बावजूद अलग-अलग निकायों में अलग परिणाम सामने आए। कहीं भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला तो कहीं कांग्रेस ने अपना आधार बचाए रखा। कुछ जगह निर्दलीयों ने पूरा समीकरण बदल दिया। बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी का बोर्ड बनना भी इसी स्थानीय राजनीतिक व्यवहार का उदाहरण है। यह परिणाम बताता है कि निकाय चुनाव में मतदाता हमेशा दो प्रमुख दलों के बीच ही चुनाव नहीं करता, बल्कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विकल्प को भी महत्व दे सकता है।

निकाय चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान की भूमिका भी बड़ी होती है। वार्ड का मतदाता अक्सर उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वह उसके सामाजिक व्यवहार, उपलब्धता और अपने छोटे-बड़े काम कराने की क्षमता को भी देखता है। यही कारण है कि बड़े राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न के बावजूद स्थानीय समीकरण कई बार अलग दिशा में चले जाते हैं। किसी वार्ड में पार्टी का मजबूत आधार होने के बावजूद उसका प्रत्याशी हार सकता है और किसी दूसरे वार्ड में अपेक्षाकृत कमजोर माने जाने वाला उम्मीदवार व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर जीत हासिल कर सकता है।

हाड़ौती के चुनाव परिणामों में मतदान प्रतिशत भी चर्चा का विषय रहा। कोटा नगर निगम में 67.66 प्रतिशत मतदान हुआ, यानी करीब एक-तिहाई मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। शहर की सरकार चुनने में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी नहीं होना राजनीतिक दलों के लिए भी सवाल है। निकाय चुनाव में आमतौर पर वही मतदाता अधिक सक्रिय दिखाई देता है, जिसका स्थानीय मुद्दों से सीधा संबंध होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने चुनौती केवल समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि उन शहरी मतदाताओं को भी जोड़ने की है जो स्थानीय चुनावों से दूरी बनाए रखते हैं।

हाड़ौती के निकाय चुनावों का एक संदेश यह भी है कि शहरों की राजनीति को केवल बड़े नेताओं और बड़ी चुनावी सभाओं से नहीं समझा जा सकता। वार्ड स्तर का संपर्क, प्रत्याशी की छवि और स्थानीय मुद्दे यहां अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में जिस दल के पार्श्व जनता के बीच उपलब्ध रहेंगे और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार दबाव बनाएं, उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होने की संभावना रहेगी। निकाय चुनाव इसलिए केवल बोर्ड बनाने का चुनाव नहीं, बल्कि शहर के मतदाता के साथ लगातार संवाद का भी चुनाव है।

भाजपा भारी, कांग्रेस ने भी दी टक्कर

उदयपुर संभाग के 28 निकायों में भाजपा ने 18 पर बोर्ड बनाकर बढ़त कायम रखी, जबकि कांग्रेस को 9 निकाय मिले। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का प्रदर्शन सीमित रहा, हालांकि कुछ जगह उन्होंने समीकरण बदले।



राजेश कसेरा,

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

श हरी निकायों में सरकार बनाने में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे रही।

भजनलाल शर्मा सरकार ने 309 निकायों में वन नेशन, वन इलेक्शन के चुनावी वादे को साकार कर बड़ी सफलता भी अर्जित की। चुनावों के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने जीत-हार के कारणों, सियासी समीकरणों की पड़ताल और धरातल पर बनाई गई रणनीति के मूल्यांकन में जुट गई। दोनों दलों के शीर्ष पदाधिकारी इस मंथन में जुट गए कि कहां और कैसे चूक हुई? जिन निकायों को जीतने का पूरा भरोसा था, वहां मात किस तरह से खा गए। साथ ही गांवों में अपनी सरकार बनाने की भाग-दौड़ भी शुरू कर दी। भाजपा निकाय चुनाव की तरह पंचायती राज चुनाव में भी जीत का परचम लहराना चाहेगी।

तइधर, राज्य के दोनों प्रमुख दलों के उदयपुर संभाग के रिपोर्ट कार्ड को खंगालेंगे तो सामने आएगा कि 28 निकायों के लिए हुए चुनावी संग्राम में शहरी मतदाताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर ही अपना भरोसा जताया। संभाग के सात जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सतलुबर में 18 निकायों पर भाजपा ने बंपर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 निकाय आए तो एक निकाय निर्दलीय के खाते में गया। संभाग में चुनाव लड़ने वाले क्षेत्रीय दलों और तीसरे मोर्चे को जनता ने सिरे से नकार दिया। संभाग में सक्रिय भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने 5 जिलों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, पर शहरी निकाय की जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मजबूती से आगे बढ़ी जनजाति अंचल की इस पार्टी को निकाय चुनावों में कहीं भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई।



बाएं महापौर पारस सिंघवी और दाएं उपमहापौर दिनेश भट्ट।

64 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन

प्रदेश के दक्षिण राजस्थान के इस संभाग का अधिकांश हिस्सा आदिवासी मतदाताओं से घिरा है। यहां के चुनावी मुद्दे अन्य अंचलों से बहुत अलग हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भाजपा सरकार के तीन साल के काम-काज पर आमजन का समर्थन हासिल करने में सफल रही। तभी तो निकाय चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड को देखें तो भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में मतदाताओं का दोगुना भरोसा हासिल किया। संभाग के सातों जिलों में भाजपा ने 64.3 प्रतिशत निकायों में जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस की हिस्सेदारी 32.1 प्रतिशत रही। आदिवासी अंचल वाले इस संभाग में अध्यक्ष पदों के स्तर पर भी कांग्रेस से कहीं आगे भाजपा रही।

उदयपुर- लगातार 7वीं लहराया भगवा परचम

भाजपा के सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले उदयपुर में पार्टी ने लगातार 7वीं बार प्रचंड जीत दर्ज की। 80 वार्डों के लिए हुए मुकाबले में भाजपा के खाते में 53 सीटें गईं तो कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें मिल पाईं। तीन वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए तो एक वार्ड माकपा के उम्मीदवार ने जीता। पार्टी का मजबूत कैडर होने का लाभ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में भी मिला। पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी पर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताकर उनके हाथ में नगर निगम के मुखिया पद की कमान सौंपी तो दिनेश भट्ट को उप महापौर का जिम्मा सौंपा। चुनावों में संगठन और संघ का संतुलन भी देखने को मिला। संगठन की पंसद पर मेयर को चुना गया तो संघ ने भट्ट के नाम को आगे बढ़ाया। इस तरह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल उदयपुर को और निखारने और संवारने का जनादेश एक बार फिर नागरिकों ने भाजपा को सौंपा।

चित्तौड़गढ़ – पांच निकायों में भाजपा का बोर्ड

संभाग के सभी जिलों की तुलना करें तो चित्तौड़गढ़ जिले की 7 निकायों में इस बार चुनाव हुए। इनमें भाजपा ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ा। जिले के 5 निकायों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, कपासन, रावतभाटा और बेगूं में भाजपा ने जीत का भगवा परचम लहराया तो बड़ी सादड़ी और आकोला में कांग्रेस का बोर्ड बना। राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम दक अपने घर बड़ी सादड़ी में पार्टी की साख नहीं बचा पाए।

उदयपुर जिले में कांग्रेस का इंका

मेवाड़-वागड़ अंचल के संभाग मुख्यालय उदयपुर में तो भाजपा ने लगातार 7वां बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जिले की 5 नगरपालिकाओं के चुनावों में भाजपा का परिणाम चिंताजनक रहा। कानोड़ और भींडर में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया तो फतहनगर में बहुमत होने के बावजूद भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने भाजपा के घर में सेंध लगाकर कांग्रेस के समर्थन से बड़ी जीत हासिल की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोट के पुत्र और भाजपा के पालिकाध्यक्ष रहे राजेश चपलोट पार्टी से बगावत करके अपनी पत्नी ममता चपलोट को अध्यक्ष बनाने में सफल रहे।



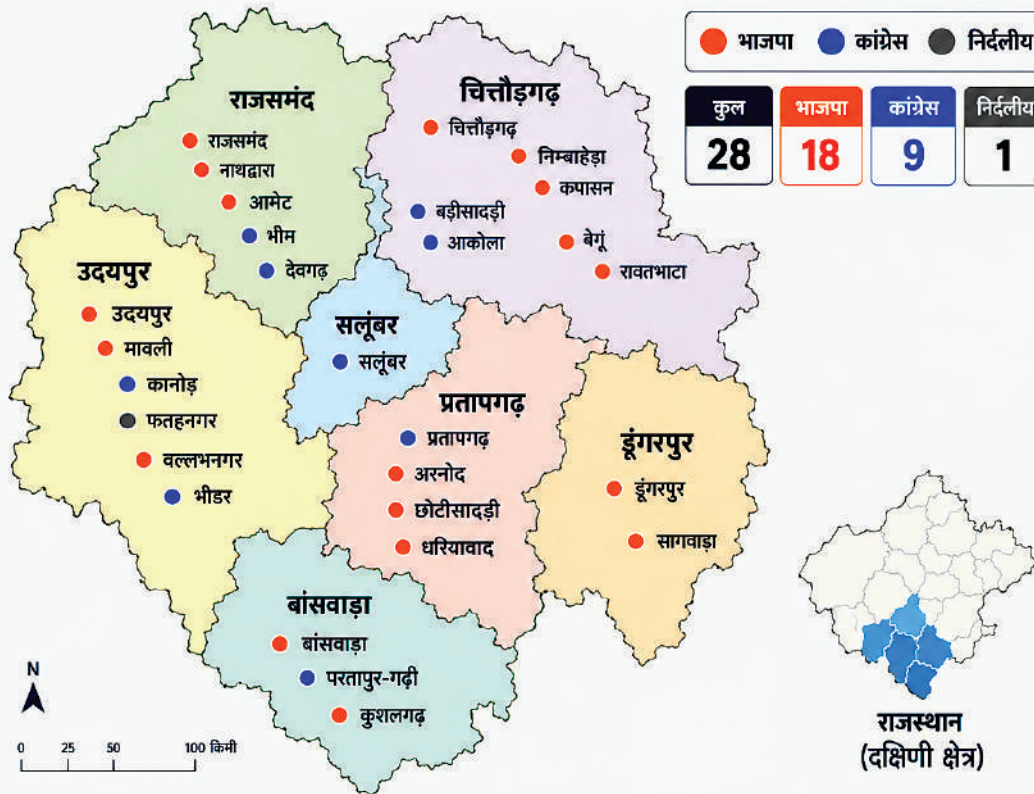
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा घर में नहीं बचा पाए साख



जनजाति अंचल के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में भाजपा इस बार अपना निकाय बोर्ड बनाने में विफल रही। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा अपने घर में पार्टी की साख नहीं बचा पाए। 40 वार्डों की नगर परिषद में कांग्रेस ने आधी सीटें जीतीं। जबकि भाजपा 17 पर सिमट गई। तीन सीटें निर्दलीय के खाते में गईं। राजस्व मंत्री मीणा ने निर्दलीय को साधने में पूरा जोर लगाया, लेकिन वे कांग्रेस के मजबूत किले को भेद नहीं पाए और कांग्रेस ने ज्योति सोनी को सभापति बना दिया। इसी तरह से उप सभापति के चुनाव में भी भाजपा पीछे छूट गई और कांग्रेस की रेखा जैन ने 8 वोटों बड़े अंतर से भाजपा के विजय जटिया को हराया। जिले के बाकी तीनों नगर पालिकाओं छोड़ी सादड़ी, अरनोद और धरियावाद में भाजपा अपना बोर्ड बना पाई।

उदयपुर संभाग के चुनावी परिणाम

28 निकायों का पार्टीवार परिणाम



सात मंत्रियों के क्षेत्रों में नहीं बना भाजपा बोर्ड

चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी नगरपालिका में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सिरौही में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और जालोर में मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा निकाय प्रमुख नहीं बना सकी। खुद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले पाली में भी भाजपा बुरी तरह से चुनाव हारी। हालांकि जोड़-तोड़ के दम पर भाजपा ने वहां अपना मेयर बना लिया। इसी तरह नावां में राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी, दूदू में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जायल में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार के विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा निकाय प्रमुख का पद हासिल नहीं कर सकी।



भारत आदिवासी पार्टी की नहीं गली दाल

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनजाति अंचल में मजबूत विकल्प बनकर उभरी भारत आदिवासी पार्टी को शहरी निकाय चुनावों में मतदाताओं को समर्थन नहीं मिल पाया। भारतीय ट्राइबल पार्टी से टूटकर राजकुमार रोट के नेतृत्व में बनी बीएपी ने एक सांसद और 4 विधायक बनाकर भाजपा और कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। जनजाति अंचल में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही पार्टी को निकाय चुनाव में पूरा भरोसा था कि वे सलूबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण के क्षेत्रों में दमदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शहरी मतदाताओं को बीएपी पार्टी के उम्मीदवार नहीं भाए और केवल 8 वार्डों में जीत दर्ज कर पाए।

बेअसर होते परम्परागत गढ़



मणिमाला शर्मा,
वरिष्ठ पत्रकार एवं
राजनीतिक विश्लेषक

रा जस्थान के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सूबे की भावी राजनीति का वो 'एक्सरे' हैं जिसने कई दिग्गजों के सियासी स्वास्थ्य की पोल खोल दी है। विशेषकर पूर्वी सिंहद्वार कहे जाने वाले भरतपुर संभाग (भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर) के जनादेश ने जयपुर के सत्ता गलियारों में वैसी ही हलचल मचा दी है, जैसी चंबल में कभी बागियों की आहत

भरतपुर संभाग का यह जनादेश सत्ता के अहंकार पर जनता का 'लोकल हंटर' है। मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि राज्य के वीआईपी दौरो से नहीं, बल्कि वार्ड की नालियों और टूटी सड़कों को दुरुस्त करने से ही दिल जीते जाते हैं।

से मचती थी। मुख्यमंत्री के गृह संभाग से आई यह राजनीतिक बयार साफ संदेश दे रही है कि जनादेश न तो किसी दल की जागीर है और न ही सत्ता का रसूख हमेशा जीत की गारंटी होता है। बारीकी से देखें तो यह चुनाव 'सत्ता की निरंतरता' का नहीं, बल्कि 'जमीनी कार्यकर्ता की उपेक्षा पर जनता के खुदर विद्रोह' का जीवंत दस्तावेज प्रतीत होता है।

पांच जिलों की पांच कहानियां और इनसाइडर गेम



मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण निकाय चुनावों में भरतपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, लेकिन वहां मतदाताओं ने दोनों प्रमुख दलों को ऐसा पटका कि उनके सिंबल हाफने लगे। भरतपुर नगर निगम के कुल 65 वार्डों में 36 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा राजनीतिक गाल पर कराता मचा था। इन चुनावों में भाजपा 20 और कांग्रेस महज 7 सीटों पर रंगती नजर आई।

चुनावी नतीजों में भले ही भाजपा पिछड़ गई थी, लेकिन 'साम-दाम-दंड-भेद' की कला में माहिर पार्टी ने सत्ता के हंटर से खेल पलट दिया। गृह राज्य मंत्री की घेराबंदी के आगे निर्दलीयों का गुट बिखर गया। सबसे मजबूत निर्दलीय दावेदार विचित्रा सिंह के कदम पीछे खींचते ही भाजपा की अनुराधा सिंह भरतपुर की निर्विरोध महापौर बन गई और उन्होंने तुरंत शपथ भी ले ली। यहां जनता ने भले ही निर्दलीयों पर भरोसा जताया, लेकिन कुर्सी पर भाजपा का काबिज होना इस चुनाव की सबसे बड़ी विडंबना ही साबित हुई है।



करौली नगर परिषद के 55 वार्डों ने यहां की राजनीति के अंतर्विरोधों को पूरी तरह नंगा कर दिया। कांग्रेस यहां 28 सीटें जीतकर बहुमत की दहलीज पर तो खड़ी थी, लेकिन 15 निर्दलीयों और भाजपा की 11 सीटों ने खेल पेचीदा कर दिया था।

भारी गुणा-भाग के बाद कांग्रेस ने निर्दलीयों को साधकर करौली में सुनील सैनी को अपना सभापति तो बना लिया, लेकिन इस 'सफलता' के पीछे गहरी सांगठनिक कमजोरी छिपी है। अगर टिकट वितरण में स्थानीय कार्यकर्ताओं की जेब देखने की बजाय उनकी वफादारी देखी जाती, तो कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। करौली के क्षत्रप अब महलों से बाहर नहीं निकले, तो अगली बार कांग्रेस को यह बैसाखी भी नसीब नहीं होगी। इस बार चुनाव में बड़े-बड़े जातीय ठेकेदारों के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने भाजपा को अपनों की 'बाड़ेबंदी' करने पर मजबूर कर दिया और कांग्रेस को निर्दलीयों की बैसाखी थमा दी।



बाघों की इस भूमि ने सत्ताधारी दल भाजपा को थोड़ी राहत जरूर दी थी लेकिन यह जीत भी उतनी मखमली नहीं रही जितनी जयपुर में बैठे दिग्गज रणनीतिकार मान रहे थे।

सवाई माधोपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में से भाजपा ने 33 सीटें हासिल कर जादुई आंकड़ा (31) पार किया। कांग्रेस 18 और निर्दलीय 9 सीटों पर समिट गए।

स्पष्ट बहुमत के दम पर सवाई माधोपुर नगर परिषद की कुर्सी पर भाजपा की मेवा चौधरी सभापति बैठ तो गई हैं, लेकिन रणथंभौर के इस दुर्ग में अंदरूनी खींचतान इस कदर हावी थी कि वोटिंग के आखिरी मिनट तक भाजपा नेताओं के हलक में जान अटकी रही। अपनों के ही भीतरघात का डर इस कदर था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखना पड़ा।



उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे इस जिले ने दोनों बड़ी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। मजे की बात ये रही कि यहां दलों के झंडे नहीं, स्थानीय क्षत्रपों के डंडे चले।

धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में कांग्रेस 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि निर्दलीयों ने 19 सीटें जीतकर भाजपा (11 सीटें) को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। धौलपुर में स्थानीय नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई इतनी नग्न थी कि पार्टियों के सिंबल बेअसर हो गए। अंततः कांग्रेस समर्थित खेमे ने निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश गर्ग की मनुहार करके उन्हें धौलपुर में सर्वसम्मति से निर्विरोध सभापति चुनवा लिया। 19 निर्दलीयों की यह धमक बताती है कि चंबल की राजनीति अब जयपुर के रिमोट कंट्रोल से नहीं, बल्कि स्थानीय रसूखदारों के इशारों पर नाचेगी।



भरतपुर से अलग होकर बने डीग जिले की नगरपालिकाओं में भी 60 फीसदी से अधिक सीटों पर बागियों और निर्दलीयों का कब्जा था। नतीजों में यहां की अधिकांश नगरपालिकाओं में निर्दलीयों ने या तो स्वयं की सरकार बनाई है या फिर सत्ताधारी भाजपा को समर्थन देकर अपनी शतों पर बोर्ड गठित करवाया है। इसने साफ कर दिया कि नए जिले का गठन करने का झुनझुना थमाने मात्र से वोट बैंक सुरक्षित नहीं होता, जनता को धरातल पर काम चाहिए।

सामाजिक अंतर्धारण:

बेअसर हुए जातीय टेकेदार

पूर्वी राजस्थान की राजनीति को जो लोग सिर्फ जाट, गुर्जर, मीणा और दलित के चरम से देखते हैं, उन्हें इस चुनाव ने नया सबक सिखाया है। बड़े चुनावों में भले ही ये जातीय ध्रुवीकरण काम कर जाता हो, लेकिन इस वार्ड स्तर के चुनावों में 'माइक्रो-कास्ट इंजीनियरिंग' हावी रहती है। जब दोनों दलों ने एक ही जाति के मोहरे मैदान में उतारे, तो मतदाताओं ने जाति के नाम पर वोट देने के बजाय उस उम्मीदवार को चुना जो उनके मोहल्ले की समस्या सुलझाने में सक्षम था।

बसपा का सूफड़ा साफ

सोशल इंजीनियरिंग का दावा करने वाली बसपा करौली और धौलपुर जैसे अपने ही गढ़ों में पूरी तरह हाफ गई। दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक ने समझ लिया कि अपने बीच के जिताऊ निर्दलीय को ताकत दी जाए ताकि सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और हुआ भी यही।

बुनियादी मुद्दों की गूंज:

'नारे' हारे, 'नाले' जीते

यह चुनाव राष्ट्रवाद या राज्य सरकार की उपलब्धियों पर नहीं लड़ा गया। यह चुनाव लड़ा गया भरतपुर की बदहाल सीवरेज व्यवस्था, धौलपुर की टूटी सड़कें, करौली का पेयजल संकट और सवाई माधोपुर की बदहाल सफाई व्यवस्था पर। जनता मंत्रियों के भाषणों से अघा चुकी थी। उसने साफ कह दिया 'हमें बड़ी योजनाएं बाद में देना, पहले हमारे घरों के आगे भरा गंदा पानी साफ करवाओ, सीवरेज के खुले मेनहोल में फेरो कवर लगाओ, सड़कों के गड्ढे भरो आदि।'

रिसॉर्ट पॉलिटिक्स के

साए में लोकतंत्र

भरतपुर संभाग की शहरों की सरकार की अंतिम तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। भले ही भरतपुर नगर निगम और सवाई माधोपुर में भाजपा ने और धौलपुर-करौली में कांग्रेस ने अपने बोर्ड बना लिए हैं, लेकिन लोकतंत्र के माथे पर 'बाड़ेबंदी' और अन्य विकल्प की कालिख साफ दिखाई दे रही है। होटलों और रिसॉर्ट्स से सीधे पोलिंग बूथ तक लाए गए पार्श्वों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही ताज पार्टियों के सिर सजा हो, लेकिन इस जंग का असली 'सिकंदर' आम मतदाता और बागी कार्यकर्ता ही हैं। जयपुर में बैठी सरकार को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि पूर्वी सिंहद्वार की जनता बदलाव के मूड में है।

भरतपुर (भरतपुर नगर निगम)

36 निर्दलीय	20 भाजपा	7 कांग्रेस	1 BSP	1 RLP
----------------	-------------	---------------	----------	----------

घोषित 65 / 65 वार्ड



नव-निर्वाचित मेयर
अनुराधा सिंह
(भाजपा - निर्विरोध)

करौली (करौली नगर परिषद)

28 कांग्रेस	15 निर्दलीय	11 भाजपा	1 BSP
----------------	----------------	-------------	----------

घोषित 55 / 55 वार्ड



नव-निर्वाचित मेयर
सुनील सैनी
(कांग्रेस - निर्दलीयों के सहयोग से)

सवाई माधोपुर (सवाई माधोपुर नगर परिषद)

33 भाजपा	18 कांग्रेस	9 निर्दलीय
-------------	----------------	---------------

घोषित 60 / 60 वार्ड



नव-निर्वाचित मेयर
मेवा चौधरी
(भाजपा - पूर्ण बहुमत)

धौलपुर (धौलपुर नगर परिषद)

27 कांग्रेस	19 निर्दलीय	11 भाजपा	3 BSP
----------------	----------------	-------------	----------

घोषित 60 / 60 वार्ड



नव-निर्वाचित मेयर
गिरीश गर्ग
(निर्दलीय - निर्विरोध)

डीग (कामां, कुम्हेर, नगर आदि नगरपालिकाएं)

स्थिति: भाजपा कमजोर, कांग्रेस पिछड़ी, 60% से अधिक सीटों पर स्थानीय बागी व निर्दलीय अध्यक्ष निर्वाचित।

पर्दे के पीछे का खेल

भरतपुर में 'सत्ता के चाणक्य' का जाल और सत्ता की जंग

भरतपुर नगर निगम का मेयर चुनाव किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा रहा है। 36 निर्दलीयों के प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस समर्थित खेमे ने पूर्व मेयर की पत्नी विचित्रा सिंह को आगे कर बाजी मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन तभी जयपुर से रिमोट कंट्रोल सक्रिय हुआ। स्थानीय मंत्रियों ने कमान संभाली और पार्टी के पुराने सिपहसालार की पत्नी अनुराधा सिंह के लिए बिसात बिछाई गई। सत्ता के दबाव और रणनीतिक चक्रव्यूह में विचित्रा सिंह को नाम वापसी के आखिरी लम्हों में मैदान छोड़ना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि मात्र 20 पार्श्वों वाली भाजपा ने 36 निर्दलीयों की आंखों में धूल झोंककर अनुराधा सिंह को निर्विरोध मेयर बनवा दिया। देखा जाए तो यह पूरी तरह जनता के मैडेट को सत्ता के प्रभाव से प्रभावित करने का क्लासिक उदाहरण है।

धौलपुर: कांग्रेस की 'गंभीर' कूटनीति, भाजपा का आत्मसमर्पण

धौलपुर नगर परिषद का क्लाइमेक्स संभाग में सबसे अनूठा रहा। यहां कांग्रेस 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। भाजपा महज 11 सीटों पर टिकी थी। यहां असली चाणक्य नीति निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश गर्ग ने चली। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस के स्थानीय दिग्गजों और असंतुष्ट खेमों के साथ ऐसी 'गंभीर कूटनीति' की कि कांग्रेस ने अपनी जगह एक निर्दलीय चेहरे को ताज सौंपना स्वीकार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि 11 सीटों वाली भाजपा और 19 निर्दलीयों के दूसरे गुट ने इस चक्रव्यूह के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया, जिसके चलते गिरीश गर्ग बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से निर्विरोध सभापति चुन लिए गए। चंबल के बीहड़ों के इस शांत राजनीतिक तख्तापलट ने साबित कर दिया कि जब सिंबल बेअसर होते हैं, तो स्थानीय रसूख ही 'माई-बाप' बनता है।

बीकानेर में कांग्रेस की वापसी

बीकानेर में 12 साल बाद कांग्रेस ने निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि चूरु में भाजपा मजबूत रही। हनुमानगढ़ में निर्दलीयों और श्रीगंगानगर में बंटे हुए जनादेश ने दोनों प्रमुख दलों के सामने चुनौती रखी। पूरे संभाग में स्थानीय समीकरण प्रभावी रहे।



राकेश आचार्य

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

बीकानेर संभाग के निकाय चुनावों ने भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले की एकरूप तस्वीर पेश करने के बजाय अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सियासी समीकरण सामने रखे हैं। बीकानेर में 12 साल बाद कांग्रेस ने निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर एक बार फिर से खुद को साबित करने का प्रयास किया है। वहीं चूरु जिले में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत रहा। हनुमानगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों के सामने चुनौती खड़ी की, जबकि श्रीगंगानगर में भी कई निकायों में जनादेश बंटा हुआ नजर आया। कुल मिलाकर परिणाम बताते हैं कि शहरी निकाय चुनाव में दलों के पारंपरिक प्रभाव के साथ स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय समीकरण भी महत्वपूर्ण रहे।

बीकानेर में भाजपा को बड़ा झटका

जिले के निकाय चुनावों में इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। छह नगर पालिकाओं और एक निगम के चुनाव में बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं 12 साल बाद कांग्रेस निगम में अपना महापौर बनाने में सफल हुई, जबकि उपमहापौर का चुनाव भाजपा के पक्ष में गया। इस परिणाम ने दोनों दलों के सामने स्थानीय स्तर पर संगठन और राजनीतिक समीकरणों को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं।

12 साल बाद कांग्रेस का महापौर

बीकानेर नगर निगम में पिछले दो चुनावों से लगातार भाजपा का बोर्ड था और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला उम्मीदवार थे, जबकि भाजपा ने डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के 42 और भाजपा के 27 पार्षद निर्वाचित हुए। महापौर चुनाव में कांग्रेस के अनिल कल्ला को 50 वोट मिले, जबकि भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत को 30 वोट मिले।



बीकानेर महापौर - अनिल कल्ला



बीकानेर उप महापौर - पंकज गहलोत

बहुमत के बावजूद उपमहापौर भाजपा के खाते में

42 पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद उपमहापौर के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की प्रत्याशी नसीम बानो को 38 मत मिले, जबकि भाजपा के पंकज गहलोत को 40 मत मिले। भाजपा के पास 27 पार्षद थे, ऐसे में उसके प्रत्याशी को अपने संख्याबल से 13 अधिक मत मिले। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी को उसके 42 पार्षदों की संख्या से चार मत कम मिले। एक मत नोटा में गया और एक मत निरस्त हुआ। गुप्त मतदान होने के कारण अतिरिक्त मत किस खेमे से आए, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। परिणाम ने बीकानेर निगम में दोनों दलों के बीच बने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को जरूर चर्चा में ला दिया।

कोर वोटर नहीं संभाल सकी भाजपा

निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निगम क्षेत्र में कमजोर रहा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में रोड शो किया। इस चुनाव में कांग्रेस ने बीकानेर पश्चिम के 39 वार्डों में 23 और पूर्व के 41 वार्डों में 19 सीटें जीतीं। भाजपा को पश्चिम में 10 और पूर्व में 17 सीटें मिलीं। इन परिणामों से भाजपा के पारंपरिक मतों के बिखराव के संकेत मिले।

भाजपा के कई प्रमुख चेहरे हारे

इस निकाय चुनाव में भाजपा के कई प्रमुख चेहरे और महापौर पद के दावेदार माने जाने वाले उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। वार्ड 73 से भाजपा के दीपक पारीक को कांग्रेस के अनिल कल्ला ने 800 से अधिक मतों से हराया। वार्ड 14 से पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित भी करीब 400 मतों से चुनाव हार गईं। इसी तरह वार्ड 32 से भूपेंद्र शर्मा, वार्ड 62 से गोपाल अग्रवाल और वार्ड 28 से मधु सुराणा को भी हार का सामना करना पड़ा।

जिले की पालिकाओं में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर

जिले की छह नगर पालिकाओं के परिणाम में कांग्रेस को केवल देशनोक में स्पष्ट बहुमत मिला। देशनोक में कांग्रेस को 15, भाजपा को 7 और निर्दलीयों को 3 सीटें मिलीं। नोखा में माकपा समर्थित विकास मंच ने 29 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यहां भाजपा को 13 और निर्दलीयों को 3 सीटें मिलीं।

लूणकरणसर में भाजपा को 23, कांग्रेस को 11 और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। खाजूवाला में भाजपा को 11, कांग्रेस को 8 और एक सीट निर्दलीय को मिली। श्रीदुंगरगढ़ में कांग्रेस 15 सीटों के साथ सबसे आगे रही, जबकि भाजपा को 13, विकास मंच को 9, माकपा को एक और निर्दलीयों को 2 सीटें मिलीं। नापासर में भाजपा को 8, कांग्रेस को 7, निर्दलीयों को 6 और आरएलपी को 2 सीटें मिलीं, जबकि दो सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इन परिणामों से साफ है कि बीकानेर निगम में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद जिले की छोटी निकायों में भाजपा का प्रभाव बना रहा।

चूरु में भाजपा मजबूत

30

भाजपा

24

कांग्रेस

6

निर्दलीय

घोषित **60 / 60** वार्ड

बीकानेर के मुकाबले चूरु जिले में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। जिले के 11 निकायों के 430 वार्डों में भाजपा ने 186, कांग्रेस ने 161 और निर्दलीयों ने 81 सीटें जीतीं, जबकि दो सीटें आरएलपी के खाते में गईं।

चूरु नगर परिषद में भाजपा को 30, कांग्रेस को 24 और निर्दलीयों को 6 सीटें मिलीं। सुजानगढ़ में भाजपा ने 31 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। सरदारशहर में भाजपा 25 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। रतनगढ़ में भाजपा को 21, तारानगर में 18 और बीदासर में 16 सीटें मिलीं। सादुलपुर में कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे आगे रही और निर्दलीयों को 14 सीटें मिलीं। रतननगर में कांग्रेस को 14 और साहवा में 11 सीटें मिलीं। छपर में भाजपा को 12, कांग्रेस को 9 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिलीं। राजलदेसर में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 14-14 सीटें मिलीं, जबकि आरएलपी को 2 और निर्दलीयों को 5 सीटें मिलीं।

हनुमानगढ़ : निर्दलीयों ने बिगाड़ा गणित



हनुमानगढ़ जिले में भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार सबसे प्रभावी रहे। जिले के आठ निकायों के 290 वार्डों में निर्दलीयों ने 133 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 91, भाजपा के खाते में 64 और माकपा के खाते में 2 सीटें आईं।

हनुमानगढ़ नगर परिषद में ही निर्दलीयों ने 34 सीटें जीतकर दोनों प्रमुख दलों को पीछे छोड़ दिया। यहां भाजपा को 15 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं। भादरा में 21 सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं। संगरिया में भी निर्दलीय सबसे आगे रहे, जबकि रावतसर में निर्दलीयों ने 18 सीटों के साथ बढ़त बनाई। नोहर में कांग्रेस ने 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई, लेकिन यहां भी 18 निर्दलीय पार्षद चुने गए। पीलीबंगा में भाजपा 18 सीटों के साथ सबसे आगे रही। टिब्बी में 11 निर्दलीय, 8 कांग्रेस और एक माकपा पार्षद चुना गया। गोलूवाला में भाजपा को 11, कांग्रेस को 10 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिलीं। हनुमानगढ़ में परिणामों ने स्पष्ट किया कि स्थानीय उम्मीदवारों और समीकरणों का प्रभाव दोनों प्रमुख दलों के लिए चुनौती बना रहा।

श्रीगंगानगर में कांग्रेस आगे, लेकिन जनादेश बंटा



30

भाजपा



17

कांग्रेस



18

अन्य

65/65

- श्रीगंगानगर जिले के 11 निकायों में परिणाम मिश्रित रहे। श्रीगंगानगर नगर परिषद में भाजपा 30 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी, जबकि कांग्रेस को 17 और निर्दलीयों को 18 सीटें मिलीं। अनूपगढ़ में कांग्रेस ने 16, भाजपा ने 7 और निर्दलीयों ने 12 सीटें जीतीं। गजसिंहपुर में कांग्रेस 13 सीटों के साथ आगे रही, जबकि भाजपा को 6 और निर्दलीयों को एक सीट मिली। घडुसाना में कांग्रेस को 16, भाजपा को 4 और निर्दलीयों को 5 सीटें मिलीं।
- केसरीसिंहपुर में कांग्रेस ने 13, भाजपा ने 5 और निर्दलीयों ने 2 सीटें जीतीं। पदमपुर में भाजपा 13 सीटों के साथ आगे रही, जबकि कांग्रेस को 11 और निर्दलीयों को एक सीट मिली। श्रीकरणपुर में भाजपा ने 14 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बनाई, कांग्रेस को 9 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिलीं।
- सादुलशहर में निर्दलीयों का दबदबा रहा। यहां 25 में से 22 सीटें निर्दलीयों ने जीतीं, जबकि भाजपा को 2 और कांग्रेस को एक सीट मिली। सूरतगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटें मिलीं, जबकि 12 सीटों पर निर्दलीय और एक सीट पर माकपा प्रत्याशी विजयी रहा। रायसिंहनगर में भाजपा को 13, कांग्रेस को 11 और निर्दलीयों को 11 सीटें मिलीं। श्रीविजयनगर में कांग्रेस 11 सीटों के साथ आगे रही, जबकि भाजपा को 10 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिलीं।
- इस तरह श्रीगंगानगर में किसी एक दल की एकतरफा तस्वीर सामने नहीं आई। कुछ निकायों में कांग्रेस मजबूत रही, कुछ में भाजपा आगे रही और कई जगह निर्दलीयों ने परिणाम का गणित बदल दिया। कुल मिलाकर बीकानेर संभाग के निकाय चुनावों का संदेश यही है कि शहरी राजनीति में पार्टी के साथ स्थानीय चेहरा, स्थानीय संगठन और वार्ड स्तर के समीकरण भी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।





बलवंत राज मेहता,
वरिष्ठ व्यंग्यकार

इस बार निकाय चुनाव में कहीं एक वोट ने लाज बचाई, कहीं शून्य ने उम्मीदवार को ही चौंका दिया; कहीं पच्चीं ने फैसला किया, कहीं निर्दलीय पूरी बाजी उलट गए और कहीं ईवीएम ने नतीजे को कल पर टाल दिया। राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे ऐसे खुले जैसे किसी ने राजनीति की ताश की गड्ढी जोर से फेंटकर मेज पर पटक दी हो। बड़े खिलाड़ी अपनी-अपनी जीत के भरोसे बैठे थे, लेकिन खुलते पत्तों ने कई जगह हिसाब-किताब ही बदल दिया। लोकतंत्र ने भी इस बार गंभीर चेहरा छोड़कर खूब मनोरंजन किया।

एक वोट की लाज

परबतसर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ एक वोट मिला। एक वोट! चुनावी मैदान में इससे छोटा समर्थन शायद ही कोई हो, लेकिन इस एक मत ने कम से कम इतना तो कर दिया कि नाम के आगे शून्य नहीं लगा। अब वह एक वोट किसका था, यह रहस्य बना हुआ है। लेकिन उस अकेले मतदाता ने उम्मीदवार की चुनावी इज्जत बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकतंत्र में कभी-कभी एक वोट भी पूरी कहानी का नायक बन जाता है।



उम्मीदवार मैदान में, वोट दूसरे वार्ड में

सिणधरी में आरएलपी प्रत्याशी ओमप्रकाश को शून्य वोट मिले। वे दूसरे वार्ड के निवासी थे, इसलिए खुद को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यह चुनावी किस्मत का ऐसा मजाक है जिसमें उम्मीदवार तो मैदान में मौजूद है, लेकिन उसका अपना वोट कहीं और बैठा है। समर्थकों ने वोट दिया या नहीं, इस पर विवाद अपनी जगह, मगर आंकड़े ने जो तस्वीर दिखाई वह इतनी विचित्र है कि व्यंग्यकार को ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। उम्मीदवार शून्य पर और चुनावी गणित पूर्ण !

वोट, फैसला एक पर्ची का

जहां मुकाबला बराबरी पर अटक गया, वहां घंटों की मतगणना के बाद फैसला एक छोटी-सी पर्ची से हुआ। उम्मीदवारों ने वोट गिने, समर्थकों ने सांसें गिनीं और आखिर में किस्मत ने अपनी पर्ची निकाल दी। सोचिए, जीत-हार के लिए सैकड़ों वोट पड़े और आखिरी फैसला उस कागज के टुकड़े ने किया, जिसकी अपनी कोई चनाबी रैली भी नहीं हुई थी !

घर-घर में चुनावी मुकाबला

इस बार रिश्तेदारी भी चुनावी मैदान में खूब उतरी। कहीं चाचा-भतीजा आमने-सामने थे, कहीं पति-पत्नी दोनों जीते और कहीं देवर-भाभी ने जीत का स्वाद चखा। राजनीति ने परिवारों को भी समझा दिया कि लोकतंत्र में रिश्ते अलग और वोट अलग होते हैं। एक ही घर में दो प्रत्याशी हों तो खाने की मेज पर भी शायद परिणाम आने तक चुनाव आयोग जैसा माहौल रहा हो ! और जहां रिश्तेदारी काम नहीं आई, वहां मतदाता ने साफ कर दिया। परिवार अपनी जगह, मेरी उंगली अपनी जगह।

निर्दलीयों ने बिगाड़ा हिसाब

भरतपुर नगर निगम में 65 वार्डों में 36 निर्दलीय जीत गए। भाजपा को 20 और कांग्रेस को सात सीटें मिलीं। यानी दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी रणनीति, टिकट और संगठन लेकर मैदान में आए, लेकिन निर्दलीयों ने परिणाम की पूरी तस्वीर बदल दी। कल तक जिन उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट न मिलने पर 'बागी' कहा जा रहा था, आज वही बहुमत के खेल में सबसे महत्वपूर्ण हो गए। राजनीति का यह भी कमाल है। जिसे कल दरवाजे पर खड़ा किया, आज उसी से चाबी मांगनी पड़ सकती है।

पार्षद या वीआईपी पैकेज?

अलवर और पाली में क्रॉस वोटिंग के डर से संभावित पार्श्वदों की बाड़ाबंदी ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। लग्जरी बसों और सुरक्षित ठिकानों से मतदान केंद्र तक लाया गया और वोट डालते ही फिर रवाना। मानो पार्श्वद नहीं, कोई ऐसा वीआईपी पैकेज हो जिसकी डिलीवरी रास्ते में किसी दूसरे खिलाड़ी के हाथ न लग जाए। लोकतंत्र में जनता ने प्रतिनिधि चुने और पार्टियां उन्हें संभालने में ऐसी जुटीं कि मतदान केंद्र तक पहुंचने का सफर भी गोपनीय मिशन बन गया।

ईवीएम का अपना मूड

कोटा के वार्ड 87 में ईवीएम की तकनीकी समस्या से परिणाम स्क गया। जयपुर के कुछ बूथों पर भी डेटा उपलब्ध न होने से नतीजे होल्ड करने पड़े। उम्मीदवार बाहर इंतजार करते रहे, कार्यकर्ता बेचैन रहे और आधी रात तक धरना चलता रहा। मशीन शायद कह रही थी। वोट तो आपने डाल दिया, परिणाम की जल्दी आपको है; मुझे नहीं! डिजिटल युग में चुनाव तेजी से हुआ, लेकिन नतीजे को कभी मशीन ने रोका, कभी पर्ची ने और कभी राजनीति ने।

आखिरी बाजी जनता की

नगर निकाय चुनावों की यह ताश कई सबक छोड़ गई। एक वोट ने प्रतिष्ठा बचाई, शून्य ने उम्मीदवार को आईना दिखाया, पर्ची ने बराबरी का फैसला किया, रिशतों ने राजनीति में पारिवारिक रंग भरा, निर्दलीयों ने दलों का गणित बिगाड़ा और ईवीएम ने इंतजार का धैर्य परखा। बड़े खिलाड़ी चाहे जितनी रणनीति बना लें, चुनावी मेज पर आखिरी चाल मतदाता ही चलता है।

सीमा की रक्षा से जनसेवा तक... एक सैनिक की गौरवगाथा, समाजसेवा की मिसाल और परिवार की नई जनसेवा यात्रा



रिटायर्ड सूबेदार चौधरी हरिराम जी

पाली जिले की धरती ने अनेक कर्मठ और संघर्षशील व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। इन्हीं में एक नाम है ग्राम पिपलिया की ढाणी, पोस्ट झीतड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली निवासी चौधरी हरिराम जी का, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रसेवा, समाजसेवा और जनसेवा को समर्पित किया।

किसान परिवार में जन्मे हरिराम जी ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा पूरी की और अपनी प्रतिभा व अनुशासन के बल पर भारतीय सेना में स्थान बनाया। आगे चलकर उनकी सैन्य सेवा, सामाजिक सक्रियता और परिवार की जनसेवा की यात्रा ने उन्हें क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ पाली शहर के सरदार समंद रोड पर निवास कर रहे हैं।

किसान परिवार से भारतीय सेना तक का गौरवपूर्ण सफर

- चौधरी देवराम जी कलिया के सात पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हरिराम जी का बचपन एक संस्कारी और संयुक्त किसान परिवार में बीता।
- उनकी प्रारंभिक शिक्षा झीतड़ा में हुई। इसके बाद उन्होंने सरदारसमंद में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए बांगड़ स्कूल, पाली में अध्ययन किया।
- पढ़ाई के साथ-साथ वे खेलों में भी विशेष रुचि रखते थे। अपने लंबे कद और शानदार खेल प्रतिभा के कारण वे बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। अनुशासन, परिश्रम और नेतृत्व की भावना बचपन से ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही।

30 सितंबर 1970 — जीवन का ऐतिहासिक दिन

30 सितंबर 1970 को हरिराम जी का चयन भारतीय सेना में हुआ और उन्हें सेना के सिग्नल डिपार्टमेंट में सेवा का अवसर मिला।

संचार व्यवस्था सेना की कार्यप्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हरिराम जी ने इसी क्षेत्र में अपनी मेहनत, तकनीकी दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा से उल्लेखनीय सेवाएं दीं।

भारतीय सेना की सिग्नल सेवा में उल्लेखनीय योगदान

सैन्य सेवा के दौरान हरिराम जी ने संचार एवं सिग्नल सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। भारतीय सेना के सिग्नल विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें रूस में आयोजित सैन्य युद्धाभ्यास में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा के दौरान उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उनकी सैन्य सेवा में पदोन्नति भी हुई और उन्होंने सेना में जिम्मेदार पदों पर कार्य किया।

लगभग 28 वर्षों की गौरवपूर्ण सैन्य सेवा पूर्ण करने के बाद 30 नवंबर 1998 को वे भारतीय सेना से सूबेदार (Yeoman of Signals) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रही सेवा

उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पूर्व सैनिकों से जुड़े संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। उन्हें जिला पूर्व सैनिक कांग्रेस के सचिव की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद संगठन ने उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें पूर्व सैनिक जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा। आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दीं।

सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जहां अधिकांश लोग आराम का जीवन चुनते हैं, वहीं हरिराम जी ने अपने जीवन का दूसरा अध्याय समाज और जनसेवा को समर्पित किया।



पार्षद संतोष चौधरी



बबिता देवी



सरोज चौधरी

समाजसेवा में बनाई अलग पहचान

- हरिराम जी का सामाजिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा जितना उनका सैन्य जीवन।
- ग्रामीण जाट पंचायत से लेकर जिला स्तर पर समाजसेवा तक उन्होंने सामाजिक विषयों में सक्रिय भूमिका निभाई।
- बाद में उन्हें पाली जिला जाट समाज का अध्यक्ष चुना गया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने लंबे समय तक पूरी निष्ठा से निभाया।
- उनके कार्यकाल में समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इनमें जाट समाज भवन का जीर्णोद्धार भी प्रमुख रहा।

वार्ड 57 से परिवार की नई जनसेवा यात्रा

- वर्ष 2026 के पाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हरिराम जी के परिवार को अवसर दिया गया।
- उनके बड़े पुत्र राजेश चौधरी के परिवार से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष चौधरी को पाली नगर निगम के वार्ड संख्या 57 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा गया।
- पूरे वार्ड में परिवार की ओर से सक्रिय जनसंपर्क किया गया। विशेष रूप से हरिराम जी के छोटे पुत्र मनोज चौधरी ने पूरे चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई।
- उनकी मेहनत, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और लगातार जनसंपर्क का परिणाम रहा कि श्रीमती संतोष चौधरी वार्ड संख्या 57 से पार्षद निर्वाचित हुईं।



मनोज चौधरी-तकनीकी शिक्षा से समाजसेवा तक

- इस जनसेवा यात्रा में छोटे पुत्र मनोज चौधरी की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है।
- पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तकनीकी क्षेत्र में रुचि के चलते उन्होंने ITI इलेक्ट्रिशियन तथा डिप्लोमा किया।
- इसके बाद उन्होंने एयरटेल भारती, पाली में तकनीशियन के रूप में कार्य किया। अपनी मेहनत और तकनीकी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए उनका चयन एरिक्सन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में हुआ।
- तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हुए भी समाजसेवा से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा। युवा जाट समाज से जुड़े रहते हुए उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई।
- इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के सिग्नल डिपार्टमेंट से जुड़े ITI ASCON प्रोजेक्ट में जोधपुर में भी सेवाएं दीं।
- इस प्रकार मनोज चौधरी ने अपने पिता से मिले अनुशासन और सेवा के संस्कारों को तकनीकी क्षेत्र और सामाजिक जीवन दोनों में आगे बढ़ाया।



प्रतिभाओं को सम्मान देने की अनूठी पहल

- हरिराम जी ने समाज की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय पहल की।
- उन्होंने वीर तेजा विकास समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से समाज के होनहार बच्चों और युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया।
- शिक्षा, खेल और राजकीय सेवा में जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की गई।
- प्रत्येक वर्ष चौधरी बलदेवराम जी मिर्धा की जयंती के अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और युवाओं का सम्मान किया जाने लगा।

पद से नहीं, सेवा से बड़ी पहचान

- नवंबर 2025 में अचानक घर पर पैर फिसलने के कारण हरिराम जी को गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकों ने उन्हें आराम की सलाह दी।
- स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होने के बाद उन्होंने स्वयं समाज की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और जाट समाज के अध्यक्ष पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देकर जिम्मेदारी समाज को सौंप दी।

परिवार भी चला जनसेवा की राह पर

- हरिराम जी ने अपने परिवार को भी मेहनत, अनुशासन और सेवा के संस्कार दिए।
- उनके परिवार में पुत्री सरोज, पुत्र राजेश चौधरी तथा पुत्र मनोज चौधरी हैं।

शहर हमारा है, जिम्मेदारी किसकी?



राकेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव खत्म हो गए, अब बारी काम की है। साफ सड़क, स्वच्छ गली, रोशन रास्ते और समय पर होने वाले छोटे-छोटे काम ही तय करेंगे कि जनता ने जिसे चुना, उसने उसके भरोसे की कितनी कद्र की।

सुबह घर से निकलिए। दरवाजे के सामने कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई है। घर का कचरा उसमें डाल दिया गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। देखने वाले को लगेगा कि सफाई का काम हो गया। लेकिन गली में कुछ कदम आगे बढ़ते ही नाली के किनारे पड़ा कचरा, सड़क पर बिखरे कागज-प्लास्टिक और जगह-जगह जमा गंदगी बता देती है कि कहानी इतनी आसान नहीं है।

हमारे शहरों में सफाई का मतलब कई बार बस इतना रह गया है कि घर-घर से कचरा उठा लिया जाए। उसके बाद वह कचरा कहां जाता है, गली कितनी साफ है, नाली कब साफ हुई, सड़क के किनारे कितनी गंदगी जमा है और सार्वजनिक स्थानों की स्थिति क्या है, इन सवालों पर ध्यान कम जाता है।

अब नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। जनता ने अपने-अपने वार्ड के प्रतिनिधि चुन लिए हैं। किसी ने विकास का भरोसा दिया होगा, किसी ने सफाई का, किसी ने सड़क और नाली का, किसी ने पानी और रोशनी का। किसी ने कहा होगा कि वह हर समय जनता के बीच रहेगा। अब भाषण और वादे पीछे छूट चुके हैं। सामने पांच साल हैं।

यही वह समय है जब जनता को भी अपने प्रतिनिधि से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हमारा वार्ड पहले से ज्यादा साफ होगा? क्या खराब सड़क समय पर ठीक होगी? क्या नाली जाम होने पर शिकायत के लिए कई चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या स्ट्रीट लाइट खराब होने पर अंधेरे में रहने की मजबूरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा पार्षद हमारी समस्या सुनने के लिए वास्तव में हमारे बीच मौजूद रहेगा?

लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इन सवालों को पूछना किसी की कृपा पर निर्भर नहीं है। जनता ने प्रतिनिधि चुना है तो उससे काम का हिसाब मांगना भी उसका अधिकार है।



कचरा उठाना ही सफाई नहीं

- किसी शहर की पहचान उसके बड़े भवनों, चौड़ी सड़कों और चमकते बाजारों से जरूर होती है, लेकिन उसकी असली तस्वीर अक्सर किसी छोटी गली में दिखाई देती है। वहां की सफाई, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्थान बता देते हैं कि शहर की व्यवस्था जमीन पर कैसी है। कई शहरों में सुबह कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी नियमित पहुंचती है। यह अच्छी बात है। लेकिन क्या केवल घरों से कचरा उठा लेना सफाई की पूरी जिम्मेदारी है?
- गली की सफाई कौन करेगा? नालियों की नियमित सफाई कौन देखेगा? सड़क किनारे जमा कचरा कौन हटाएगा? सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी कौन रखेगा? बारिश से पहले नालियां साफ हैं या नहीं, इसकी चिंता कौन करेगा?
- इन सवालों का जवाब केवल सफाईकर्मी नहीं दे सकते। इसके लिए पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार होना पड़ेगा और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उस व्यवस्था पर नजर रखनी होगी।

दुनिया के कुछ शहरों ने दिखाया है रास्ता



- दुनिया के कुछ शहरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि सफाई केवल झाड़ू लगाने से नहीं आती। सिंगापुर में सार्वजनिक स्थानों की सफाई के साथ नागरिक अनुशासन और नियमों का पालन कराने पर भी जोर दिया जाता है। कूड़ा फैलाने पर जुर्माने की व्यवस्था है और कुछ मामलों में दोषियों को सार्वजनिक सफाई से जुड़े काम भी करने पड़ते हैं।
- टोक्यो में भी सार्वजनिक सफाई केवल सरकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं है। नागरिकों को कचरा न फैलाने, अपना कचरा अपने साथ रखने और स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहां यह सोच विकसित की गई है कि सार्वजनिक जगह किसी और की नहीं, सभी की है।
- ज्यूरिख जैसे शहरों में भी सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और नागरिक भागीदारी पर जोर है। वहां भी गंदगी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे नजरअंदाज करने के बजाय व्यवस्था लगातार उससे निपटने का प्रयास करती है।
- इन शहरों की तस्वीर देखते हुए हमारे सामने एक सीधा सवाल आता है। क्या हमारे शहरों में भी सफाई को केवल सफाईकर्मीयों की जिम्मेदारी मानना बंद नहीं किया जाना चाहिए? साफ शहर के लिए सफाईकर्मी जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है व्यवस्था, निगरानी और नागरिक अनुशासन।

इंदौर की मिसाल, लेकिन सवाल भी



भारत में स्वच्छता की बात होती है तो इंदौर का नाम सामने आना स्वाभाविक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले इंदौर ने देश के दूसरे शहरों के सामने एक उदाहरण रखा है। लेकिन किसी शहर की रैंकिंग और उसके हर मोहल्ले का अनुभव एक ही चीज नहीं होते।

इंदौर में रहने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले की सफाई को जिस तरह देखता है, वह किसी सर्वेक्षण की रैंकिंग से अलग अनुभव हो सकता है। इसलिए सवाल इंदौर की उपलब्धि पर संदेह करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या किसी भी शहर की स्वच्छता की सफलता तब पूरी मानी जा सकती है, जब उसका हर वार्ड, हर गली और हर सार्वजनिक स्थान उसी स्तर की व्यवस्था महसूस करे? यही सवाल राजस्थान के शहरों से भी पूछा जाना चाहिए।

पार्षद सिर्फ पार्षद नहीं, जनता का आदमी है

पार्षद बनने के बाद किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शायद यही है कि वह अपने वार्ड से दूर न हो जाए। चुनाव के समय घर-घर पहुंचने वाला जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद भी उतना ही आसानी से लोगों के बीच पहुंच सके, यह लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर होगी।

इसके लिए महीने में कम से कम एक बार वार्ड के लोगों के साथ खुली बैठक या जनसंवाद किया जा सकता है। कोई बड़ा मंच लगाने की जरूरत नहीं। मोहल्ले के लोगों के साथ बैठकर पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। हो सकता है किसी गली में नाली महीनों से साफ नहीं हुई हो। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब हो। किसी सड़क पर गड्ढे हों। कहीं कचरा नियमित नहीं उठ रहा हो। किसी बुजुर्ग को पेंशन से जुड़ी परेशानी हो। किसी परिवार को किसी सरकारी योजना की जानकारी न हो।

जनता से सीधे बात करने पर ऐसी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं, जो फाइलों में शायद कभी दर्ज ही नहीं होंगी। और इसका फायदा केवल जनता को नहीं होगा। पार्षद का अपने क्षेत्र से सीधा संपर्क भी बना रहेगा। उसे यह जानने के लिए चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि लोग उसके काम से संतुष्ट हैं या परेशान।

सरकारी दफ्तर में अटका काम भी जनता की समस्या है

- एक आम आदमी के लिए नगर निकाय ही पूरी दुनिया नहीं है। उसका सामना बिजली, पानी, राजस्व, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, प्रमाण पत्र और दूसरे सरकारी विभागों से भी होता है। यदि किसी नागरिक का जायज काम किसी सरकारी कार्यालय में अनावश्यक रूप से अटक रहा है तो जनप्रतिनिधि की भूमिका केवल यह कहकर खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि यह मेरे विभाग का काम नहीं है।
- वह संबंधित अधिकारी से बात कर सकता है, नागरिक को सही प्रक्रिया बता सकता है और यह जान सकता है कि समस्या कहां अटकी है। इसका अर्थ किसी अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाना नहीं, बल्कि नागरिक और प्रशासन के बीच जिम्मेदार सेतु बनना है। यही वह भूमिका है जिससे लोगों को महसूस होता है कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि केवल वोट मांगने के समय उनका अपना नहीं था।

जनसेवा के छोटे काम, बड़ी राहत

- जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में समय-समय पर स्वास्थ्य जांच या चिकित्सा परामर्श शिविर भी आयोजित कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं, पेंशन, प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं की जानकारी देने वाले शिविर लगाए जा सकते हैं। संबंधित विभागों को एक जगह बुलाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराने की पहल की जा सकती है।
- ऐसे काम किसी पार्षद का संवैधानिक दायित्व नहीं हैं, लेकिन जनसेवा की भावना का हिस्सा जरूर हो सकते हैं। एक बुजुर्ग को पेंशन की जानकारी मिल जाए, किसी महिला को सरकारी योजना का लाभ मिल जाए, किसी जरूरतमंद को समय पर स्वास्थ्य परामर्श मिल जाए या किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय की प्रक्रिया समझ आ जाए तो यह भी जनप्रतिनिधि की भूमिका को सार्थक बनाता है।

जनता को भी आईना देखना होगा

- हर बात के लिए जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं होगा। सड़क पर कागज फेंकने वाला कौन है? नाली में प्लास्टिक डालने वाला कौन है? सार्वजनिक दीवार को गंदा करने वाला कौन है? कूड़ेदान पास होने के बावजूद सड़क पर कचरा डालने वाला कौन है? वह भी इसी शहर का नागरिक है।
- इसलिए साफ शहर के लिए प्रशासन जितना जिम्मेदार है, नागरिक भी उतना ही जिम्मेदार है। फर्क इतना है कि नागरिक से नियमों का पालन करने की अपेक्षा है और जनप्रतिनिधि से यह अपेक्षा भी है कि वह व्यवस्था को काम करते हुए सुनिश्चित करे।

केवल शिकायत नहीं, हिसाब मांगना भी जरूरी

- नगर निकाय के बजट में वार्ड के लिए कितना पैसा आया? कौन सा काम स्वीकृत हुआ? उसकी लागत कितनी है? काम कब तक पूरा होना है? कितना काम हुआ और कितना बाकी है? इन सवालों के जवाब जनता को मिलना चाहिए।
- आज तकनीक ने यह काम काफी आसान कर दिया है। वार्डवार काम, खर्च और शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक की जा सकती है। इससे जनता को भी पता रहेगा कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है और जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन दोनों के लिए जवाबदेही भी तय होगी।

पांच साल बाद सवाल यही होने चाहिए

पांच साल बाद जनता को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि उसके पार्षद ने कितने उद्घाटन किए या कितने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसे पूछना चाहिए कि उसके वार्ड में कितनी सड़कें सुधरीं, कितनी नालियां साफ हुईं, कितनी स्ट्रीट लाइटें ठीक हुईं, सफाई कितनी नियमित हुई और लोगों की कितनी शिकायतों का समाधान हुआ। यही किसी जनप्रतिनिधि के काम का वास्तविक हिसाब है।

पांच साल बहुत लंबा समय है। लेकिन जनता को अगले चुनाव तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसे हर महीने, हर मौसम और हर जरूरी मौके पर अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों को भी याद रखना चाहिए कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है। चुनाव के बाद जनता के बीच बने रहना, उसकी समस्या सुनना और उसका समाधान कराने के लिए प्रयास करना ही उस जीत को सार्थक बनाता है।

आखिर शहर केवल सरकार का नहीं है। शहर जनता का है। जनता का काम केवल वोट देना नहीं और जनप्रतिनिधि का काम केवल चुनाव जीतना नहीं। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के बाद शुरू होती है।

चुनाव आयोग की साख पर सवाल



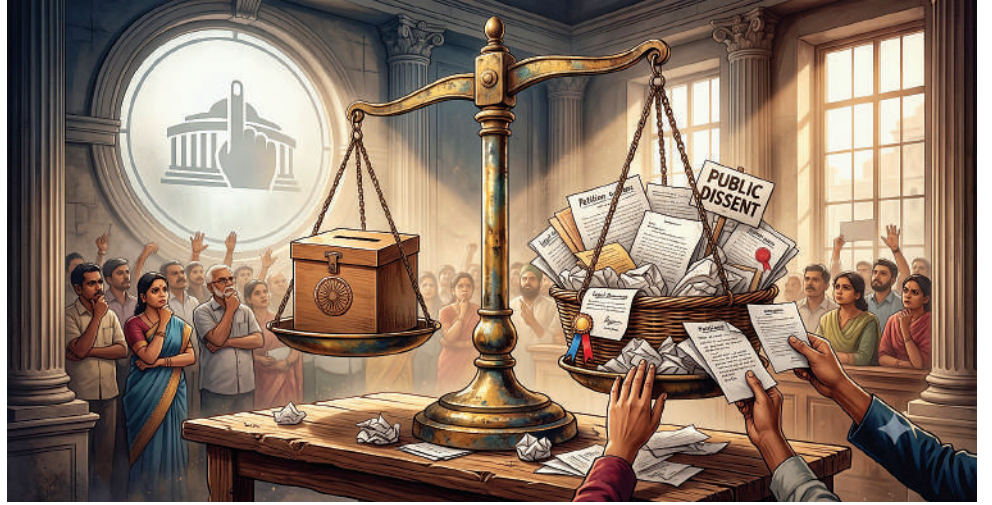
राधा रमण,

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल केवल उसके तीन आयुक्तों के बीच मतभेद तक सीमित नहीं हैं। एसआईआर, मतदाता सूची और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता ने आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता को बहस के केंद्र में ला दिया है।

देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में शामिल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल तो लंबे समय से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया, जब अंग्रेजी के एक प्रमुख अखबार ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों का खुलासा किया। हालांकि, चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर इन रिपोर्टों पर अपना पक्ष रखा है, लेकिन विवाद से जुड़े सवाल अभी बने हुए हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव आयोग की भूमिका एक रेफरी की तरह है। रेफरी चाहे खेल का हो या लोकतंत्र के महापर्व का, उसकी जीत किसी एक पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि मुकाबले की निष्पक्षता में निहित होती है। लेकिन जब रेफरी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, तो पूरे मुकाबले की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।



दो आयुक्तों की आपत्तियों से उठे सवाल



विवेक जोशी

ज्ञानेश कुमार

सुखबीर सिंह संधू

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीरसिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच करीब दस महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, 16 अप्रैल को एक ही दिन में चार आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इनकी प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त समेत उन उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गईं, जो संबंधित कार्यों की निगरानी कर रहे थे। इन आपत्तियों में स्पेशल इंटींसिव रिवीजन (एसआईआर), मतदाता पंजीकरण, नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया और मतदाता डाटाबेस से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे। यह वही प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, नये मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और मृत, अपात्र या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आपत्तियां निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और एसआईआर सहित आयोग के फैसले तीनों आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए। ऐसे में विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि इन आपत्तियों को आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि मतभेदों और अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया से जुड़े तथ्य सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किए जाएं।

मतदाता सूची की विश्वसनीयता सबसे अहम



लोकतंत्र में मतदाता सूची ही मतदान के अधिकार का आधार होती है। यदि मतदाता सूची की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाए, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव पर आपत्ति जताई और इसे अनधिकृत तथा अवैध बताया। साथ ही, मतदाता डाटाबेस के दिल्ली में केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकारियों की उस तक पहुंच न होने पर भी सवाल उठाए हैं।

अखबार का दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सॉफ्टवेयर और आईटी प्रणाली से जुड़ी चिंताओं से कैबिनेट सचिव को भी अवगत कराया था। यदि इन आपत्तियों और शिकायतों का विवरण सही है, तो यह महज प्रशासनिक असहमति का मामला नहीं रह जाता। यह चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा गंभीर सवाल बन जाता है।

रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से यह आपत्ति दर्ज किए जाने की बात कही गई है कि कई आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए। यह इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आखिर जिस संस्था के फैसले करोड़ों नागरिकों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करते हैं, वहां निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और सामूहिक है?

3 सदस्यीय आयोग की व्यवस्था भी सवालों में

चुनाव आयोग पहले एक सदस्यीय संस्था था। वर्ष 1993 में इसे तीन सदस्यीय बनाया गया। उस समय टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तत्कालीन सरकार ने एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति को भी चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया था। इस व्यवस्था के खिलाफ शेषन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने न केवल तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था को बरकरार रखा, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि तीनों चुनाव आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन फैसले आम सहमति या बहुमत से लिए जाएंगे।

ऐसे में मौजूदा विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेखांकित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की भावना से जुड़े सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्तियां दर्ज कराईं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उन आपत्तियों पर किस स्तर पर विचार हुआ और अंतिम निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए गए?

नियुक्ति प्रक्रिया पर भी उठते रहे हैं सवाल

वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति की सलाह से करने की व्यवस्था दी थी। बाद में संसद ने कानून बनाकर चयन समिति की संरचना बदल दी तथा मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्र सरकार के एक मंत्री को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया।

सरकार की ओर से तब यह तर्क दिया गया था कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और अदालत संसद से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन सवाल केवल संसद की विधायी शक्ति का नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का भी है। नियुक्ति प्रक्रिया की संरचना को लेकर उठने वाले राजनीतिक प्रभाव के सवाल संस्था की स्वतंत्रता की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। नये कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके आधिकारिक कृत्यों के संबंध में विशेष कानूनी संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया और इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बीते दिनों सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता उसके कार्यों में भी दिखाई देनी चाहिए।

यही इस पूरे विवाद का केंद्रीय सवाल है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता केवल कानून की किताबों में दर्ज प्रावधानों से सुनिश्चित नहीं होती। उसका वास्तविक प्रमाण उनके फैसलों, कार्यप्रणाली और सार्वजनिक जवाबदेही में दिखाई देता है।

विपक्षी दल लंबे समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और इससे एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई। इन आरोपों को चुनाव आयोग ने किस हद तक स्वीकार या खारिज किया है, यह अलग विषय है। लेकिन नये खुलासों के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की गंभीरता बढ़ गई है।

साख बचाने के लिए पारदर्शिता जरूरी... चुनाव आयोग की साख केवल राजनीतिक दलों के आरोपों या उसके बचाव में जारी बयानों से तय नहीं होनी चाहिए। उसकी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही ही उसकी संस्थागत विश्वसनीयता का आधार बनती है। इसीलिए आयोग को मौजूदा विवाद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय आत्ममंथन और सुधार के अवसर के रूप में लेना चाहिए।

बहरहाल, तीनों चुनाव आयुक्तों को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे विवाद पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची में किए गए बदलावों, नाम हटाने और बहाल करने के आंकड़ों तथा संबंधित आईटी प्रणाली की कार्यप्रणाली का पूरा विवरण

एसआईआर में पारदर्शिता की असली परीक्षा

एसआईआर के तहत अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इनमें से करीब 22 लाख मतदाताओं ने आयोग के फैसले को चुनौती दी। रिपोर्टों के मुताबिक, अप्रैल से अब तक ट्रिब्यूनलों ने 1,26,194 मामलों का निपटारा किया, जिनमें 1,13,943 लोगों के नाम मतदाता सूची में बहाल किए गए। यानी निपटाए गए मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक में नाम बहाल किए गए।

यह आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हटाए गए सभी नाम गलत थे। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियों के मामले भी शामिल हैं। लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम बहाल कराने के लिए अपील और कानूनी प्रक्रिया का सहारा क्यों लेना पड़ा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम इस प्रक्रिया के दौरान हटे और बाद में बहाल हुए, उनके बीच यदि कोई मतदान से वंचित रहा हो, तो उसके लोकतांत्रिक अधिकार की भरपाई का सवाल भी महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची को शुद्ध करने का उद्देश्य जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न कटे।

अब तक एसआईआर के दो चरणों में बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया कराई जा चुकी है। तीसरे चरण में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और ओडिशा के साथ अरुणाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ समेत अन्य निर्धारित क्षेत्रों में भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

ऐसे में प्रक्रिया की पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा का महत्व और बढ़ जाता है। एसआईआर के दौरान मतदाताओं से पूछे जा रहे सवालों और दस्तावेजों की मांग को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी उनकी और उनकी मां की उम्र के बीच अंतर से जुड़ी विसंगति पर नोटिस दिया गया। नये मतदाताओं से उनके पिता का नाम पिछली एसआईआर में दर्ज नहीं होने का कारण पूछा जा रहा है। कई चर्चित लोगों को भी एसआईआर से जुड़े नोटिस दिए जाने की खबरें सामने आई हैं।

ये कुछ चर्चित उदाहरण हैं। आम नागरिकों को इस प्रक्रिया में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका पूरा आकलन सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए। मतदाताओं से नागरिकता संबंधी प्रमाण मांगे जाने के आरोप भी गंभीर हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का वैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया में नागरिकता संबंधी जांच और मतदाता पात्रता के नियमों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

एक ओर चुनाव आयोग का नारा है कि कोई पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए, दूसरी ओर यदि पात्र नागरिकों को अपने नाम बचाने या वापस जुड़वाने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों से गुजरना पड़े, तो इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता के अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के दो आवश्यक आधार हैं।

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की बात कह चुके हैं। राजनीतिक दलों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल किसी एक दल या सरकार से कहीं बड़ा है।

सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही, आयोग के भीतर असहमति दर्ज करने, उस पर विचार करने और अंतिम निर्णय तक पहुंचने की स्पष्ट व्यवस्था भी सामने रखी जानी चाहिए।

लोकतंत्र में असहमति कमजोरी नहीं, बल्कि संस्थागत मजबूती का प्रमाण होती है। लेकिन जब असहमति दर्ज होने के बावजूद उसका जवाब न मिले और फैसलों की प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे, तो संस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सवाल केवल चुनाव आयोग के तीन आयुक्तों के बीच मतभेद का नहीं है। सवाल उस संस्था की विश्वसनीयता का है, जिसके निष्पक्ष होने पर ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के जनादेश की विश्वसनीयता टिकी हुई है।

मतभेद के बीच सहयोग की राह



ज्ञान चंद पाटनी
वरिष्ठ पत्रकार

ब्रिक्स का विस्तार जहां इसे वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली मंच बना रहा है, वहीं सदस्य देशों के बीच मतभेद भी चुनौती हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता में सहयोग, आर्थिक समन्वय और वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया।

भारत की अध्यक्षता में हाल ही संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया है कि बदलते दौर में ब्रिक्स जैसे मंचों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ब्रिक्स अब वैश्विक व्यापार, तकनीक, आपूर्ति नेटवर्क और विश्व स्तरीय संस्थाओं में सुधार जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रभाव डालने वाला मंच बन रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में जारी घोषणा-पत्र की खासियत यह रही कि इसमें शामिल देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद साझा सहमति बनाने का प्रयास किया गया। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ 'जिरो टॉलरेंस' की नीति पर जोर दिया गया तथा इसके सभी रूपों को खारिज किया गया। ब्रिक्स नेताओं ने आतंककारियों के सुरक्षित ठिकानों, टेरर फंडिंग और सीमा पार आतंकवाद की आवाजाही को रोकने के लिए ठोस और संयुक्त कार्रवाई की मांग की। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है।

चीन के साथ द्विपक्षीय संवाद

भारत के लिए इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू चीन के साथ द्विपक्षीय संवाद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में दोनों देशों के संबंधों को स्थिर करने की कोशिश दिखाई दी। सीमा पर शांति और स्थिरता के साथ-साथ व्यापार, आपूर्ति नेटवर्क और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर बातचीत हुई।

ब्रिक्स कंटीन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव

भारत ने 'ब्रिक्स कंटीन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म' का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत आपसी समन्वय बढ़ाने और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी की बात है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अक्सर घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की गति अध्यक्षता बदलने के साथ धीमी पड़ जाती है।

व्यापक आर्थिक एजेंडा

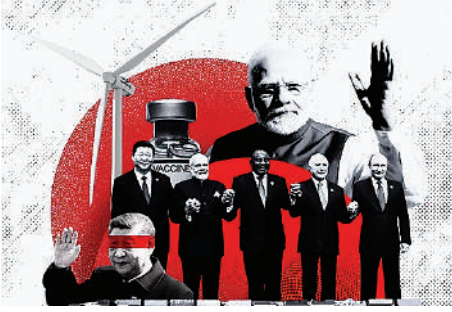
आर्थिक एजेंडा भी व्यापक रहा। वित्त, बुनियादी ढांचा, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि-पारिस्थितिकी और फिनटेक जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। ब्रिक्स ने एकतरफा टैरिफ, गैर-टैरिफ उपायों और संरक्षणवाद पर भी चिंता जताई। ब्रिक्स को विकास की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने वाले सहयोगी मंच के रूप में विकसित करने की कोशिश हो रही है।

कम नहीं चुनौतियां

पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्दों में सीमा पार भुगतान की चर्चा बढ़ी है। इसका मकसद डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है। हालांकि अभी तक ब्रिक्स ने कोई साझा तकनीकी ढांचा या एकीकृत सेटलमेंट प्रणाली तय नहीं की है और 'ब्रिक्स पे' जैसी कोई साझा भुगतान व्यवस्था भी शुरू नहीं हुई है। इस दिशा में कई व्यावहारिक अड़चनें हैं। अलग-अलग देशों की विनिमय दर व्यवस्थाएं अलग-अलग हैं। इसके अलावा कुछ देशों पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर सीमा पार भुगतान की व्यवस्था पर पड़ सकता है। व्यापार असंतुलन भी एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए ब्रिक्स की आर्थिक महत्वाकांक्षा को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। पहले स्थानीय मुद्दों में द्विपक्षीय व्यापार की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, फिर बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों के बीच तकनीकी तालमेल बढ़ाया जाए और उसके बाद व्यापक साझा व्यवस्था की संभावना पर विचार किया जाए।

वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग... भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को महत्व दिया। दुनिया में आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल रहा है, लेकिन वैश्विक संस्थाओं की संरचना अब भी काफी हद तक पुराने शक्ति-संतुलन को प्रतिबिम्बित करती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग इसी असंतुलन से जुड़ी है। नई दिल्ली सम्मेलन का व्यापक संदेश यही है कि आज की दुनिया में विभिन्न देशों के बीच मतभेदों के बावजूद सहयोग की जगह खत्म नहीं हुई है।

क्या है ब्रिक्स



ब्रिक्स तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर बी.आर.आई.सी. और एस. से बना ऐसा शब्द है, जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य बने, जबकि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया इसका सदस्य बना। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 2025 में इसके पार्टनर देश बने।

ब्रिक्स का लक्ष्य



ब्रिक्स का गठन विकासशील देशों को एकजुट करने के मकसद से हुआ था, ताकि विकसित देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती दी जा सके। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं लेकिन इनमें से कुछ के बीच भारी राजनीतिक विवाद भी हैं। ब्रिक्स का हर वर्ष शिखर सम्मेलन होता है। हर साल सदस्य देश बारी-बारी से इसकी अध्यक्षता और मेजबानी संभालते हैं। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 49.5 प्रतिशत आबादी ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत है। इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। साथ ही वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। इसका सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सदस्य देश आपसी सहमति से ये फैसला लेते हैं।

शाकाहारी थाली पर इतना हंगामा क्यों?



ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए आयोजित भोज भी सुर्खियों में आया। ब्रिक्स भोज में शाकाहारी व्यंजन परोसे जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी शुरू हो गई। एक वर्ग ने यह तर्क दिया कि देश की बड़ी आबादी मांसाहारी है, इसलिए विदेशी मेहमानों को केवल शाकाहारी भोजन परोसना भारत की समावेशी खाद्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी शाकाहारी आबादी वाला देश है। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण दुनिया में आजकल शाकाहार लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय शाकाहारी व्यंजनों को प्रस्तुत करने पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है।

भारत में शाकाहार की जड़ें बहुत गहरी हैं। धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और पीढ़ियों से चली आ रही खान-पान की आदतों ने यहां शाकाहारी भोजन को व्यापक आधार दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक शाकाहारी व्यंजनों की अपनी अलग पहचान है। शाकाहार आज केवल धार्मिक या पारंपरिक भोजन की श्रेणी तक सीमित नहीं है। पर्यावरण, पशु कल्याण और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता भी लोगों को प्लांट-बेस्ड भोजन की ओर ले जा रही है। करुणा भी वह मुख्य कारण है जिसके चलते कई लोग शाकाहारी जीवनशैली अपनाते हैं। भारत की विशेषता यह है कि यहां शाकाहारी भोजन केवल किसी आधुनिक 'डाइट ट्रेंड' का परिणाम नहीं है। यह सदियों से विकसित जीवनशैली का हिस्सा रहा है। अहिंसा की भारतीय अवधारणा ने भी इसे मजबूत आधार दिया है। भोजन में हिंसा को कम करने की सोच भारतीय दर्शन के कई हिस्सों में दिखाई देती है। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी शाकाहार के

प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भोजन के लिए बेजुबान जानवरों को मारना उचित नहीं है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि 'मैं अपने पेट को जानवरों की कब्रगाह नहीं बनाना चाहता।' उनके लिए शाकाहार केवल भोजन का चुनाव नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण था।

यदि भोजन के जरिए अपनी संस्कृति दिखाने का अवसर मिले तो भारत को इससे पीछे क्यों हटना चाहिए? दुनिया आज मिलेट्स की चर्चा कर रही है। रागी और बाजरा जैसे अनाज भारतीय भोजन परंपरा में सदियों से मौजूद हैं। दुनिया में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और वैकल्पिक भोजन की चर्चा बढ़ रही है तो भारतीय दालें, चना, राजमा और अनेक प्रकार के अनाज इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मशरूम से बने व्यंजन, दालों से तैयार स्पूप, पनीर के अनेक रूप और क्षेत्रीय सब्जियों की विविधता भारत की भोजन परंपरा को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दे सकती है। जब विदेशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया जाता है तो हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन शाकाहार को लेकर असहज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यदि भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा शाकाहारी भोजन है तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे दिखाने में संकोच कैसा?

शाकाहार का समर्थन अहिंसा, पर्यावरण और पशु कल्याण जैसे मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। दुनिया जब टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भोजन की ओर देख रही है, तब भारत के पास अपनी प्राचीन शाकाहारी परंपरा के जरिए देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए किसी शाकाहारी राजकीय भोज को लेकर अनावश्यक आक्रोश के बजाय इसे भारत की खाद्य-सांस्कृतिक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए।

नाराज सियासी फूफा और फूफियां!



हरीश मलिक,
लेखक और व्यंग्यकार

हमारे देश में हर कुनबे, समुदाय, वर्ग या बड़े परिवार में एक फूफा'जी जरूर होते हैं। यह वो प्राणी है जो शादी में देर से आते हैं। खाने में कमी निकालते हैं। टैंट से लेकर कैटरिंग वाले तक रौब झाड़ते हैं। शादी में कुर्सी पीछे पड़ गई तो फूफा नाराज। नाश्ता पांच मिनट देर से पहुंचा तो फूफा नाराज। फोटो में दूल्हे के पास जगह नहीं मिली तो फूफा नाराज। जाते-जाते पूरे परिवार को बता जाते हैं कि इंतजाम उनसे पूछकर करना चाहिए था। दरअसल, फूफा भारतीय समाज का वह सम्मानित रिश्ता है, जिसकी नाराजगी का कारण कभी स्पष्ट नहीं होता। मगर उसे दूर करना पूरे परिवार का नैतिक कर्तव्य माना जाता है।

राजनीति ने इस महान परंपरा को लोकतांत्रिक स्वरूप दिया है। दरअसल, सियासत में दो तरह के लोग अहम होते हैं। एक वे, जिनके पास वोट होते हैं। दूसरे वे, जिन्हें भ्रम होता है कि सारे वोट उन्हीं के पास हैं। दूसरी जाति के प्राणी को हम सुविधा के लिए 'सियासी

फूफा' कह सकते हैं। घर के फूफा की तरह ही सियासी फूफा को भी यह भ्रम नहीं, बल्कि पूरा विश्वास होता है कि उनके बिना पार्टी अधूरी है और राजनीति में उनके बिना चुनाव अधूरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि घरेलू फूफा नाराज होकर शादी में खाना छोड़ सकते हैं, जबकि सियासी फूफा नाराज होकर पूरा चुनावी समीकरण तोड़-मरोड़ सकते हैं।

यह भी दिलचस्प है कि सियासी फूफा किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। यह समान रूप से सभी पार्टियों में सर्वव्यापी हैं। सर्वज्ञ हैं और सर्व-भक्षक हैं। यहां तक कि अभी ताजी-ताजी बनी पार्टी में भी एक नाराज फूफा ने अपनी दूसरी पार्टी बना डाली। तब यह

समझना और आसान है कि पुरानी और सबसे पुरानी पार्टियों में कितने दमदार फूफा-फूफी होंगे। इनकी अपनी पार्टी में भले ही रत्ती-भर न चले, लेकिन दूसरे दलों के इंतजाम पर टिप्पणी करना ये अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। सरकार कुछ करे तो कहेंगे- हमें पूछा क्यों नहीं? सरकार कुछ न करे तो बोलेंगे- देखा, कुछ कर ही नहीं रहे! चुनाव हार जाएं तो मशीन खराब, जीत जाएं तो जनता समझदार है!

सियासी फूफा नाराज हो जाएं तो साम, दाम, दंड, भेद की चारों नीति मिलकर भी उसे मनाने में बस पसीना बहा सकती है। साम से समझाइए तो कहेंगे- बहुत समझा लिया, हम बच्चे हैं का? दाम का संकेत दीजिए तो कहेंगे- हमें

से राजनीति में सम्मान का वह अध्याय शुरू होता है, जिसमें सम्मान की परिभाषा टिकट, पद, बोर्ड, निगम, आयोग, संगठन और कभी-कभी राज्यसभा सीट तक पहुंच जाती है।

राजनीति में फूफा होना सामान्य बात नहीं है। फूफा वह प्राणी है, जिसे पार्टी ने कभी पद दिया हो या न दिया हो, लेकिन वह स्वयं को पार्टी का सर्वेसर्वा मान लेता है। वह नाराज होने के लिए कारण खुद ही बना लेता है। टिकट, पद, कुर्सी, ओहदा, भाषण, सम्मान किसी में भी फूफा की भैंहें तन सकती हैं। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए। पार्टी की हार पर सवाल उठें तो फूफा की पहली लाइन होती है- "मैंने तो पहले ही कहा था..." यह "मैंने पहले ही कहा था" राजनीति का सबसे खतरनाक वाक्य है। चुनाव परिणाम के बाद हर फूफा के पास यह कहने के लिए पर्याप्त प्रमाण होता है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी। कोरोना से लेकर इकोनॉमी तक बेखौफ कह देते हैं- "मैंने पहले ही कहा था।"

पहले राजनीतिक नाराजगी पर पुरुषों का एकाधिकार था। लोकतंत्र ने यहां भी समान अवसर बनाए हैं। अब फूफियां भी मैदान में हैं। सियासी फूफिया टिकट वितरण से लेकर संगठन की नियुक्ति तक सब पर पैनी नजर रखती हैं। फूफा के पास कार्यकर्ताओं की डायरी है, फूफियों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है। फूफा के पास पुराना अनुभव है तो फूफी के पास नया नेटवर्क है। चुनाव आते ही फूफा ही नहीं फूफियों का महत्व भी अचानक बढ़ जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों पार्टी की



बिकाऊ समझे हो? दंड की बात कीजिए तो पूरे ताव के साथ कहेंगे- अब देखिए मैं क्या-क्या कर सकता हूं। और भेद तो फूफा'जी के पास पहले से ही होता है। आखिर वे राजनीति में हैं, उनके पास आधे नेताओं की पूरी कुंडली और बाकी आधे नेताओं की आधी-अधूरी जानकारी तो होती ही है! सियासी फूफा की एक बड़ी खूबी है कि उसे मनाने की कोशिश जितनी ज्यादा करेंगे, वे उतने ही अधिक भाव खाएंगे। आप कहेंगे फूफा'जी, आपके बिना पार्टी अधूरी है। वे बोलेंगे- अच्छा अब हमारी याद आई? आप टिकट का लालच उछालेंगे। वे मुस्कराकर कहेंगे कि टिकट-विकट मुद्दा नहीं है। बात मान-सम्मान की है। और यहीं

अमूल्य धरोहर हैं। यह अलग बात है कि इस धरोहर का मूल्य चुनाव तक ही रहता है।

अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। जैसे-जैसे चुनावी माहौल गरमाएगा, वैसे-वैसे सियासी फूफा-फूफियों की पूछ बढ़ेगी। ऐसे में चुनावी राजनीति का एक नया सूत्र-वाक्य यह होना चाहिए कि वोटर को साधना, कार्यकर्ता को संभालना और गठबंधन को बचाना आसान है, लेकिन नाराज सियासी फूफा को मनाना लोहे के चने चबाने के समान है। इसलिए भले ही देश-प्रदेश गत में चले जाएं, लेकिन सियासी फूफा की नाराजगी नाकाबिले बदरिस्त होनी चाहिए!

आत्मा बदली तो श्राद्ध किसका?



पार्थसारथि थपलियाल,
लेखक, साहित्यकार

आत्मा के देह परिवर्तन और पुनर्जन्म की मान्यता के बीच श्राद्ध की सार्थकता पर सवाल उठता है। भारतीय दर्शन और शास्त्रीय परंपराओं के संदर्भ में यह विवेचन पितृऋण, श्रद्धा और कृतज्ञता का अर्थ बताता है।

हिन्दू जीवन-दर्शन में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन मानी गई है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं- वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही। अर्थात् जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है।

जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तब स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है- यदि हमारा कोई पूर्वज पुनर्जन्म ले चुका है, तो हम श्राद्ध किसे अर्पित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले आत्मा और पितर के अंतर को समझना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में आत्मा को नित्य, अविनाशी और देह से भिन्न माना गया है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पितृ शब्द एक व्यापक पारिवारिक और धार्मिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत हमारे दिवंगत पूर्वजों की स्मृति, उनकी परंपरा और हमारे ऊपर उनके उपकार का भाव सम्मिलित है।

वैदिक परंपरा में 'देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण' जैसी उत्तरदायित्व-बोधक अवधारणा दिखाई देती है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति में श्राद्ध, पितृयज्ञ, पात्रता और विधि का अधिक व्यवस्थित वर्णन मिलता है। गरुडपुराण तथा विभिन्न धर्मशास्त्रीय निबंधों में मृत्यु के बाद की अवस्थाओं, प्रेतावस्था और श्राद्ध के संबंध पर विस्तार है। दूसरी ओर, उपनिषदों और भगवद्गीता में आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म पर अधिक दार्शनिक बल है।

यही कारण है कि श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को भोजन पहुंचाना मात्र नहीं है। 'श्राद्ध' शब्द ही 'श्रद्धा' से बना है। अर्थात् श्रद्धा और कृतज्ञता से किया गया कर्म श्राद्ध है। हम अपने पूर्वजों के प्रति उस ऋण को स्वीकार करते हैं, जिसे भारतीय चिंतन ने पितृऋण कहा है। हमें शरीर, संस्कार, भाषा, परिवार, ज्ञान, परंपरा और जीवन की अनेक सुविधाएं पूर्वजों से मिली हैं। श्राद्ध उनके प्रति इसी कृतज्ञता का धार्मिक रूप है। भारतीय शास्त्रों में मृत्यु के बाद की अवस्थाओं के संबंध में अनेक सूक्ष्म धारणाएं मिलती हैं। 'प्रेत' की अवधारणा भी एक विशेष संक्रमण-अवस्था से संबंधित है। गरुडपुराण और कुछ धर्मशास्त्रीय परंपराएं मृत्यु के बाद प्रेतावस्था तथा सपिंडीकरण के माध्यम से पितृलोक में प्रतिष्ठा का वर्णन करती हैं, पर इन विवरणों को सभी हिन्दू दार्शनिक परंपराएं समान रूप से स्वीकार नहीं करतीं।



भगवद्गीता (2.22) देह-परिवर्तन का रूपक देती है और (8.6) अंतर्कालीन स्मरण तथा कर्म-संस्कारों के संबंध की चर्चा करती है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में कर्म के अनुसार विभिन्न गतियों तथा पुनर्जन्म की धारणाएं मिलती हैं। वहीं कुछ उपनिषद् आत्मज्ञान को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। इसलिए "हर मृत व्यक्ति तुरंत किसी नए शरीर में जन्म लेता है" या "हर मृत व्यक्ति लंबे समय तक पितृलोक में ही रहता है"- दोनों को सभी ग्रंथों का निर्विवाद निष्कर्ष कहना उचित नहीं होगा।

तर्पण का शाब्दिक अर्थ है- तृप्त करना, संतुष्ट करना। जल अर्पित करते समय मनुष्य अपने पितरों का स्मरण करता है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। यह आवश्यक नहीं कि तर्पण का अर्थ यह समझा जाए कि जल भौतिक रूप से किसी अदृश्य व्यक्ति तक पहुंच रहा है। धार्मिक कर्म का महत्व उसके पीछे स्थित भाव, संकल्प और श्रद्धा में भी निहित है।

यदि कोई पूर्वज पुनर्जन्म ले चुका हो, तब भी श्राद्ध की सार्थकता समाप्त नहीं होती। क्योंकि उस वंश से प्राप्त संस्कार और स्मृतियां सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं। अतः पितृपक्ष में जिस तिथि को किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है।

- दार्शनिक या प्रतीकात्मक दृष्टि से यह उस संबंध का स्मरण है, जो जैविक वंश, संस्कार और सामाजिक उत्तराधिकार के माध्यम से बना रहता है। जैसे हम किसी महान व्यक्ति की स्मृति में स्मारक बनाते हैं, उनके नाम से पुस्तकालय या छात्रवृत्ति स्थापित करते हैं अथवा उनकी जयंती मनाते हैं, वैसे ही श्राद्ध पारिवारिक स्तर पर पूर्वजों की स्मृति को जीवित रखने की सनातन व्यवस्था है।

- हमारा अस्तित्व अकेले हमारा बनाया हुआ नहीं है। उसमें अनेक पीढ़ियों का योगदान समाहित है। श्राद्ध अंधविश्वास नहीं, कृतज्ञता है। यह केवल मृतक की चिंता नहीं, बल्कि पूर्वजों से प्राप्त जीवन-मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प है।

- श्राद्ध उस आत्मा को भोजन कराने का कर्म नहीं, जिसे हम उसकी वर्तमान देह में खोज रहे हैं। यह उस पितृपरंपरा के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसके कारण हम आज अस्तित्व में हैं। हम अपने पूर्वजों को केवल स्मरण नहीं करते, उनके ऋण को स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त जीवन-परंपरा को आगे ले जाने का संकल्प करते हैं।

सेवा . समर्पण . सहयोग . संस्कार . विकास

समाज सेवा की पहचान भोम सिंह जी धारवी



उनका जीवन संदेश...
अपनी मेहनत से आगे बढ़ना
और अपनी क्षमता से समाज के
काम आना — यही जीवन की
सच्ची सफलता है।

रा

जस्थान के बाड़मेर जिले में शिव तहसील के धारवी कलां गांव निवासी समाजसेवी व भामाशाह भोम सिंह जी भाटी, धारवी क्षेत्र में समाज सेवा, जनसहयोग और सामाजिक सरोकारों के लिए निरंतर सक्रिय रहने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हैं।

उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, व्यवसाय, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणादायी यात्रा है। अब राजनीति क्षेत्र में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जनता की सेवा करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। भोम सिंह जी क्षेत्र का लोकप्रिय नाम है। जरूरतमंदों, गरीबों, आमजन व ग्रामीणों की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। समाजसेवी भोम सिंह जी को गांव के लोग सुख दुख का साथी मानते हैं। वे क्षेत्र में गरीबों के मसीहा की तरह उभर रहे हैं। युवाओं और बुजुर्गों में भी खासे से लोकप्रिय है।

पारिवारिक एवं शैक्षणिक परिचय

नाम: भोम सिंह जी धारवी

पिताजी: भगवान सिंह जी

- ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े और गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की।
- साधारण परिवेश से आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई।
- बचपन से ही सामाजिक सरोकारों और लोगों की मदद करने की भावना को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

संघर्ष से सफलता तक- व्यवसायिक यात्रा

- भोम सिंह जी ने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत फर्नीचर के कार्य से की। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने पाली के सुमेरपुर हाईवे पर होटल व्यवसाय की शुरुआत की और वर्तमान में पाली में दो होटल संचालित कर रहे हैं।
- समय के साथ बदलती तकनीक और भविष्य की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने सोलर सिस्टीम एवं सोलर प्रोजेक्ट्स, सोलर पार्क के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया। इस क्षेत्र में भी ऊंचाईयां प्राप्त कर रहे हैं।
- आज उनका कार्यक्षेत्र सोलर प्रोजेक्ट एवं सोलर पार्क से जुड़े कार्यों तक विस्तृत है।

क्षेत्र के प्रमुख भामाशाह के रूप में पहचान

अपने क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं जनहित के कार्यों में सहयोग के कारण भोम सिंह जी ने एक प्रमुख भामाशाह एवं समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग

भोम सिंह जी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में भी निरंतर सहयोग करते हैं।

—कोटेश्वर धाम, सिवाना

कोटेश्वर धाम, सिवाना के प्रमुख कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के लिए भोजन व्यवस्था में सहयोग उनकी सेवा भावना का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

—कारियाप पाबूजी मंदिर, जैसलमेर

कारियाप पाबूजी मंदिर, जैसलमेर में किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं विकास कार्यों में सहयोग के लिए भोम सिंह जी सदैव तत्पर रहते हैं।

—संत सत्यम गिरी जी के परम शिष्य

भोम सिंह जी संत सत्यम गिरी जी के परम शिष्य हैं।

संतों के मार्गदर्शन, संस्कारों और सेवा भावना को जीवन में आत्मसात करते हुए वे समाज सेवा को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

कोरोना काल में मानव सेवा की मिसाल



कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब हर व्यक्ति अपने जीवन और परिवार की चिंता में था, उस समय भोम सिंह जी ने समाज के जरूरतमंद लोगों के बीच सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी।

कोरोना काल में किए गए प्रमुख सेवा कार्य:

- बाड़मेर जिले के भियाड़, शिव तहसील क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवाने में सहयोग।
- लोगों को मास्क वितरित किए।
- ग्रामीणों को कोरोना से बचाव एवं सावधानियों के प्रति जागरूक किया।
- जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क अपने वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की।
- गंभीर मरीजों को जोधपुर अस्पताल तक पहुंचाने में सहयोग किया।
- गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन और पानी की व्यवस्था करवाई।
- दिन-रात लोगों की जरूरत के समय खड़े रहकर मानव सेवा का परिचय दिया।

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए समर्पित प्रयास

भोम सिंह जी का मानना है कि गांव और समाज का भविष्य हमारे विद्यार्थी हैं।

इसी सोच के साथ वे क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए लगातार सहयोग करते रहे हैं।

रणकदेव क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में

- विद्यार्थियों के लिए प्याऊ एवं पेयजल व्यवस्था में सहयोग।
- गर्मी के मौसम में विद्यार्थियों के लिए छाया की व्यवस्था।
- विद्यार्थियों के लिए खान-पान एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग।
- विद्यालय एवं विद्यार्थियों से जुड़े सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहना।

धारवी कलां सरकारी विद्यालय में विशेष सहयोग

धारवी कलां के सरकारी विद्यालय में भी भोम सिंह जी का निरंतर सहयोग देखने को मिलता है।

राष्ट्रीय पर्वों पर विशेष सहयोग

26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर:

- विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण में सहयोग।
- विद्यार्थियों के लिए खाना-पीना एवं अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग।
- विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सहयोग के लिए सदैव आगे रहना।
- शिक्षा एवं विद्यार्थियों के प्रोत्साहन से जुड़े कार्यों में निरंतर भागीदारी।

समाज के हर वर्ग के साथ सहयोग की भावना

भोम सिंह जी का सामाजिक जुड़ाव केवल एक क्षेत्र या एक संस्था तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, विद्यार्थी, गरीब एवं जरूरतमंद परिवार, धार्मिक आयोजन, विद्यालय और सामाजिक कार्यक्रम-सभी क्षेत्रों में यथासंभव सहयोग के लिए आगे रहना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

भियाड़ क्षेत्र से जुड़े सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में भी वे लगातार सहयोग करते रहे हैं।

सेवा ही पहचान — समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व

भोम सिंह जी धारवी की पहचान केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवा और जनसहयोग के लिए सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व के रूप में बनी है। लेकिन सफलता के साथ समाज, आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी पीछे नहीं छोड़ा।



भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भोम सिंह जी अपना आदर्श मानते हैं।

‘विराट’ तूफान और कीर्तिमानों का महाकुंभ

तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली के नाबाद
139 रनों के तूफान से वेस्टइंडीज पस्त।
महज 303 पारियों में सबसे तेज 15,000
वनडे रन पूरे कर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा,
साथ ही गावस्कर के ऐतिहासिक कीर्तिमान
की भी बराबरी की।



अजय अस्थाना
वरिष्ठ पत्रकार

क्रिकेट की दुनिया में मैच जीतने तो कई खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, लेकिन जब विराट कोहली क्रीज पर कदम रखते हैं, तो सांख्यिकीविदों और रिकॉर्ड बुक्स के पन्नों में हलचल मच जाती है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ने एक ऐसी ही शाम देखी, जहां कैरेबियाई गेंदबाजी थी, 22 गज की पट्टी थी और सामने खड़ा था रनों का सबसे भूखा सौदागर। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में कोहली ने ऐसी आतिशी पारी खेली कि वेस्टइंडीज 8 विकेट से मुकाबला ही नहीं हारी, बल्कि मैदान पर विराट नाम का बवंडर देखकर दंग रह गई।

हर तरफ चौकों-छक्कों की नुमाइश

अक्सर विराट कोहली को पिच पर सूझबूझ से पारी बुनने और दौड़कर रन चुराने वाले मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में उनका अंदाज कुछ और ही था। यहां रणनीति के साथ आक्रामकता भी नजर आई। कोहली ने महज 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की ऐसी पारी खेली कि गेंदबाज दबाव में नजर आए। 10 चौके और 9 छक्के उनकी इस पारी की खासियत रहे। नौ छक्के वनडे की एक पारी में कोहली के सर्वाधिक छक्के भी हैं।

15 हजारी क्लब: सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त

इस मुकाबले में इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया, जिसे दोहराना आसान नहीं होगा। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यह उपलब्धि उन्होंने 303वें पारी में अपने नाम की। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 377 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। इस तरह कोहली ने सचिन से 74 पारियां कम लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

शतकों का पहाड़: 86वां अंतरराष्ट्रीय शतक

विराट कोहली जब लय में हों तो शतक उनके लिए जैसे सहज उपलब्धि बन जाते हैं। इस मुकाबले में उनके बल्ले से निकला वनडे का 55वां शतक। इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने और मजबूत किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका 86वां शतक था। आधुनिक क्रिकेट के इस दौर में, जहां गेंदबाज हर दिन नए विश्लेषण लेकर आते हैं, कोहली की यह निरंतरता खास है।



सचिन और गावस्कर की बराबरी

- तिरुवनंतपुरम की यह शाम सिर्फ नए रिकॉर्ड बनाने की नहीं, बल्कि क्रिकेट के दो दिग्गजों के रिकॉर्ड की बराबरी करने की भी गवाह बनी।
- घरेलू सरजमीं पर 42वां शतक: भारतीय धरती पर यह कोहली का 42वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही सरजमीं पर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतकों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
- लिस्ट-ए में 60वां सैकड़ा: इस पारी के साथ उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में अपना 60वां शतक पूरा किया और इस मामले में भी सचिन तेंदुलकर की बराबरी की।
- लिटिल मास्टर के रिकॉर्ड की बराबरी: वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कोहली का 13वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। इसके साथ ही उन्होंने कैरेबियाई टीम के खिलाफ सुनील गावस्कर के 13 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की।

‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का अनोखा रिकॉर्ड

- विराट कोहली उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने आईसीसी के सीमित ओवरों के वैश्विक टूर्नामेंट में तीन बार ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का पुरस्कार जीता है। उन्होंने यह उपलब्धि टी20 विश्व कप 2014 और 2016 तथा एकदिवसीय विश्व कप 2023 में हासिल की। 2023 विश्व कप में उनके 765 रन किसी एक विश्व कप संस्करण में किसी बल्लेबाज के सर्वाधिक रन भी हैं।
- बड़े टूर्नामेंटों में लगातार रन बनाने और रिकॉर्ड अपने नाम करने की कोहली की क्षमता उनके लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर की खास पहचान रही है। तिरुवनंतपुरम की पारी ने इस रिकॉर्ड यात्रा में एक और बड़ा अध्याय जोड़ दिया।

कैंब्रिज : एक यात्रा जिसने नेतृत्व को नए अर्थ दिए

कैं ब्रिज की धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे इतिहास, ज्ञान और भविष्य एक ही जगह संवाद कर रहे हों। सदियों पुरानी इमारतों, शांत गलियों और अकादमिक वातावरण के बीच चलते हुए यह एहसास लगातार बना रहा कि यह केवल एक विश्वविद्यालयी शहर नहीं, बल्कि विचारों की एक जीवंत परंपरा है। इसी वातावरण में लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।

कैंब्रिज की इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यहां मिले लोग और उनके विचार रहे। अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और पेशेवर पृष्ठभूमियों से आए प्रतिभागियों के साथ संवाद ने यह समझने का अवसर दिया कि दुनिया को देखने के तरीके भले अलग हों, लेकिन सीखने और बेहतर भविष्य बनाने की आकांक्षा सबको जोड़ती है।

इन संवादों के बीच नेतृत्व को लेकर मेरी अपनी समझ भी बदली। मैंने महसूस किया कि नेतृत्व केवल निर्णय लेने, आदेश देने या किसी पद की शक्ति का उपयोग करने का नाम नहीं है। सच्चा नेतृत्व वह है, जिसमें व्यक्ति लोगों को सुनता है, उनकी क्षमताओं पर विश्वास करता है और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ता है। एक लीडर की सफलता इस बात में भी है कि उसके साथ चलने वाले लोग स्वयं को कितना सक्षम और सशक्त महसूस करते हैं।

कैंब्रिज ने मुझे यह भी सिखाया कि चुनौतियां विकास का अवसर होती हैं। किसी समस्या के सामने रुक जाने के बजाय उसके भीतर छिपे नए विचार और संभावनाओं को तलाशना ही नवाचार की शुरुआत है। निरंतर सीखना, प्रश्न पूछना, नई दृष्टि को स्वीकार करना और बदलते समय के साथ स्वयं को विकसित करना, यही आधुनिक नेतृत्व की वास्तविक पहचान है।

इस सीख को मैं अपने संस्थानों तक ले जाना चाहता हूं। 140 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाले सर प्रताप स्कूल, सर प्रताप कॉलेज (आर्ट्स) और सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर के नेतृत्वकर्ता के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक न ले जाए, बल्कि उन्हें नेतृत्व, आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए तैयार करे।

कैंब्रिज से लौटते हुए मेरे साथ यहां की स्मृतियों के साथ एक नई दृष्टि भी थी—शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि संभावनाओं को जगाना है; और नेतृत्व का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना है।

शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है, **“सच्चा नेतृत्व दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ाने में है।”**



गिरीश माथुर
संस्थापक अध्यक्ष

सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर
सर प्रताप स्कूल
सर प्रताप कॉलेज (आर्ट्स)



जय हिंद | जय राजस्थान | जय भाजपा, विजय भाजपा



भाजपा का परचम, विकास का संकल्प! जैतारण नगर पालिका में फिर से भाजपा का ऐतिहासिक बोर्ड

कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी
के नेतृत्व में प्रचंड जीत



राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जैतारण विधायक श्री अविनाश जी गहलोत की दूरदर्शी सोच, अथक परिश्रम और घर-घर जनसंपर्क का ही परिणाम है कि राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण नगर पालिका की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपना अटूट विश्वास जताया है।

25 वार्डों वाली जैतारण नगर पालिका में 19 वार्डों पर ऐतिहासिक विजय दर्ज कर भाजपा ने अपना परचम लहराया है।

इस शानदार विजय के साथ ही जन-जन के प्रिय, अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता श्री भेणाराम जी गहलोत पुनः जैतारण नगर पालिका के अध्यक्ष (चेयरमैन) पद पर सुशोभित हुए हैं। स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली। चुनाव प्रचार के लिए पूरे जैतारण शहर में घर-घर घूमें। कैबिनेट मंत्री की ओर से करवाए गए विकास कार्य की बदौलत जनता ने दोबारा भाजपा में विश्वास जताया। नगर पालिका अध्यक्ष भेणाराम जी गहलोत ने इस जीत का श्रेय कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व जनता को दिया है। श्री भेणाराम जी गहलोत इस बार वार्ड संख्या 13 से दोबारा पार्षद निर्वाचित हुए।

व्यक्तित्व एवं जीवन परिचय
श्री भेणाराम जी गहलोत



जैतारण की माटी में जन्मे और हमेशा जनसेवा को समर्पित रहने वाले श्री भेणाराम जी गहलोत सादगी, निष्ठा, विश्वास और विकासपरख राजनीति के प्रतीक हैं।

- जन्म तिथि: 5 जनवरी 1959
- जन्म स्थान: जैतारण (ब्यावर, राजस्थान)
- पिता: पूज्य श्री छगाराम जी गहलोत
- माता: पूजनीय श्रीमती गोपुड़ी बाई

गौरवशाली राजनीतिक व सामाजिक सफर

विगत चार दशकों से अधिक समय से संगठन, समाज और जनता की सेवा में समर्पित श्री भेणाराम जी गहलोत का राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान अतुलनीय रहा है:

जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्य उपलब्धियाँ

1982: ग्राम सेवा सहकारी समिति, जैतारण के उपाध्यक्ष रहकर किसानों व ग्रामीणों के हित में कार्य किया।

1995: जैतारण नगर पालिका में प्रथम बार पार्षद निर्वाचित होकर जनसेवा की शुरुआत की।

2005 - 2010: जैतारण नगर पालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए।

2021 - 2026: पार्षद के रूप में जनता के बीच रहकर लगातार समस्याओं का समाधान किया।

वर्तमान: पुनः भारी बहुमत से अध्यक्ष, नगर पालिका (जैतारण) निर्वाचित।

श्री भेणाराम जी ने भाजपा संगठन में निभाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ

- दो बार भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष (जैतारण)
- जिला उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा
- जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी (संगठन)

सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व

अध्यक्ष: ज्योतिबा फुले संस्थान, जैतारण
उपाध्यक्ष: अखिल भारतीय माली सेवा संस्थान, पुष्कर
सचिव: राजस्थान माली महासभा

जनसेवा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता

नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भेणाराम जी गहलोत ने शहर में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं तथा आमजन से जुड़े विषयों पर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उनके सार्वजनिक जीवन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शहर में आवश्यक विकास कार्य, आमजन से जुड़े नागरिक मुद्दों पर कार्य, नगर पालिका की सुविधाओं को बेहतर बनाना, शहर में भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, बिना भेदभाव नागरिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर ध्यान देना, जैतारण के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना शामिल हैं।

समाजसेवा और जनसेवा से बढ़ रही बाबूलाल भाटी की लोकप्रियता

जैतारण नगर पालिका के वार्ड संख्या 5 की पार्षद श्रीमती कंचन देवी के पति बाबूलाल भाटी क्षेत्र में अपनी समाजसेवा, जनसेवा



और सरल व्यवहार के चलते लगातार लोगों के बीच पहचान बना रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद हो या वार्डवासियों की समस्याओं को लेकर सक्रियता—बाबूलाल भाटी हर समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर नजर आते हैं।

समाजसेवा के साथ-साथ बाबूलाल भाटी एक प्रतिष्ठित मोबाइल

व्यवसायी के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। खासकर युवाओं के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ और लोकप्रियता देखने को मिलती है।

वार्ड संख्या 5 में इस बार कंचन देवी ने पार्षद पद पर भारी मतों से विजय हासिल की, जिसे उनके समर्थक पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और क्षेत्रवासियों के साथ लगातार बने संपर्क का परिणाम बताते हैं। वार्डवासियों ने उनके पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों को याद करते हुए एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।

वहीं, पार्षद कंचन बाबूलाल भाटी का कहना है कि जनसेवा उनके लिए केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने का माध्यम है। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना और क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में उनके साथ खड़ा रहना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

वार्ड संख्या 5 में पुनः विकास की बयार

वार्ड संख्या 5 से लोकप्रिय एवं कर्मठ प्रत्याशी श्रीमती कंचन बाबूलाल भाटी ने भारी मतों से दोबारा पार्षद पद पर विजय प्राप्त की है। समाज सेवा एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री बाबूलाल जी भाटी (पार्षद प्रतिनिधि) एवं श्रीमती कंचन भाटी ने इस जीत का श्रेय कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और वार्ड की देवतुल्य जनता को दिया है।

अध्यक्ष का जनता के नाम संदेश

यह जीत जैतारण की देवतुल्य जनता की जीत है। हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत के कुशल मार्गदर्शन, मेहनत और विकासपरक सोच के कारण ही भाजपा का बोर्ड बना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैतारण शहर के प्रत्येक वार्ड में बिना किसी भेदभाव के भाईचारे और निष्पक्षता के साथ चौमुखी विकास कराया जाएगा।

—श्री भेणाराम जी गहलोत (अध्यक्ष, नगर पालिका जैतारण)



जैतारण नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनने एवं श्री भेणाराम जी गहलोत के अध्यक्ष बनने पर समस्त जैतारण निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत का हार्दिक आभार।

शुभेच्छु- कंचन बाबूलाल भाटी,
 पार्षद, वार्ड संख्या- 5 नगर पालिका, जैतारण

हरित कौशल, नए करियर



डॉ. त्रिलोक शर्मा

करियर विश्लेषक एवं प्रबंधन शिक्षाविद

दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से हरित हो रही है और इसका असर रोजगार पर भी दिख रहा है। हरित कौशल अब केवल पर्यावरण क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि वित्त, प्रबंधन, तकनीक और पारंपरिक पेशों की भी जरूरत बन रहे हैं।

कल्पना कीजिए, चार साल बाद दो विद्यार्थी एक ही डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। दोनों को लेखांकन, वित्तीय विश्लेषण और एक्सेल का ज्ञान है। लेकिन एक विद्यार्थी को ईएसजी, कार्बन लेखांकन, सततता रिपोर्टिंग, जलवायु जोखिम और हरित वित्त की भी समझ है।

सवाल है, क्या दोनों के लिए रोजगार के अवसर एक जैसे होंगे? यह सवाल आने वाले रोजगार बाजार की बड़ी सच्चाई की ओर संकेत करता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल दिशा में बढ़ रही है और इसके साथ नौकरियों की प्रकृति भी बदल रही है। इसका अर्थ केवल सौर ऊर्जा अभियंताओं या पर्यावरण वैज्ञानिकों की मांग बढ़ना नहीं है। असली बदलाव यह है कि लगभग हर पेशे में नए हरित कौशल जुड़ रहे हैं।

हरित करियर का बदलता अर्थ

‘हरित करियर’ सुनते ही सौर ऊर्जा तकनीशियन, पर्यावरण वैज्ञानिक या वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ की तस्वीर सामने आती है। लेकिन पारंपरिक नौकरियां भी अब ‘हरित’ होती जा रही हैं। एक लेखाकार को कार्बन उत्सर्जन की गणना और रिपोर्टिंग समझनी पड़ सकती है। बैंकिंग में किसी परियोजना से जुड़े जलवायु जोखिम का आकलन महत्वपूर्ण हो सकता है। निवेश विश्लेषक किसी कंपनी को उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर भी देख सकता है।

यानी भविष्य का हरित करियर केवल पर्यावरण विज्ञान पढ़ने वालों के लिए नहीं है। वाणिज्य, प्रबंधन, अभियंत्रण, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, आंकड़ा विश्लेषण, विपणन और वित्त, हर क्षेत्र में हरित कौशल की भूमिका बढ़ रही है।



डिग्री के साथ जोड़ें हरित कौशल

वाणिज्य या प्रबंधन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी पूरी पढ़ाई बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें मौजूदा शिक्षा में एक नई परत जोड़नी है। ईएसजी विश्लेषण, सततता रिपोर्टिंग, कार्बन लेखांकन, हरित वित्त, जलवायु जोखिम और सतत खरीद जैसे क्षेत्र नए अवसर खोल सकते हैं।

सरल सूत्र में ऐसे समझा जा सकता है:

डिग्री + हरित ज्ञान + डिजिटल कौशल + काम का प्रमाण = हरित करियर की तैयारी केवल प्रमाण-पत्रों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और उसे कहां इस्तेमाल किया।

शुरुआत आज से

हरित करियर की तैयारी के लिए चार साल का इंतजार जरूरी नहीं है। अगले 30 दिन भी शुरुआत के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहले सप्ताह में ईएसजी, कार्बन, सतत विकास लक्ष्य और चक्रीय अर्थव्यवस्था समझें। दूसरे सप्ताह में किसी कंपनी की सततता रिपोर्ट पढ़ें। तीसरे सप्ताह में आईएफआरएस एस1 और एस2 जैसे मानकों की जानकारी लें। चौथे सप्ताह में सीखी बातों के आधार पर दो-तीन पृष्ठ का छोटा सततता विश्लेषण तैयार करें।

तीस दिनों में कोई विशेषज्ञ नहीं बनेगा, लेकिन ‘हरित करियर के बारे में सुना है’ से आगे बढ़कर ‘मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है’ तक जरूर पहुंचा जा सकता है।

विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि चार साल बाद सबसे अच्छा करियर कौन-सा होगा। इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पानी, कचरा, संसाधन दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, आपूर्ति शृंखला, जोखिम प्रबंधन और सतत विकास ऐसी ही चुनौतियां हैं। इनसे जुड़े कामों में अलग-अलग विषयों की विशेषज्ञता की जरूरत होगी।

आज के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ‘कल की महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए मैं आज कौन-सी क्षमताएं विकसित कर सकता हूँ?’ भविष्य की नौकरी का इंतजार करने की बजाय भविष्य की जरूरतों के लिए खुद को तैयार करना ही आज के विद्यार्थी की सबसे उपयोगी तैयारी हो सकती है।

आंकड़े बदलाव की कहानी बताते हैं

लिंगडइन की Global Green Skills Report 2025 के अनुसार, हरित कौशल की मांग उनकी उपलब्धता की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ रही है। आधे से अधिक हरित नियुक्तियां ऐसी पारंपरिक भूमिकाओं में हो रही हैं, जिन्हें अब तक सीधे पर्यावरण से नहीं जोड़ा जाता था। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 2024 में दुनिया भर में 1.66 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा था। भारत में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और सत्त्व कंसल्टिंग के अध्ययन में 2047 तक भारत में लगभग 3.5 करोड़ हरित रोजगारों की संभावना जताई गई है।

भारत में बढ़ते अवसर

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत वाहन, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा दक्षता से जुड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ रही हैं। दिसंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 513 गीगावाट से अधिक हो चुकी थी और गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 51.93 प्रतिशत पहुंच गई थी। राजस्थान और गुजरात सौर ऊर्जा के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान का भड़ला, मध्य प्रदेश का रीवा और गुजरात का कच्छ उस आर्थिक बदलाव के प्रतीक हैं जिसमें ऊर्जा, तकनीक, वित्त, आंकड़े और मानव संसाधन एक साथ जुड़ते हैं। एक बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को इंजीनियरों के साथ वित्त विशेषज्ञ, आंकड़ा विश्लेषक और अन्य पेशेवर भी चाहिए होते हैं।

अनुवाद करना परकाया प्रवेश करना है

अनुवाद केवल शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंचाना नहीं, बल्कि रचनाकार की भावभूमि, संवेदना और संस्कृति को समझने की प्रक्रिया है। सच्चा अनुवाद तभी संभव है, जब अनुवादक मूल रचना में उतरकर उसकी आत्मा को नई भाषा में जीवंत कर सके।



दिनेश सिंदल,

कवि, लेखक

प के पास भागों का एक गुच्छा है। उसे आप पहन नहीं सकते। किंतु अगर इन भागों को तरतीब दे दी जाए तो वह कपड़ा बन जाएगा। अब उसे आप पहन सकते हैं। उसे ओढ़ सकते हैं। यह तरतीब देना कविता है। भाषा (शब्द) धागे हैं। कविता में भाषा का इतना ही काम है।

भाषा कविता का उपकरण है। जैसे चित्रकार के लिए रंग और तुलिका। संगीतकार के लिए स्वर, वाद्ययंत्र, वैसे ही कवि के लिए भाषा। उपकरण अपने आप में कला नहीं है। इसी तरह सिर्फ भाषा से कविता नहीं होती। कविता का जन्म कवि की संवेदना, अनुभव, कल्पना, दृष्टि और सृजनात्मकता से होता है। भाषा उन सबको रूप देने का माध्यम है। भाषा एक दूल है। आप अपने दूल को कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं यह आपका कौशल है।

कविता में शब्द इशारे होते हैं। वे हमें वह दिखाने का प्रयास करते हैं जो हमारा सत्य है। जो हमारा साध्य है। भाषा साध्य नहीं, साधन है। साध्य तो वह है, जिसे हम कह नहीं पा रहे। कविता की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि हमें वह कहना होता है जो साधारण भाषा में कहा नहीं जा सकता। कविता उस अनुभव को भाषा देने का प्रयास है, जिसे साधारण भाषा पूरी तरह कह नहीं पाती। या कविता वह कहने की कोशिश है जिसे केवल शब्दों में कह देना संभव नहीं। यह भी सच है कि कविता भाषा से ही बनती है। किंतु कवि भाषा की व्यक्त करने की सीमा को पार करता है। उसका अतिक्रमण करता है। वह शब्दों को नए अर्थ प्रदान करता है। एक शब्द है 'साफ'। इसके प्रयोग देखें- साफ-साफ कहो, अपने कमरे को साफ रखो, मेरा हिसाब साफ कर लो। सभी जगह 'साफ' अलग-अलग अर्थ दे रहा है।

एक और उदाहरण देखें। शब्द है 'खराब'। इसके प्रयोग देखें- बुखार से मुंह का स्वाद खराब हो गया। समय खराब चल रहा है। कीचड़ से मेरे कपड़े खराब हो गए। यहां खराब सभी जगह अलग-अलग अर्थ दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि कवि के लिए शब्द शब्दकोश से नहीं आते। वे उसके अनुभव से आते हैं। इस तरह के कई शब्द, कई भाषाई मुहावरे आपको मिल जाएंगे।

शब्द एक दिन में नहीं बनते। वे समाज के लंबे अनुभव, उच्चारण, जरूरत और प्रयोग से धीरे-धीरे प्रचलित होते हैं, आकार लेते हैं। फिर वे शब्दकोश में आते हैं।

भाषा में समय के साथ-साथ शब्द जुड़ते रहते हैं। घिसते रहते हैं। मिटते रहते हैं। वे जनता के बीच पैदा होते हैं। पलते हैं, जीते हैं और फिर शब्दकोश में स्वीकृत कर लिए जाते हैं। शब्द पहले आमजन में स्वीकृत होता है, फिर शब्दकोश में आता है।

मित्रों, मुझे एक खेल याद आता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कान में कुछ कहता है। दूसरा तीसरे के कान में उसे दोहराता है। तीसरा चौथे के... चौथा पांचवें के... इस तरह वह बात आगे बढ़ती है। जब अंतिम व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने क्या सुना तो वह बात बिल्कुल बदल चुकी होती है।

यह बात साहित्य अकादमियों द्वारा करवाए जा रहे अनुवादों पर खरी उतरती है। अकादमियों द्वारा अनुवाद के लिए पुस्तकें कभी-कभी ऐसे रचनाकारों को भी दे दी जाती हैं जिनका उस कृत की मूल भाषा से कोई लेना-देना नहीं होता। अतः मूल कृत का लेखक किसी अन्य व्यक्ति से उस कृत का हिंदी या अंग्रेजी में (लिप्यांतर) करवाता है, फिर वह अनुवादक उस लिप्यांतर से अपनी भाषा में उसका अनुवाद करता है। अतः ये अनुवाद नहीं होकर अनुवाद का अनुवाद हो गया।

जब हम किसी साहित्यिक कृत का उसकी मूल भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद करते हैं तो वह मात्र लिप्यांतर नहीं होता। क्योंकि शब्द केवल अर्थ बताने का साधन नहीं है, बल्कि वह भाव, ध्वनि, चित्र और संवेदना भी पैदा करता है। किसी कविता के भावानुवाद के लिए अनुवादक को पहले कविता के भाव तक पहुंचना होता है। यह तभी संभव है जब मूल कविता के कवि ने जिस भावभूमि में बैठकर रचा है, उसी भावभूमि में पहुंचा जाए। उसके भाव को समझना और उस भाव को दूसरी भाषा के शब्दों का जामा पहनाना। यह परकाया प्रवेश करने जैसा कार्य है।

इसलिए कविता का अनुवाद आसान नहीं होता। क्योंकि कविता के भाव पक्ष के साथ-साथ उसकी एक आंतरिक लय भी है। उसका निर्वाह भी करना होता है। इस लय के साथ मूल रचनाकार के भाव को बचाना और उसे लक्ष्य भाषा में प्रकट करना। यह श्रमसाध्य कार्य तो है ही, उच्च प्रतिभा व विषय की गहरी समझ भी मांगता है।

कई बार अनुवादक को मूल रचनाकार से भी अधिक श्रम करना पड़ता है।

हम जानते हैं कि भाषा में ही संस्कृति बची रहती है।

अतः अनुवादक दो भाषाओं को ही नहीं, दो संस्कृतियों को भी जोड़ रहा होता है। अनुवादक को दोनों भाषाओं के शब्द-संस्कारों से परिचित होना चाहिए। वह रचनाकार की आवाज को एक नई भाषा में जीवन देता है। उसकी सोच को नई भाषा में प्रतिष्ठा देता है।

अनुवादक को स्रोत भाषा (जिससे अनुवाद होना है) एवं लक्ष्य भाषा (जिसमें अनुवाद होना है) दोनों की शब्दावली, व्याकरण, मुहावरे और लहजे की समझ होनी चाहिए, अन्यथा वह रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

भाषा के साथ संस्कृति भी जुड़ी रहती है। अतः अनुवादक को दोनों भाषाओं की संस्कृतियों की समझ होनी चाहिए। परंपरा, प्रतीक और संदर्भ समझने की क्षमता तभी उसमें होगी, जब वह दोनों भाषाओं की संस्कृतियों को समझ रहा होगा।

अनुवादक को संवेदनशील और सृजनात्मक भी होना चाहिए। जहां तक कविता का सवाल है, उसकी आत्मा को वह तभी पकड़ पाएगा जब वह संवेदनशील और सृजनशील है।

अनुवाद की भाषा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अनुवाद पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगे कि जैसे वह मूल स्वाभाविक रचना पढ़ रहा है।

अनुवादक रचना पर अपनी राय नहीं थोपता, अपना मत जाहिर नहीं करता। वह मूल रचना का आशय जस का तस अन्य भाषा में पहुंचाता है।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी चीज को मैं उतना ही देख पाऊंगा जितनी मेरी देखने की क्षमता है। जैसे कोई पेड़ मुझे हरा दिख रहा है तो इसका हरापन मेरी आंख के रेटिना की क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरे व्यक्ति को वह वैसा हरा नहीं दिखेगा जैसा मुझे दिख रहा है। उसे अपनी आंख के रेटिना की क्षमता के अनुसार हरा दिखेगा।

अतः किसी रचना को मैं अपने अनुभव, अपनी क्षमता, अपनी संवेदना के स्तर तक महसूस करता हूं तो उसके रूपांतरण में कहीं न कहीं मेरा होना शामिल हो जाता है।



अंत में... उमर खय्याम की रुबाइयों का अंग्रेजी में एडवर्ड फिट्जजेराल्ड द्वारा किया गया अनुवाद इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिट्जजेराल्ड ने 1859 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया। यह अनुवाद विवादास्पद रहा। अनेक रुबाइयों को बदलकर, जोड़कर अपनी विक्टोरियन संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया। मूल फारसी में जहां सूफियाना संकेत है, दार्शनिक गहराई है और कई स्तरों वाले अर्थ हैं वहीं फिट्जजेराल्ड के अनुवाद में जीवन क्षणभंगुरता, मदिरा प्रेम और वर्तमान क्षण को जीने की भावना अधिक मुखर हो जाती है। उन्होंने खय्याम को कहीं-कहीं भोगवादी की तरह प्रस्तुत किया है, जबकि मूल में आध्यात्मिक व दार्शनिक परतें कहीं अधिक जटिल हैं।

उमर खय्याम कबीर व फरीद की परंपरा के सूफी संत थे। अतः जब हम अनुवाद करते हैं तो रचनाकार की पृष्ठभूमि की जानकारी भी हमें होनी चाहिए।

राजस्थान में गूंजती बंगाल की धुन

राजस्थान में बसे बंगाली परिवारों के लिए दुर्गा पूजा आस्था के साथ अपनी भाषा, परंपरा और जड़ों से जुड़ने का अवसर है। पंडाल, ढाक, धुनुची और सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ते हैं।



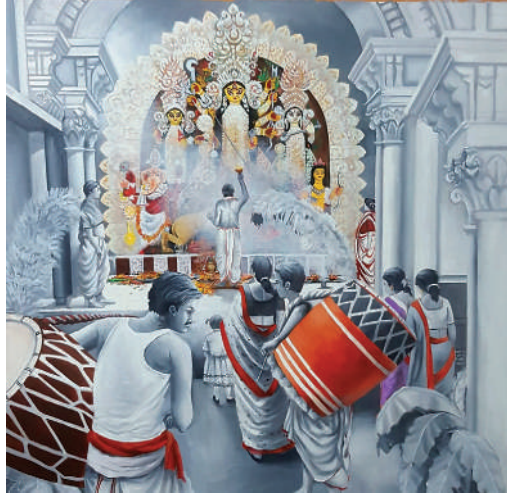
डॉ. मधु बैनर्जी,
वरिष्ठ पत्रकार

सि तंबर-अक्टूबर की हवा में जब हल्की ठंडक घुलने लगती है, तब राजस्थान के कई शहरों में एक अलग ही रंग दिखाई देने लगता है। कहीं पंडाल सजने लगते हैं, कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है, तो कहीं बंगाली परिवार खरीदारी और तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ दिनों के लिए राजस्थान की धरती पर बंगाल की संस्कृति जैसे उतर आती है। ढाक की आवाज, धुनुची की धुन, शंखनाद, लाल-पाड़ साड़ी और मां दुर्गा के जयकारे माहौल को पूरी तरह बदल देते हैं।

यह सिर्फ पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा बंगाली समाज के लिए अपने घर, अपनी भाषा, अपनी स्मृतियों और अपनी जड़ों तक लौटने का बहाना है। राजस्थान में रहने वाला बंगाली समाज भले ही वर्षों पहले रोजगार, नौकरी, शिक्षा या व्यवसाय के सिलसिले में यहां आया हो, लेकिन दुर्गा पूजा आते ही उसके भीतर का बंगाल जाग उठता है। जो लोग साल भर हिंदी, अंग्रेजी या राजस्थानी में बातचीत करते हैं, वे इन दिनों बंगाली में ज्यादा सहज नजर आते हैं। बच्चे, जो शायद बंगाल की गलियों को सिर्फ तस्वीरों में जानते हैं, पंडाल और पूजा के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होते हैं।

घर से दूर, लेकिन बंगाल से दूर नहीं... राजस्थान और बंगाल की भौगोलिक दूरी भले ही हजारों किलोमीटर हो, लेकिन दुर्गा पूजा इस दूरी को कुछ दिनों के लिए मिटा देती है। बंगाली परिवारों के लिए ये पांच दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों के नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप के भी होते हैं। पूजा पंडाल में पहुंचते ही पुराने परिचित मिल जाते हैं। किसी का परिवार कोलकाता में है तो कोई वर्षों से राजस्थान में रह रहा है। कोई पहली बार पूजा में आया है तो कोई बचपन से इसी परंपरा का हिस्सा है।

बातचीत में पुरानी यादें लौटती हैं। कोलकाता की



प्रतिमा में सिर्फ मां नहीं, कलाकार की पहचान भी

दुर्गा पूजा की तैयारी प्रतिमा के पंडाल में पहुंचने से काफी पहले शुरू हो जाती है। प्रतिमा निर्माण की परंपरा बंगाली संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिट्टी से देवी की प्रतिमा तैयार करने से लेकर रंग-रोगन और आभूषणों तक, हर चरण में कलाकार की मेहनत दिखाई देती है।

राजस्थान में रहने वाले बंगाली समाज के सामने चुनौती यह भी है कि यहां पूजा की तैयारियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करनी पड़ती हैं। कई बार प्रतिमा और पूजा सामग्री दूसरे शहरों या राज्यों से मंगाई जाती है। इसके बावजूद कोशिश रहती है कि पूजा की मूल परंपराओं और स्वरूप में ज्यादा बदलाव न हो।

दुर्गा पूजा के सबसे आकर्षक दृश्यों में धुनुची नृत्य और सिंदूर खेला शामिल हैं। धुनुची में धूप से भरे पात्र के साथ श्रद्धालु ताल पर नृत्य करते हैं। ढाक की थाप और धुनुची के धुएं से वातावरण में अलग ही ऊर्जा भर जाती है। वहीं विजयादशमी पर होने वाला सिंदूर खेला बंगाली समाज की विशेष परंपरा है। महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि महिलाओं के आपसी स्नेह और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक भी बन जाता है। लाल किनारी वाली सफेद साड़ियों में महिलाएं और पारंपरिक परिधान में पुरुष इस उत्सव को एक विशिष्ट बंगाली पहचान देते हैं।

पूजा, कॉलेज स्ट्रीट की भीड़, पंडालों की रोशनी, अल्बर्ट हॉल की सजावट और शांति, हावड़ा ब्रिज का नजारा, कालीघाट पर गूंजती शंख की ध्वनि, बेलूर मठ की संध्या आरती और घर की बनी मिठाइयां। पूजा के बाद दोस्तों के साथ घूमने की यादें भी ताजा हो जाती हैं। यही वजह है कि राजस्थान में होने वाली दुर्गा पूजा बंगाली समाज के लिए धार्मिक आयोजन से ज्यादा सामुदायिक पहचान का उत्सव बन जाती है।

नई पीढ़ी के लिए संस्कृति की पाठशाला

- राजस्थान में जन्मी बंगाली समाज की नई पीढ़ी के लिए दुर्गा पूजा का अर्थ थोड़ा अलग है। कई बच्चे और युवा बंगाल में लंबे समय तक नहीं रहे। उनके लिए कोलकाता, दुर्गा पूजा और बंगाली संस्कृति की कहानियां परिवार से मिली स्मृतियां हैं।
- ऐसे में पूजा पंडाल उनके लिए सांस्कृतिक पाठशाला बन जाता है। यहां वे बंगाली गीत सुनते हैं, नृत्य करते हैं, पारंपरिक भोजन चखते हैं और परिवार के बुजुर्गों से अपनी संस्कृति के बारे में सुनते हैं। कई पूजा समितियां बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, नृत्य, संगीत और बंगाली भाषा से जुड़े आयोजन भी करती हैं। इससे त्योहार केवल अगली पीढ़ी तक पहुंचता ही नहीं, बल्कि उसके अर्थ भी समझाए जाते हैं।

राजस्थान की मिट्टी में बंगाल का उत्सव

- राजस्थान में दुर्गा पूजा का एक खूबसूरत पक्ष यह भी है कि यहां बंगाली परंपरा स्थानीय समाज से जुड़ती जा रही है। पूजा में केवल बंगाली परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे समुदायों के लोग भी शामिल होते हैं। राजस्थान की मेहमाननवाजी और बंगाल की सांस्कृतिक आत्मीयता मिलकर एक नया सामाजिक रंग बनाती है।
- पंडालों में बंगाली व्यंजनों की खुशबू के साथ राजस्थान के स्वाद भी दिखाई देने लगे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बंगाली गीतों के साथ हिंदी और स्थानीय भाषाओं के गीत भी जगह बना रहे हैं। यानी उत्सव अपनी मूल पहचान को बचाए रखते हुए उस शहर की संस्कृति का भी हिस्सा बन रहा है, जहां वह आयोजित हो रहा है।

बाबा की बीज व गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

मॉडर्न एजुकेशन सोसायटी, जोधपुर

के चुनाव में **भारी मतों से विजयी** होने पर

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

संरक्षक मंडल



इंद्र कुमार टहल्यानी



गंगाराम लालवानी



रामचन्द्र गिदवानी



नानक राम वाधवानी



चन्दु रामचंदानी



मुरली गंगवानी
अध्यक्ष



नरेन्द्र बुधवानी
महासचिव



रमेश रामनानी
उपाध्यक्ष



मदन आईदासानी
कोषाध्यक्ष



हरीश देवनानी
सह सचिव



वासुदेव स्वराजानी
कार्यकारिणी सदस्य



राजकुमार चावला
कार्यकारिणी सदस्य



हेमन्त रोचवानी
कार्यकारिणी सदस्य



राजेश गिदवानी
कार्यकारिणी सदस्य



लखपत धनकानी
कार्यकारिणी सदस्य



दीपक मोरदानी
कार्यकारिणी सदस्य

शुभेच्छु : सुनील तलवार, राहुल पाराशर, के.के.पित्ति, खुशाल अयानी, महिपाल सिंह उज्ज्वल, प्रवीण भंसाली, ईशान तलवार, निर्मल भंडारी, एन.के.श्रीमाली, प्रलयंकर जोशी, अक्षित तलवार, हरीश संचेती, सुयोग काबरा, प्रभुदयाल गंगवानी, मनीष मेहता, राजू भंसाली, रुचित तलवार, प्रवीण कुमार छाजेड़, बिक्रमजीत सिंह बख्शी।

जगदेव सिंह खालसा, हरजीत सिंह भूटानी, दर्शन सिंह लोटे, कुलदीप सिंह सलूजा, जीतेन्द्र बत्रा, मंजीत सिंह छाबड़ा



विपुल डोवाल, ज्योतिष, पीठाधीश्वर।
श्री शनिधाम आश्रम, विकासनगर देहरादून
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

अक्टूबर 2026 में मेष, मिथुन, कर्क व तुला राशि वालों के लिए यह समय प्रभावशाली है। बाकी राशियों के लिए भी समय बुरा नहीं है, बस धैर्य, संयम और सही निर्णय की जरूरत रहेगी।



मेघ

अक्टूबर का महीना आपके लिए कार्य क्षेत्र में सक्रियता और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापार में नई योजना बन सकती है और पुराने संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परिवार में किसी सदस्य के कारण प्रसन्नता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को तुल देने से बचें। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अधिक सकारात्मक रहेगा।



वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर धन, परिवार और स्थिरता का महीना बन सकता है। आर्थिक मामलों में पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है। यदि किसी निवेश या संपत्ति से संबंधित योजना पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें और सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। परिवार में किसी शुभ समाचार से वातावरण प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। महीने के मध्य में कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खान-पान में लापरवाही से बचना उचित होगा।



मिथुन

यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए नई योजनाओं के विस्तार का रहेगा। आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क भविष्य में लाभ दे सकता है। व्यापार में नई दिशा तलाशने वालों के लिए समय उपयोगी है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में गुलतफहमी को बातचीत के माध्यम से दूर करें। महीने के अंतिम सप्ताह में कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है।



कर्क

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना भावनात्मक संतुलन और कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत दे रहा है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा से संबंधित कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कार्यभार बढ़ सकता है। व्यापारियों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। परिवार में वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में पेट और पाचन संबंधी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। इस महीने धैर्य आपके लिए सबसे बड़ा सहायक रहेगा।



सिंह

सिंह राशि के लिए अक्टूबर आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का महीना हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में बड़े निर्णय सोच-समझकर लें। किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात सुखद रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना लाभकारी होगा। महीने का अंतिम भाग विशेष रूप से सक्रिय रहेगा।



कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह महीना मेहनत के परिणाम मिलने का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी की संभावना है। व्यापार में हिसाब-किताब और कागजी कार्यवाही को लेकर विशेष सावधानी रखें। धन संबंधी स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। किसी संपत्ति अथवा वाहन से जुड़ा निर्णय सामने आ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या आवश्यकता को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां संभल जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें।



तुला

तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना संबंधों, साझेदारी और आर्थिक अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार में साझेदारी करने वालों को स्पष्ट समझौते के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है। दांपत्य जीवन में अहंकार से बचना होगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी तनाव को हावी न होने दें। महीने के मध्य के बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल दिखाई देती हैं।



वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर परिवर्तन और महत्वपूर्ण निर्णयों का महीना है। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को विकल्प मिल सकते हैं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी और आपको अपनी रणनीति मजबूत रखनी होगी। परिवार में किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता आवश्यक है। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और थकान से बचें। महीने का अंतिम सप्ताह किसी महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत दे रहा है।



धनु

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर भाग्य, यात्रा और उन्नति का संदेश लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापारियों को दूर स्थान से लाभ अथवा नया संपर्क मिल सकता है। विदेश या दूर की यात्रा की योजना बन सकती है। विलासिता पर अत्यधिक खर्च से बचें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समय उपयोगी रहेगा। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य की कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से उत्साहवर्धक रहेगा।



मकर

मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर जिम्मेदारियों के साथ उपलब्धियों का महीना रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना लाभकारी होगा। व्यापार में धीरे-धीरे विस्तार की संभावना है। संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दांपत्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर, घुटनों या थकान संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें। धैर्य और निरंतरता इस महीने सफलता की कुंजी रहेगी।



कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर नई सोच, नए संपर्क और नए अवसरों का महीना हो सकता है। नौकरी में आपकी रचनात्मकता का लाभ मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी से भविष्य में उन्नति का रास्ता खुल सकता है। व्यापार में तकनीक और नए माध्यमों का प्रयोग लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन एक साथ कई जगह धन लगाने से बचें। मित्रों से लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। अंतिम दिनों में कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है।



मीन

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। नौकरी में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। यदि आप लंबे समय से किसी पद या अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखें। महीने का उत्तरार्ध संतोष व सकारात्मक ऊर्जा देने वाला रहेगा।

स्वाद वो जो बना दे बात
मनभाती महक, लाजवाब स्वाद, भरपूर पौष्टिकता

सोना सिक्का®



महंगा है पर
खरा है!
स्वाद और सेहत
से भरा है !

42 वर्षों से शुद्धता के हर
मापदंड पर खरा उतरा है,
इसलिए बेस्ट है सोना सिक्का

सोना सिक्का रखता है ख्याल आपकी सेहत का आपके परिवार की खुशियों का इसलिए सोना सिक्का तेल
के निर्माण में गुणवत्ता शुद्धता और सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाता है।

परिवार की सेहत के लिए सोना सिक्का में व्यंजन बनायें, खुद खायें, सबको खिलायें....!

मिलते-जुलते नाम और अशुद्ध ब्रांड से सावधान. आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं

Shyam and Shyam Oils Pvt. Ltd. Jodhpur

Plot No. B 5,6,7 (A), 1st Phase, Basni Industrial Area, Jodhpur, (Raj.)

डिस्ट्रीब्यूटर बनने एवं डीलरशिप हेतु
टोल फ्री नं. पर सम्पर्क करें: 1800 313 3292

sonasikka.com | info@sonasikka.com | sonasikka

0291-2512333, 2512338

Available on: amazon | Flipkart

SHAKUN



भारतीय जनता पार्टी



भारतीय जनता पार्टी

श्री प्रसन्न चंद मेहता
को जोधपुर नगर निगम के
महापौर बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

**आपका अपना
अमित भण्डारी
(जॉनी)**

नाकोड़ा साड़ी & N.S. GROUP

सौरभ, गौरव एवं समस्त भण्डारी परिवार व स्टाफगण।

सिरेउमराव मार्केट, श्याम मार्केट, त्रिपोलिया बाजार मोती चौक, जोधपुर